जबलपुर शनिवार 13 जून 2026 > शक संवत 1948, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी/चतुर्दशी व्रत

वर्ष 31 अंक 344 मूल्य ₹ 3.00 > पेज 12 > आर.एन.आई. पंजीयन नम्बर 64561/96

www.swatantramat.com

अब हर रोज दर्पण ⏩ 3

स्वतंत्र मत

स्वतंत्र मत में विज्ञापन देने के लिए 9589920250 पर कॉल करें * स्वतंत्र मत का अंक प्राप्त करने के लिए 9301359695 पर कॉल करें।

मौसम
अधिकतम तापमान 40.6°C
न्यूनतम तापमान 25.5°C
सूर्योदय -5.24 | सूर्यास्त - 6.57

जिले में सीबीआई की छापामार कार्यवाही, बैंक ⏩ 2

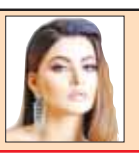

उर्वशी रौतेला को चाहिए संस्कारी लड़का ⏩ 7

साहित्य के क्षेत्र में सुयश त्यागी को मिला अखिल ⏩ 8

पेट्रोल पंप पर एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा

कालाबाजारी रोकने औद्योगिक एवं खुदरा ग्राहकों के लिए नियंत्रण आदेश जारी

नई दिल्ली (वार्ता)। डीजल की खुदरा बिक्री में कई जिलों में भारी वृद्धि के बाद सरकार ने औद्योगिक तथा संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए आम पेट्रोल पंपों से इसकी खरीद पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, कालाबाजारी रोकने के लिए खुदरा ग्राहकों के लिए भी एक दिन में खरीद की अधिकतम सीमा 200 लीटर तय कर दी गयी है, और यह शर्त भी रखी गयी है कि वे इसकी पुन: बिक्री नहीं कर सकेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार देर रात नया नियंत्रण आदेश जारी किया। इसे फिलहाल 90 दिन के लिए लागू किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी वाहन या व्यक्ति को एक दिन में पेट्रोल पंप पर 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा। नये नियम से लंबी तथा मध्यम दूरी के माल परिवहन वाले ट्रकों पर असर पड़ने की संभावना है। पेट्रोल पंप डीलरों को आदेश दिया गया है कि वे डीजल की बिक्री केवल वाहनों के टैंक अथवा पेसो (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) से अनुमोदित कंटेनर में ही करेंगे। आदेश में फिलहाल पेट्रोल की खुदरा बिक्री की कोई सीमा तय नहीं की गयी है, लेकिन भविष्य में ऐसा करने की गुंजाइश रखी गयी है। साथ ही, डीजल के साथ इसकी भी जमाखोरी रोकने के लिए कार्रवाई का प्रावधान है। तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश में कहा गया है कि संस्थागत और प्रत्यक्ष अथवा औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहक खुदरा बिक्री केंद्र से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीदेंगे या नहीं मंगवायेंगे। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अपने उपभोक्ता पंप से ही करेंगे। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे आज के आदेश और अन्य लागू कानूनों के तहत पेट्रोल और डीजल से संबंधित जमाखोरी, कालाबाजारी, अनधिकृत रूप से उनकी खरीद, जिस उद्देश्य के लिए खरीदा गया है उससे अलग इस्तेमाल और अन्य अनाचारों के विरुद्ध कार्रवाई सहित सभी आवश्यक उपाय करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

रोजाना 500 करोड़ का नुकसान

सरकार ने कहा है कि संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ता भी उनके लिए निर्दिष्ट माध्यमों की बजाय सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों के आम पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में डीजल खरीद रहे थे। इससे आम उपभोक्ताओं के लिए सस्ते डीजल की उपलब्धता कम हो रही थी। साथ ही तेल विपणन कंपनियों पर भी भारी आर्थिक दबाव पड़ रहा था। पश्चिम एशिया संकट के बीच कम कीमत पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति से उन्हें रोजाना 500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

डीजल की बिक्री में भारी उछाल

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि एक साल पहले के मुकाबले इस साल मई में देश के 327 जिलों में सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों के खुदरा आउटलेट पर डीजल की बिक्री में 10 प्रतिशत उछाल दर्ज किया गया। इनमें से 80 जिले ऐसे हैं जहां बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गयी। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नये नियामक उपायों का उद्देश्य खुदरा ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।

12 करोड़ की ड्रग्स के साथ मॉडल हर्षा सनी गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मशहूर मॉडल और पिछले साल 'मिसेज केरल' पेजेंट की रनर-अप रहीं हर्षा सनी को कस्टम विभाग ने भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। 29 वर्षीय मॉडल हर्षा सनी बैंकॉक से मुंबई लौट रही थीं। एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने जब उनके सामान की जांच की, तो उनके ट्रॉली बैग से 12 वैक्यूम-सील्ड पैकेट बरामद हुए। जांच में पता चला कि इन पैकेटों में 'हाइड्रोपोनिक कैनबिस' (विदेशी गांजा) भरा हुआ था जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 11.82 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

सरकारी बिल्डिंग में आग 4 हजार ईवीएम जलीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से करीब 4 हजार ईवीएम जल गईं। ये मशीनें इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर इस्तेमाल की गई थीं। घटना के बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग से सवाल किए हैं। वहीं, कांग्रेस और आप ने भी सरकार से जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। बिल्डिंग में दक्षिण 24 परगना जिला परिषद समेत कई सरकारी दफ्तर हैं। आग पर पूरी तरह काबू पाने में करीब 24 घंटे लगे।

देश विरोधी गतिविधियों में शामिल एजेंट गिरफ्तार

भोपाल। भोपाल में एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड ने देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ने के संदेह में एक युवक को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद फराज के रूप में हुई है। एटीएस ने उसे शुक्रवार को सुबह भोपाल के काजी कैंप इलाके में नन्हें बी की मस्जिद के पास से पकड़ा है। आरोपी एक डॉक्टर के क्लीनिक पर काम करता था। प्रारंभिक जांच में एजेंसी को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपी की गतिविधियों की जांच की जा रही है।

मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली (वार्ता)

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द होने को चुनौती दी थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें यह छूट दी है कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर कर इस मामले को आगे बढ़ा सकती हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एस चांदूरकर की पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत इस चरण में न्यायिक हस्तक्षेप वर्जित है। यह टिप्पणी करते हुए कि इस चुनौती को वैधानिक चुनाव याचिका तंत्र के माध्यम से उठाया जा सकता है, पीठ ने रिट याचिका को विचारणीय न मानते हुए खारिज कर दिया। सुश्री नटराजन का नामांकन 9 जून को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने अपने हलफनामे में इस बात का खुलासा नहीं किया था कि तेलंगाना की एक अदालत में उनके खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की गयी थी। सुश्री नटराजन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कल ही परिणाम घोषित कर दिये, जिसमें अन्य उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। इसके चलते कल मेंशनिंग के समय उनके द्वारा व्यक्त की गयी आशंका सच साबित हुई। प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग ने मिलकर भाजपा को तीसरी राज्यसभा सीट दिलाने का रास्ता साफ किया है।

कोई जानकारी नहीं छिपाई: नटराजन

सुश्री नटराजन ने कहा कि यह कहा गया है कि मैंने राज्यसभा नामांकन के फॉर्म 26 में जानकारी छिपाई। फॉर्म 26 में जिन बातों का ब्यौरा मांगा जाता है उनमें मतदाता सूची में उम्मीदवार का क्रमांक, उम्मीदवार का फोन नंबर, ई-मेल आदि जानकारियां, पैन और इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी, संपत्ति और अन्य चीजों का विवरण, लेकिन वो बिंदु जिन पर ये सारी बातें शुरू हुईं, वो हैं उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण, उन मामलों का विवरण जिसमें उसे किसी दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। मैंने फॉर्म 26 में यही जानकारी दी कि मुझ पर ऐसा कुछ भी लागू नहीं है... क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है, जिसका अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया है। ऐसी जानकारी देने के लिए फॉर्म 26 में कोई कॉलम नहीं था, जिसमें कहा गया हो कि आपको निजी शिकायत की भी जानकारी देनी होगी। ये बिल्कुल साफ है- न फॉर्म में कोई कमी थी और न ही मांगी गई कोई जानकारी छिपाई गई। जो भी जानकारी मांगी गई, वो फॉर्म 26 के तहत दी गई।

भारतीय राजनीति में ये पहला मामला

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय राजनीति में ये पहला मामला है, जिसमें राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन निरस्त किया गया है और ये देश में चर्चा का विषय है। आज मध्य प्रदेश के हमारे विधायक यहां मौजूद हैं और निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां राज्यसभा चुनाव को लेकर जो उत्साह और एकजुटता थी, उससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मध्य प्रदेश में भाजपा का पूरा नेतृत्व भयभीत हो गया। यही कारण रहा कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में ऐसा अपराध कर दिया, जो सरपंच और जनपद के छोटे-छोटे चुनाव में किया जाता है।

निर्वाचन आयोग का रवैया पक्षपातपूर्ण

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बार-बार उच्चतम न्यायालय को गुमराह कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा किसी भी कीमत पर मध्यप्रदेश में तीसरी राज्यसभा सीट जीतना चाहती थी और निर्वाचन आयोग का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताते हुए इसे सीट चोरी का मामला करार दिया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उम्मीदवार के खिलाफ केवल एक शिकायत दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया था।

मप्र का क्रेडिट कार्ड आवेदन संग्रहण में देश में दूसरा स्थान

पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

भोपाल (स्वतंत्र मत)। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण एवं वित्तीय समावेशन के लिए प्रदेश में प्रयास निरंतर जारी हैं। योजना के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र संग्रहण में मध्यप्रदेश ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। प्रदेश में अब तक 10 हजार से अधिक क्रेडिट कार्ड आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं, जिनमें से बैंकों द्वारा 900 से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन कर 500 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना अंतर्गत क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें वे समस्त शहरी पथ विक्रेता पात्र होंगे, जिन्होंने अपने ऋण की द्वितीय किश्त का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान कर दिया है तथा वे तृतीय किश्त के लिए अर्हता रखते हैं। इसके अतिरिक्त, वे वेंडर्स भी इस सुविधा के पात्र होंगे जिन्होंने पूर्व में ही तृतीय किश्त का ऋण प्राप्त कर लिया है- उनका ऋण खाता वर्तमान में सक्रिय हो अथवा पूर्णत: जमा हो चुका हो। आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 21 से 65 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है। यह क्रेडिट कार्ड सुविधा तृतीय किश्त के ऋण के अतिरिक्त देय होगी, जिससे हितग्राही अपनी पात्रता एवं प्राथमिकता के आधार पर ऋण, क्रेडिट कार्ड अथवा दोनों सुविधाओं का संयुक्त लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वित्तीय नियमों के अनुरूप, आवेदक का किसी भी वित्तीय संस्था में कोई निष्पादित परिसंपत्ति खाता नहीं होना चाहिए, यद्यपि एसएमए-0 श्रेणी के खातों पर बैंकों द्वारा विचार किया जा सकेगा तथा इसके लिए न्यूनतम क्रेडिट ब्यूरो स्कोर की कोई बाध्यता नहीं होगी।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरा

भारतीय नाविकों की मौत पर सरकार की चुप्पी चिंताजनक

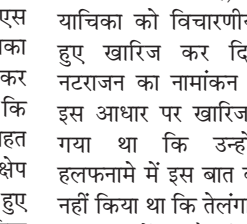

नई दिल्ली (वार्ता)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में तीन दिनों के भीतर तीन जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी हैरान करने वाली है और उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अन्तरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में तीन दिन में तीन जहाजों पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे 'कम्प्रोमाइज्ड पीएम' एक शब्द तक नहीं बोले। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है कि ये एक शब्द बोल जाएं। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में नरेन्द्र मोदी विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन जिन हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत हुई, उनके प्रति सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। उनका कहना था, अगले हफ्ते जी-7 में हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन तीन भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उन देशों को नाराज करने का साहस नहीं दिखा रहे हैं, जिनकी कार्रवाई में भारतीय नागरिकों की जान गई है। उन्होंने कहा, कम्प्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें न हिम्मत है और न ताकत। उन्होंने कहा कि जब किसी विदेशी शक्ति की कार्रवाई में भारतीय नागरिकों की जान जाती है तो प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए, लेकिन इस मामले में उनकी ओर से एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

आपके हथियारों से हम पर हमले हो रहे

यूरोप के दोहरे रवैये पर जयशंकर की खरी-खरी

हेलसिंकी। फिनलैंड दौरे पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूरोपीय देशों की दोहरी नीति की तीखी आलोचना की। एक पत्रकार द्वारा भारत पर रूस के प्रति अधिक सहानुभूति और रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाए जाने पर जयशंकर ने कड़ा जवाब दिया। 'कुलतारंता टॉक्स' में उभरती हुई ताकतें और नया भू-राजनीतिक मुकाबला विषय पर पैनल चर्चा के दौरान जयशंकर ने कहा कि यूरोप हथियार बेचता है जिनका इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है, फिर भी भारत की नीतियों पर उंगली उठाता है।

उन्होंने कहा, किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं किया गया। काश मैं भारत के संदर्भ में यूरोप के हथियारों के बारे में भी ऐसा कह पाता। जयशंकर ने आगे कहा, यूरोप हथियार बेचता है, जिनका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए किया जाता है। न केवल अभी, बल्कि कई वर्षों से। हम भारतीयों ने कभी भी यूरोप को खतरे में डालने वाला कोई काम नहीं किया है। विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का फैसला बाजार की कीमत और उपलब्धता के आधार पर लिया। उन्होंने बताया कि उस समय यूरोपीय देश मिडिल ईस्ट से तेल खरीद रहे थे, जबकि रूसी तेल बाजार में भरपूर मात्रा में उपलब्ध था।

जयशंकर ने कहा, मैं कीमत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदता हूं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका ने ही भारत से रूसी तेल खरीदने को कहा था ताकि वैश्विक तेल बाजार स्थिर रहे।

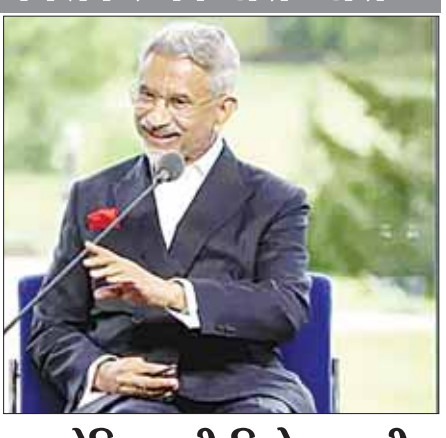

अमेरिका की विरोधाभासी नीति पर सवाल

जयशंकर ने अमेरिका की नीति की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाए गए, फिर प्रतिबंध हटा लिए गए। हमें यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि इसमें कोई बड़ा सिद्धांत शामिल है। इसे नैतिकता का मुद्दा बनाना सही नहीं है।

भारत लगातार यह साफ कर चुका है कि उसका ऊर्जा आयात राष्ट्रीय हित, नागरिकों के कल्याण और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। साथ ही, भारत यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता रहा है।

टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाओं के लिए नए दूरसंचार नियमों का मसौदा जारी

नई दिल्ली (वार्ता)। सरकार ने टेलीविजन, रेडियो और संबंधित प्रसारण सेवाओं से जुड़े दूरसंचार नियमों के मसौदे को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर लोगों से 27 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार द्वारा तैयार किए गए दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियम, 2026 का उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न दिशानिर्देशों को एकीकृत और सरल बनाना है। संसद ने 2023 में दूरसंचार अधिनियम पारित किया था, जिसने 1885 के पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लिया। नया अधिनियम दूरसंचार सेवाओं की व्यापक श्रृंखला को कवर करता है और विभिन्न सेवाओं के प्रशासन की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों को सौंपी गई है। टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध प्रसारण सेवाओं से जुड़े प्रावधानों का संचालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंत्रालय के अनुसार, नए नियमों का मसौदा टेलीविजन और रेडियो प्रसारण सेवाओं के लिए पूर्व में जारी विभिन्न नीतियों और दिशानिर्देशों को एक ही नियामक ढांचे में समाहित करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें सैटेलाइट टीवी चैनलों की अपलिंकिंग-डाउनलिंकिंग नीति, डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस संबंधी दिशा-निर्देश, हेडएंड-इन-द-स्काई सेवाएं, एफएम रेडियो प्रसारण, सामुदायिक रेडियो स्टेशन और आईपीटीवी सेवाओं से जुड़े नियम शामिल किए गए हैं। सरकार का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद प्रसारण उद्योग को एक एकीकृत और सरल नियमावली उपलब्ध होगी, जिससे कारोबार करने में सुगमता बढ़ेगी और वर्तमान व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं सुसंगत बनेगी। मंत्रालय ने सभी हितधारकों, प्रसारण संस्थानों और आम नागरिकों से मसौदा नियमों पर सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, ताकि अंतिम नियमों को अधिक प्रभावी और उद्योग-अनुकूल बनाया जा सके। इन मसौदा नियमों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक और अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है।

मौसम : दिनभर तपाया, शाम को भिगोया

तेज हवाओं ने भी झकझोरा, बरसात के बाद घूमने निकले लोग

जबलपुर (स्वतंत्र मत)।

संस्कारधानी जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से परेशान नागरिकों को आज आखिरकार बड़ी राहत मिल गई। मंगलवार के बाद सीधे शुक्रवार की शाम को मौसम ने करवट बदली और शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। अचानक हुए इस मौसम परिवर्तन से जहां एक ओर चिलचिलाती धूप और उमस से बेहाल लोगों के चेहरे खिल उठे, वहीं दूसरी ओर तेज आंधी-तूफान के कारण शहर में थोड़ा-बहुत नुकसान होने की भी खबर है। शुक्रवार की सुबह से ही शहर का मिजाज बेहद तल्ख था अधिकतम तापमान 40.6 तो वही न्यूनतम तापमान 28.5 दर्ज किया गया। सूरज की तीखी किरणों और हवा में भारी नमी के कारण लोग भीषण गर्मी और उमस से तरबतर हो रहे थे। दोपहर होते-होते स्थिति

ऐसी हो गई कि राहगीरों और कामकाजी लोगों का सड़कों पर निकलना दूभर हो गया था। पंखे और कूलर भी इस उमस भरी गर्मी के आगे बेअसर साबित हो रहे थे और हर कोई बस राहत की एक बूंद के लिए आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा था।

आसमान को काले बादलों ने घेरा

शाम होते-होते प्रकृति ने अपना रूप बदला और आसमान में अचानक काले-घने बादलों का डेरा जमा हो गया। देखते ही देखते ठंडी और तेज हवाओं ने दस्तक दी, जिससे पूरा वातावरण खुशनुमा हो गया। इसके बाद शहर के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। लंबे इंतजार के बाद हुई इस तेज बारिश ने तपती धरती को शांत किया और दिनभर की झुलसाने वाली गर्मी को पूरी तरह से सोख लिया। इस मानसूनी फुहार और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम पूरी तरह सुहावना और ठंडा हो गया।

तेज हवाओं ने किया परेशान

बारिश के साथ आए तेज आंधी-तूफान ने शहर में थोड़ा-बहुत व्यवधान और नुकसान भी पैदा किया। खास कर तूफान के बाद शहर के कई इलाको में विद्युत सेवा काफी देर के लिए बाधित हो गई । कुछ क्षेत्रों में एहतियातन बिजली की कटौती भी की गई, जिससे बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित हुई। तेज रफ्तार हवाओं के कारण शहर के कुछ इलाकों में पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिर गईं और कई जगहों पर होर्डिंग्स व बैनर उड़ गए। इसके बावजूद, इस मामूली नुकसान पर गर्मी से मिली बड़ी राहत भारी पड़ती दिखाई दी।

शाम को घूमने निकले लोग

बारिश थमने के बाद जब मौसम बेहद लुभावना और खुशनुमा हो गया, तो लोग खुद को घरों में रोक नहीं पाए। शाम के समय बड़ी संख्या में नागरिक, विशेषकर युवा और परिवार, इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए घरों से बाहर निकल पड़े। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, चौपाटी और बाजारों में लोगों की अच्छी-खासी रौनक देखी गई। कुल मिलाकर शुक्रवार की कड़कड़ाती और झमाझम बारिश ने जबलपुर वासियों को हफ्तेभर की थका देने वाली गर्मी से एक शानदार और तरोताजा करने वाली राहत प्रदान की है।

नियमित जांच और स्वस्थ्य जीवनशैली से हराई जा सकती है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी

हितकारिणी नर्सिंग कॉलेज ने मनाया राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर दिवस

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। हितकारिणी सभा द्वारा संचालित जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च (जिनसार) द्वारा राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर दिवस के अवसर पर अ सेलिब्रेशन फॉर लाइफ थीम के अंतर्गत 11 जून को यूसीएचसी, मनमोहन नगर में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रात: 11 बजे हुआ, जिसमें बीएससी नर्सिंग प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय के लोगों को कैंसर के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों, लक्षणों, कारणों, बचाव, निदान एवं उपचार के संबंध में जागरूक करना था। विद्यार्थियों ने लोगों को यह संदेश दिया कि कैंसर की शीघ्र पहचान एवं समय पर उपचार से इस गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत एक जागरूकता नाटक (स्किट) रहा, जिसमें कैंसर के कारणों, लक्षणों, उपचार एवं बचाव के उपायों को सरल एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने समुदाय के लोगों से संवाद स्थापित कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने तथा कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों को पहचानने के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की। यह कार्यक्रम जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च की प्राचार्य प्रो. डॉ. प्रिंसी शाजी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का सफल समन्वयन डॉ. रीना मैथ्यू, अरविंद यादव एवं आसिया अंसारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कैंसर के प्रति स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। यह आयोजन कैंसर सर्वाइवर्स के साहस, संघर्ष एवं जीवन के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को सम्मानित करने के साथ-साथ यह संदेश देने में सफल रहा कि जागरूकता, शीघ्र पहचान एवं समय पर उपचार से जीवन बचाया जा सकता है।

सांसद आशीष दुबे ने पाटन के दो दर्जन गांवों में किया धुआंधार जनसंपर्क

जबलपुर (स्वतंत्र मत) ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद आशीष दुबे ने पाटन विधानसभा के पौंडा मंडल के अंतर्गत आने वाले दो दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। सांसद ने ग्रामीणों, किसानों, युवाओं और महिलाओं से सीधा संवाद कर केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के जमीनी प्रभाव की जानकारी ली। सांसद आशीष दुबे ने कूड़ा, कंजई,

कैलवास, देवरी, सहजपुरा, चन्नौटा, मुरेठ, सिमरिया, पौंडा, मरहटी, बैहर, रिवझा और सागौड़ी सहित विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर चौपालें लगाईं। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आत्मीय मुलाकात की और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में राजकुमार पटेल, विद्या चौरसिया, राजेश दहिया, बृजेश पटेल, नीलू बाजपेयी उपस्थित रहे।

आज से शुरू होगा चिकित्सा ज्ञान का महाकुंभ 'एंडो डायलॉग 2026'

देश के 100 से अधिक दिग्गज डॉक्टर करेंगे मंथन

जबलपुर (स्वतंत्र मत) ।

संस्कारधानी जबलपुर एक बार फिर राष्ट्रीय चिकित्सा जगत के केंद्र में आने जा रही है। शहर के प्रतिष्ठित डायबिटीज, थायरॉइड, मोटापा एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव और डॉ. ऋतु श्रीवास्तव के नेतृत्व में 13 एवं 14 जून को पार्क इन बाय रैडिसन में दो दिवसीय राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन एंडो डायलॉग का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह सम्मेलन एंडोक्राइन और

मेटाबॉलिक रोगों के क्षेत्र में देश का एक बड़ा ज्ञान-संगम साबित होगा, जिसमें देशभर से 100 से अधिक ख्यातिप्राप्त चिकित्सक, शोधकर्ता और चिकित्सा प्रोफेसर हिस्सा लेंगे।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय ब्रिजिंग द गैप ऑन एंडो मेटाबॉलिक डिजीज रखा गया है।

इसके तहत आधुनिक दौर की सबसे बड़ी चिकित्सा चुनौतियों जैसे मधुमेह, थायरॉइड, मोटापा, हार्मोनल असंतुलन और इनसे जुड़े हृदय रोगों के उपचार में आ रहे आधुनिक तकनीकी बदलावों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

बदलती लाइफस्टाइल और बीमारियां- डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आज के दौर में खराब जीवनशैली के कारण ये बीमारियां बहुत तेजी से पैर पसार रही हैं। ऐसे समय में आम मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए डॉक्टरों का नवीनतम चिकित्सा ज्ञान और तकनीकों से अपडेट होना बेहद जरूरी है। देशभर से आ रहे विशेषज्ञों के लिए विशेष वैज्ञानिक सत्र, पैनल डिस्कशन और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां तैयार की गई हैं, जिससे डॉक्टरों के क्लीनिकल अनुभवों का सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा। डॉ. पुष्पराज पटेल ने एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज मधुमेह और दिल की बीमारियां एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अनियंत्रित डायबिटीज के कारण हार्ट अटैक और अन्य हृदय रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

अवैध शराब के जखीरे के साथ आरोपी गिरफ्तार

घर से कर रहा था अवैध शराब बेचने का काम

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। जिले में अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैंट थाना पुलिस ने घेराबंदी कर एक शराब के तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। बरामद की गई शराब की कुल कीमत लगभग 60 हजार रुपये है ।

कैंट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र पटले ने बताया कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि बगीचा नंबर 57, चिकनी रोड इलाके में एक व्यक्ति अपने खंडहरनुमा घर में भारी मात्रा

में अवैध शराब छिपाकर बेचने की फिराक में है। पुलिस टीम ने तत्काल बताए गए स्थान पर दबिश दी। वहां खंडहर के पास खड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे सक्रिय टीम ने तत्परता से घेराबंदी कर दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी का नाम 45 वर्षीय दिलीप कुमार पटेल उर्फ बिल्लू , निवासी चिकनी रोड, बगीचा नंबर 57 (कैंट) पता चला । पुलिस ने तलाशी ली, तो आरोपी के पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद हुआ। तलाशी के दौरान दो कार्टूनों से कुल 16 बोतल बैगपाइपर व्हिस्की, तीन कार्टूनों से 8-पीएम व्हिस्की के 122 पाव और एक नीले रंग के पिट्ठू बैग से बैगपाइपर के 81 पाव बरामद किए गए।

आरोपी के कब्जे से कुल 16 बोतल और 203 पाव अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। कैंट पुलिस ने आरोपी दिलीप उर्फ बिल्लू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से यह पूछताछ कर रही है कि वह यह शराब कहां से लेकर आया था और इसे किसे सप्लाई करने वाला था।

गंदगी फैलाने वाले 47 लोगों पर की गई कार्रवाई

जबलपुर (स्वतंत्र मत) । नगर निगम के सभी 16 संभागों में स्वच्छता टीम द्वारा एक साथ औचक निरीक्षण और चालानी कार्रवाई का अभियान चलाया गया। इस व्यापक अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले 47 लोगों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मौके पर ही चालानी कार्रवाई करते हुए 1 लाख 32 हजार 4 सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया। निगम के स्वास्थ्य विभाग और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों की टीमों ने सभी संभागीय क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई शुरू की। मुख्य बाजारों, व्यावसायिक क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में कार्रवाई की गई।

दफ्तर छोड़ फील्ड पर रहें अफसर: निगमायुक्त

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और स्वच्छता को चाक-चौबंद बनाने के लिए सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करते निगमायुक्त ने सिविल लाइंस और इलाहाबाद बैंक चौराहे से लेकर डुमना एयरपोर्ट चौक तक के पूरे मार्ग का सघन जायजा लिया। निगमायुक्त ने न सिर्फ सफाई व्यवस्था को देखा, बल्कि उद्यान और लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की भी जमीनी हकीकत जानी।

निरीक्षण के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए निगमायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे दफ्तरों में बैठने के बजाय अनिवार्य रूप से फील्ड पर रहें। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट और शहर की हरियाली से जुड़े हर काम की मॉनिटरिंग सीधे मौके पर जाकर की जाए।

रेलवे पुल के नीचे चल रहा अवैध कार वॉश बंद, रांझी में होटलों पर जुर्माना

जबलपुर (स्वतंत्र मत) ।

संस्कारधानी को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए निगम की टीम ने गौरीघाट रेत नाका रेलवे पुल के नीचे शासकीय भूमि से न सिर्फ अवैध कब्जा हटाया, बल्कि गंदगी फैलाने वाले संचालक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। इसके साथ ही रांझी क्षेत्र में भी स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। गौरीघाट मामले की जानकारी देते हुए संभागीय अधिकारी पंकज अवस्थी ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक युवक रोहित बर्मन द्वारा रेलवे पुल के नीचे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर कार वाशिंग की दुकान चलाई जा रही थी। इस दुकान के कारण न केवल बेशकीमती सरकारी जमीन का दुरुपयोग हो रहा था, बल्कि वाशिंग के केमिकल और गंदे पानी से पूरे इलाके में भारी गंदगी फैल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने मौके पर ही दुकान को जमींदोज कर दिया और 5 हजार का स्पॉट फाइन किया।

रांझी में होटलों की चेकिंग

संभाग क्रमांक 10 रांझी में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सघन चेकिंग की गई। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम जब कमल दास नामक होटल संचालक के संस्थान पर पहुंची, तो वहां डस्टबिन नहीं मिली और चारों तरफ गंदगी पसरी हुई पायी गयी । इस पर नाराजगी जताते हुए टीम ने तत्काल चालानी कार्रवाई की और सख्त हिदायत दी।

काम से लौट रहे युवक को अज्ञात बाइक सवार ने मारी टक्कर

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। घमापुर थाने में 38 वर्षीय शुभम आर्थर निवासी कांचघर घमापुर ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 11 जून की रात वह अपना काम खत्म करके ऑटो में बैठकर वापस घर लौट रहा था। कांचघर चौक पर पहुंचने के बाद वह ऑटो से उतरा और पैदल अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह जैसे ही कांचघर चौक के पास स्थित एक बर्तन दुकान के सामने पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात बाईक चालक ने अपने वाहन को लापरवाही और अत्यधिक तेज गति से चलाते हुए उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे शुभम सड़क पर दूर जा गिरा और उसके हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद आरोपी बाइक सवार तेजी से वाहन चलाते हुए मौके से रफूचक्कर हो गया। अचानक हुई इस घटना और चोट लगने के कारण पीड़ित मोटरसाइकिल का नंबर नहीं देख पाया। आसपास के लोगों की मदद से घायल को प्राथमिक उपचार दिलाया गया। जिसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया।

मार्कशीट ही फर्जी है तो सुनवाई का क्या औचित्य?

आंगनबाड़ी आवेदिकाओं की याचिकाएं खारिज

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर बेहद तल्ख और सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने टीकमगढ़ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती से जुड़े एक मामले में दो महिलाओं की याचिकाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा, जब भर्ती प्रक्रिया में शामिल की गई 12वीं की मार्कशीट ही फर्जी पाई गई है, तो आवेदिकाओं को अतिरिक्त सुनवाई का अवसर देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के कीमती समय को बर्बाद करना होगा। जस्टिस विशाल मिश्रा की वेकेशन बेंच ने यह कड़ा फैसला ममता यादव और नीतू राजपूत द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया। दोनों महिलाओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर

करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के प्रशासनिक आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

मेरिट लिस्ट में थीं टॉपर, शिकायत के बाद खुली पोल

मामला साल 2025 की भर्ती से जुड़ा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जून 2025 में जारी विज्ञापन के तहत दोनों महिलाओं ने आवेदन किया था। आवेदन के साथ उन्होंने महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल द्वारा जारी 12वीं की अंकसूची अपलोड की थी। शुरुआती दस्तावेज सत्यापन के बाद अगस्त 2025 में जब अंतरिम मेरिट सूची जारी हुई, तो दोनों महिलाएं अंक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर थीं और उनका चयन पक्का माना जा रहा था। इसी बीच, अक्टूबर 2025 में जिला चयन समिति के पास इनकी मार्कशीट फर्जी होने की शिकायत पहुंची।

संस्थान की रिपोर्ट ने खोली पोल

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला स्तरीय विवाद निवारण समिति ने संबंधित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से इन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराया। संस्थान ने जनवरी 2026 में अपनी रिपोर्ट भेजकर साफ कर दिया कि दोनों ही मार्कशीट पूरी तरह फर्जी और कूटरचित हैं।

इस खुलासे के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 26 मई 2026 को आदेश जारी कर दोनों आवेदिकाओं को अयोग्य घोषित कर दिया और विभाग को 7 दिनों के भीतर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह बघेल ने पक्ष रखा और कोर्ट के सामने फर्जीवाड़े के पुख्ता सबूत पेश किए। रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि पुलिस उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करती है, तो वे कानून के दायरे में रहकर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगी।

उबाऊ नहीं, दिलचस्प बनाइए इतिहास की हर कक्षा

इतिहास केवल बीते हुए समय की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन लोगों, संघर्षों, खोजों और उपलब्धियों की जीवंत कहानी है, जिन्होनें हमारे वर्तमान को आकार दिया है। दुर्भाग्य से कई बच्चे इतिहास को केवल तिथियों और तथ्यों को याद करने वाला विषय समझते हैं, जिसके कारण उनकी रूचि कम हो जाती है। यदि इतिहास को कहानी, चित्र, अभिनय, खेल और रोचक गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए तो यह बच्चों के लिए किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं होगा। एक अच्छा शिक्षक इतिहास को केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि बच्चों को उस युग का अनुभव कराता है। आइए जानते हैं कुछ प्रभावी तरीकों के बारे में, जिनकी मदद से इतिहास को बच्चों का पसंदीदा विषय बनाया जा सकता है।

इतिहास को कहानी की तरह सुनाएं

कक्षा में जब भी बच्चों को पढ़ाएं घटनाओं, राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कहानी के रूप में बताएं। जब बच्चे सुनेंगे कि कैसे किसी राजा ने कठिन परिस्थितयों का सामना किया या किसी वीर योद्धा ने साहस का परिचय दिया तो इतिहास के प्रति उनकी रूचि स्वत: बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप या रानी दुर्गावती की वीरता को कहानी के तौर पर सुनाने से बच्चे अधिक उत्साह से सीखते हैं।

चित्रों और मानचित्रों का करें प्रयोग

विभिन्न रिपोर्टस में यह बात सामने आयी है कि बच्चे दृश्य सामग्री को जल्दी समझते हैं। कक्षा में पढ़ाने के दौरान विभिनन ऐतिहासिक स्थलों, व्यक्तियों और घटनाओं के चित्र दिखाने से विषय जीवंत बन जाता है। बच्चा आसानी से विषय को समझ सकेगा ओर लंबे समय तक याद रख सकेगा। इसी तरह पढ़ाई के दौरान मानचित्रों के माध्यम से यह बताया जा सकता है कि कोई घटना कहां हुयी थी।

बच्चों से रोल प्ले करवाएं

पढ़ाते समय कक्षा में बच्चों को ऐतिहासिक पात्रों की भूमिका निभाने का अवसर दें। जब कोई बच्चा सम्राट अशोक, अकबर या भगत सिंह बनकर संवाद बोलता है तो वह उस चरित्र को बेहतर तरीके से समझ पाता है। बोले गए संवाद बच्चे के बाल मन में ताउम्र याद रहेंगें और वह संबंधित विषय को कभी भी नहीं भूल पाएगा। इसी तारतम्य में कक्षा में सुनने वाले अन्य बच्चे भी रोमांचक कहानी का वाचन सुनेंगे जिससे उनकी रूचि इतिहास के विषय में बढ़ेगी।

क्विज का आयोजन करें

कक्षा में समय समय पर बच्चों से इतिहास से जुड़े सवाल, पहेलियां और क्विज पूछें, इससे उनमें इतिहास के प्रति उत्सुकता पैदा होगी। ऐसा करने से उनकी याददाश्त भी मजबूत होगी और सीखने की यह प्रक्रिया मनोरंजक बन जाएगी। क्विज में विजेता बनने का लालच बच्चों को इतिहास पढ़ने के प्रति उत्सुक करेंगी और बच्चा इतिहास को रटने का नहीं समझने का प्रयास करेगा।

इतिहास को वर्तमान से जोड़ें

एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो विषय सामग्री को वर्तमान से जोड़कर पढ़ाए। इतिहास की विषय वस्तु को वर्तमान से जोड़कर पढ़ाने से बच्चा आसानी से समझ सकता है। बच्चों को बताएं कि इतिहास की अमुक घटनाओं का प्रभाव आज भी हमारे जीवन पर पड़ता है। उन्हें बताएं कि संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय प्रतीक और अनेक परंपराएं इतिहास की ही देन है। ऐसा करने से कक्षा का माहौल भी रचनात्मक होगा।

ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों की सैर कराएं

यदि संभव हो तो बच्चों को समय निकालकर संग्रहालय, किले, स्मारक या ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराएं। इन्हें देखने के साथ ही वहां स्थित शिलालेखों और स्मारक लेखों को पढ़ने से बच्चा अधिक जिज्ञासु भी बनेगा। ऐसा करने से वास्तविक वस्तुओं और स्थानों को देखकर इतिहास उनके लिए अधिक वास्तविक और यादगार बन जाता है। इतिहास के प्रति उनकी रूचि बढ़ेगी।

कहते हैं धरती हमारी माँ है। माँ अगर बीमार पड़े तो बेटा चैन से कैसे बैठे? आज हमारी धरती माँ बीमार है। बुखार है- ग्लोबल वार्मिंग का। साँस फूल रही है- प्रदूषण से। जख्म हैं- कटे हुए जंगलों के। पर अच्छी बात ये है कि इस बीमारी की दवा भी उसी के आंचल में है, और वो दवा हमारे हाथ में है।

धरती माँ को क्या-क्या बीमारी है?

पहली बीमारी- बुखार यानी ग्लोबल वार्मिंग

पेड़ कट रहे हैं, एसी-फ्रिज-गाड़ियों से गैस निकल रही है। नतीजा, गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस पार। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। मालदीव जैसे देश डूबने के कगार पर हैं।

दूसरी बीमारी- साँस की तकलीफ यानी वायु प्रदूषण

दिल्ली की हवा पीएम 2.5 से भरी है। बच्चे इन्हेलर लेकर स्कूल जा रहे हैं। फैक्ट्री का धुआँ, पटाखे, पराली जलाना- सब धरती के फेफड़े खराब कर रहे हैं।

तीसरी बीमारी- खून की कमी यानी जल संकट

नदियाँ कचरे से भरी हैं। भूजल 300 फीट नीचे चला गया है। चेन्नई, बेंगलुरु में पानी के लिए लड़ाई हो रही है। 'जल है तो कल है'- ये सिर्फ पोस्टर नहीं, सच्चाई है।

चौथी बीमारी- कैंसर यानी प्लास्टिक

1 प्लास्टिक बैग 500 साल तक खत्म नहीं होता। समुद्र में कछुए प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं। हमारे खाने में भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया है।

2. दवा क्या है और वो हमारे हाथ में कैसे है? डॉक्टर भगवान होते हैं, पर धरती के डॉक्टर हम खुद हैं। दवा महंगी नहीं है, बस इरादा चाहिए।

दवा नंबर 1 - पेड़

पेड़ धरती का फेफड़ा है। 1 बड़ा पेड़ रोज 4 लोग की ऑक्सीजन देता है। दवा- हर जन्मदिन, हर त्योहार पर 1 पेड़ लगाओ। एक पेड़ माँ के नाम- प्रधानमंत्री मोदी का अभियान यही कहता है। पेड़ काटो मत, लगाओ।

दवा नंबर 2 - 3आर का फॉर्मूला

Reduce, Reuse, Recycle। कपड़े का थैला रखो, प्लास्टिक ना कहो। पुरानी बोतल से फूलदान बनाओ। कचरे को कचरा मत समझो, रिसोर्स समझो। स्वच्छ भारत इसी दवा से बनेगा।

दवा नंबर 3 - पानी की एक-एक बूंद

ब्रश करते समय नल बंद = 6 लीटर पानी बचत। टपकता नल = रोज 20 लीटर बर्बाद। दवा- Rain water harvesting, टपक सिंचाई। खेत का किसान भी, शहर का छात्र भी - सब पानी बचा सकते हैं।दवा नंबर 4 - प्रदूषण को ना*

2 किमी तक पैदल जाओ, साइकिल चलाओ। पटाखे, कचरा जलाना बंद। सोलर एनर्जी अपनाओ। धरती माँ को धुआँ नहीं, ठंडी हवा चाहिए।

3. उदाहरण हमारे सामने हैं

Chipko आंदोलन की औरतों ने पेड़ से लिपटकर जंगल बचाया।

'वॉटर मैन' राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में सूखी नदियाँ जिंदा कर दीं।

अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं?

धरती माँ चीख नहीं रही, वो धीरे-धीरे घुल रही है। वो शिकायत नहीं करती, सहती जाती है। पर अब सहने की हद आ गई है।

याद रखो- हमारे पास Planet B नहीं है। Elon Musk मंगल पर कॉलोनी बनाए, पर माँ जैसी माँ नहीं मिलेगी।

इसलिए आज प्रण लें:-

धरती माँ बीमार है, दवा हमारे हाथ में है। मैं दवा दूंगा- पेड़ लगाकर, पानी बचाकर, प्लास्टिक हटाकर। क्योंकि धरती बचेगी, तभी भारत बचेगा। तभी हम बचेंगे। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य- ये सिर्फ नारा नहीं, जीने का तरीका बनाना होगा।

श्रीमती निधि पहारिया

एडीटी
बीएमडी हितकारिणी
चिल्ड्रन एकेडमी
दीक्षितपुरा, जबलपुर

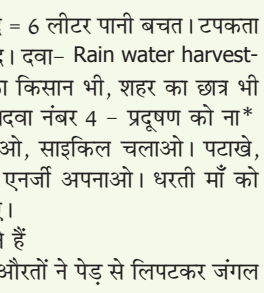

जिम्मेदार नागरिक बनें, राष्ट्र निर्माण में योगदान दें

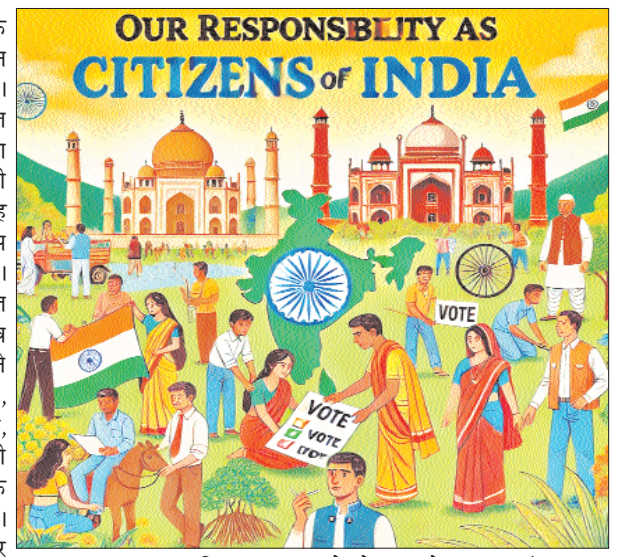

किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों की जागरूकता, अनुशासन और जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। एक जिम्मेदार नागरिक न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करता है, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करता है। वह समाज, पर्यावरण और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाता है। जिम्मेदार नागरिकता ही एक मजबूत लोकतंत्र और विकसित राष्ट्र की नींव है। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा, तब समाज अधिक सुरक्षित, स्वच्छ, शिक्षित और समृद्ध बनेगा। राष्ट्र की प्रगति सरकार और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। इसलिए आइए, हम सभी जिम्मेदार नागरिक बनकर एक बेहतर समाज और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

कानूनों का सम्मान और पालन करें

एक जिम्मेदार नागरिक हमेशा देश के कानूनों और नियमों का पालन करता है। यातायात नियमों का पालन करना, करों का भुगतान करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना नागरिक कर्तव्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कानूनों का सम्मान समाज में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

मताधिकार का सही उपयोग करें

लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि देश के भविष्य को तय करने की जिम्मेदारी भी है। जागरूक नागरिक सोच-समझकर मतदान करते हैं और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए हर चुनाव मे वोट डालने जरूर जाएं।

स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाएं

स्वच्छ वातावरण स्वस्थ समाज की पहचान है। अपने घर, विद्यालय, कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। स्वच्छता अभियान में भाग लेना और कूड़ा-कचरा निर्धारित स्थान पर डालना समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। ऐसा कर अपनी जिम्मेदारी समझें।

पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें

आज पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती हैं। पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और ऊर्जा की बचत करना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। प्रकृति की रक्षा करके हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।

पंचायती राजः लोकतंत्र की सशक्त आवाज

पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का माध्यम है। इसका उद्देश्य शासन को गांवों तक पहुंचाना, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना तथा विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और स्थानीय नेतृत्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह समझ लिया था कि भारत का विकास तभी संभव है जब लोकतंत्र की शक्ति गांवों तक पहुंचे। आज पंचायती राज व्यवस्था देश के लोकतांत्रिक ढांचे का महत्वपूर्ण आधार है और इसके सशक्तीकरण में राजीव गांधी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। सन 1980 के दशक में यह महसूस किया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई विकास योजनाओं का पूरा लाभ गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रशासनिक जटिलताओं और नौकरशाही के कारण विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। राजीव गांधी का मानना था कि यदि गांवों को अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति दी जाए तो विकास की गति तेज हो सकती है। उन्होंने कहा भी था कि सरकार द्वारा भेजे गए एक रुपये में से बहुत कम हिस्सा ही वास्तविक लाभार्थी तक पहुंच पाता है। इस समस्या का समाधान उन्होंने स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने में देखा।

64वां संविधान संशोधन विधेयक

वर्ष 1989 में राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य पंचायतों को अधिक अधिकार, नियमित चुनाव और वित्तीय संसाधन प्रदान करना था। यद्यपि यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, लेकिन इसने देश में पंचायती राज सुधारों की दिशा में मजबूत नींव रख दी। बाद के वर्षों में इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए संविधान संशोधन किए गए।

73वां संविधान संशोधन

वर्ष 1992 में पारित और 1993 से लागू हुए 73 वें संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यद्यपि यह संशोधन राजीव गांधी के निधन के बाद लागू हुआ, लेकिन इसकी मूल अवधारणा और प्रेरणा उनके प्रयासों से जुड़ी थी। इसलिए उन्हें पंचायती राज व्यवस्था के आधुनिकीकरण का प्रमुख सूत्रधार माना जाता है।

प्रमुख प्रावधान

- पंचायतों को संवैधानिक मान्यता।
- तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था।
- नियमित चुनाव की व्यवस्था।
- जनजाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण।
- राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।
- स्थानीय विकास योजनाओं में पंचायतों की भूमिका सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान

आसमान में कौन बजाता है ढोल?

जानिए बादलों की गर्जना और बारिश का रहस्य!

बरसात के मौसम में जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और तेज गर्जना सुनाई देती है, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर बादल गरजते क्यों हैं और बारिश कैसे होती है? क्या बादल आपस में टकराते हैं? क्या बिजली की चमक और गर्जना का कोई संबंध है? इन सवालों के जवाब विज्ञान में छिपे हैं, जो प्रकृति के इस अदभुत खेल को और भी रोचक बना देते हैं।

बादल बनते कैसे हैं

सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों, तालाबों और झीलों का पानी धीरे-धीरे भाप बनकर ऊपर आसमान में उठता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऊपर आसमान में जाते-जाते यह जलवाष्प ठंडी हवा के संपर्क में आकर छोटे-छोटे जलकणों में बदल जाती है। लाखों-करोड़ों जलकण मिलकर बादलों का निर्माण करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बादल आसमान में तैरते हुए पानी की बेहद छोटी-छोटी बूंदों और बर्फ के कणों का विशाल समूह होते हैं।

कैसे होती है बारिश

बादलों में मौजूद जलकण लगातार आपस में मिलते रहते हैं। धीरे-धीरे उनका आकार और वजन बढ़ने लगता है। जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती, तब वे पृथ्वी की ओर गिरने लगती हैं। यही प्रक्रिया वर्षा कहलाती है। यदि ऊपरी वातावरण बहुत ठंडा हो तो पानी बर्फ के रूप में गिर सकता है, जिसे ओले या हिमपात कहते हैं।

कैसे बनती है बादलों में बिजली

तूफानी बादलों के भीतर जलकण और बर्फ के कण तेज गति से टकराते रहते हैं। इन टक्करों से विद्युत आवेश (इलेक्ट्रिक चार्ज) पैदा होता है। बादल का एक हिस्सा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक आवेश से भर जाता है। जब इन आवेशों के बीच का अंतर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो अचानक ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह निकलता है। यही चमकती हुई रेखा हमें बिजली (लाइटिंग) के रूप में दिखाई देती है।

क्यों गरजते हैं बादल

जब बिजली चमकती है, तो उसके आसपास की हवा कुछ ही क्षणों में लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। इतनी तेज गर्मी से हवा अचानक फैलती है और फिर तेजी से सिकुड़ती है। हवा के इस विस्फोटक फैलाव और संकुचन से शक्तिशाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन्हीं ध्वनि तरंगों को हम बादलों की गर्जना के रूप में सुनते हैं।

बिजली पहले और आवाज बाद में क्यों

दिलचस्प बात यह है कि बिजली और गर्जना एक ही समय पर होती हैं, लेकिन प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत अधिक होने के कारण हमें पहले बिजली दिखाई देती है और बाद में गर्जना सुनाई देती है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, जबकि ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी कारण बिजली की चमक हमारी आंखों तक तुरंत पहुंच जाती है, जबकि उसकी आवाज कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है।

लोकतंत्र की मजेदार पहेलियां

न्याय दिलाना मेरा काम,
कानून का रखना सम्मान।
सबको समान अधिकार दिलाऊं,
बताओ मैं क्या कहलाऊं?
उत्तर - न्यायपालिका

पांच साल में एक बार आता,
जनता का फैसला कहलाता।
उंगली पर स्याही लगवाता,
लोकतंत्र को मजबूत बनाता।
उत्तर - मतदान

गांव की सरकार कहलाऊं,
गांव के विकास में काम आऊं।
सरपंच जिसके मुखिया होते,
बताओ हम क्या कहलाते?
उत्तर - पंचायत

जनता चुनकर मुझे बनाती,
देश की संसद तक पहुंचाती।
जनता की आवाज उठाता हूं
बताओ मैं कौन कहलाता हूं?
उत्तर - सांसद

मैं खबरों को पहुंचाता,
जनता को जागरूक बनाता।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता,
बताओ मैं कौन कहलाता?
उत्तर - मीडिया

भारतीय संविधान के रोचक तथ्य

- भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्तमान में इसमें 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है।
- भारतीय संविधान को न तो टाइप किया गया था न ही प्रिंट। इसे हाथ से लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे सुंदर कैलिग्राफी में लिखा था।
- संविधान की मूल प्रति आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम नियंत्रित बक्से में सुरक्षित रखी गयी है।
- संविधान की मूल कॉपी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गयी थी।
- संविधान सभा ने संविधान को बनाने में लगभग दो साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था।
- इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज इंजेक्शन का अकाल

बाजार से खरीदने को मजबूर मरीज, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप

कटंगी, स्वतंत्र मत

बालाघाट जिले के विकासखंड मुख्यालय कटंगी स्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली फिर एक बार सामने आई है। लंबे समय से यहां रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। कुत्ता, बिल्ली या अन्य जानवरों के काटने से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। मजबूरी में घायल और उनके परिजनों को बाजार से महंगा यानी करीब 4 सौ रुपए का इंजेक्शन खरीदकर लाना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में अन्य जरूरी इंजेक्शन और दवाओं का भी टोटा है। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन इस गंभीर मामले में लापरवाही बरत रहा है। शुक्रवार को अस्पताल में दो अलग-अलग स्थानों से ऐसे बच्चे (मरीज) पहुंचे जिन्हें 05 जून को कुत्ते ने काट लिया था। वह अपने पिता के साथ रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आए थे। लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्टॉक में इंजेक्शन न होने की बात कहते हुए उन्हें कल आना कहकर वापस जाने के लिए कह दिया था। बता दें जिन दो लोगों को वापस जाने के लिए कहा गया था उनमें एक नगर वार्ड क्रमांक 14 निवासी पार्षद प्रतिनिधि खेमू कोचर भी शामिल थे। जब उन्हें स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वापस जाने के लिए कहा कि तो उन्होंने सीधे लेखपाल सचिन अग्रवाल से चर्चा की। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने बाजार से रेबीज का इंजेक्शन मंगवाया और दोनों ही मरीजों को लगवाया।

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सवाल यही है कि यदि जनप्रतिनिधि हस्तक्षेप न करते तो क्या मरीजों को बिना इंजेक्शन लौटना पड़ता? गौरतलब हो कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर मुख्य जिला एवं चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रशासन का ध्यान नहीं है। दिलचस्प बात तो यह है कि बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने अब तक के अपने कार्यकाल में एक बार भी सरकारी अस्पताल कटंगी का निरीक्षण नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि जिले के आला अधिकारी समय-समय पर स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करें तो दवाओं की कमी, स्टाफ की लापरवाही जैसी समस्याएं सामने आ सकेंगी। कटंगी ब्लॉक मुख्यालय का अस्पताल होने के बावजूद यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव चिंताजनक है। खैर, इस घटना के सामने आने के बाद लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई और जवाबदेही तय होना जरूरी है और यह काम सीएचएमओ और कलेक्टर दोनों ही कर सकते है क्योंकि स्टॉक खत्म होने पर पहले से डिमांड न भेजने वाले प्रभारी पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में भी इस तरह की लापरवाही के मामले सामने आते ही रहेगें।

खेमू कोचर ने बताया कि 05 जून को उनके बेटे को कुत्ते ने काट लिया। घटना के बाद जब वह अस्पताल पहुंचे तो बेटे को रेबीज का इंजेक्शन लग गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इंजेक्शन के शेष डोज के लिए तिथि निर्धारित कर दी। निर्धारित तिथि पर जब वह अस्पताल पहुंचे तो इंजेक्शन ही नहीं था। समय पर इंजेक्शन नहीं लगने की वजह से अब फिर से पूरा कोर्स करना होगा। उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल गरीब जनता के लिए है। यदि यहां भी बाजार से इंजेक्शन खरीदना पड़े तो फिर सरकारी सुविधा का क्या मतलब? रेबीज का मामला बहुत संवेदनशील है। हमने लेखपाल से बात कर आज इंजेक्शन लगवाया, लेकिन रोज-रोज हम नहीं जा सकते। स्थायी समाधान होना चाहिए। ग्राम बासी ताराचंद राउत ने बताया कि उनके बेटे भव्य को 05 जून को कुत्ते ने काट दिया। वह अस्पताल पहुंचे इंजेक्शन लगा दूसरे डोज के लिए 08 जून को बुलाया गया। अस्पताल आए तो इंजेक्शन नहीं था 09 तारीख को बुलाया गया। 09 को इंजेक्शन लगा तीसरे डोज के लिए 12 को बुलाया गया आज पहुंचे तो फिर इंजेक्शन नहीं था। उन्होंने बताया कि उनका गांव अस्पताल से 10 किमी दूर है। डॉक्टर ने पर्ची पर इंजेक्शन लिखा और कर्मचारी बोल रहे है कि स्टॉक में नहीं है, मेडिकल स्टोर से ले आओ। 400-500 रुपये का एक डोज है। हमें 5 डोज लगवाने हैं। मजदूरी करके परिवार चलाते हैं, इतना पैसा कहां से लाएं? सरकार कहती है इलाज मुफ्त है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास कोई निजी साधन नहीं है ऐसे में ऑटो से आते है कि एक बार कटंगी आने-जाने में ही 120 का खर्च आता है बार-बार आना-जाना करते रहेगे तो पूंजी की बर्बादी होती है।

सूत्रों का कहना है कि समस्या केवल एंटी रेबीज वैक्सीन तक सीमित नहीं है। सरकारी अस्पताल कटंगी में तमाम तरह के जरूरी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और इमरजेंसी दवाओं की भी कमी है। कई बार मरीजों को सामान्य बुखार, उल्टी-दस्त की दवाएं भी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एंटी रेबीज वैक्सीन को अनिवार्य दवाओं की सूची में रखा गया है। नियमानुसार हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यह वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार नियमित बजट जारी करती है। जिला वैक्सीन स्टोर से ब्लॉक स्तर पर मांग के अनुसार सप्लाई दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग के जानकार बताते हैं कि यदि किसी केंद्र पर स्टॉक खत्म हो रहा है तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह 15 दिन पहले ही डिमांड भेजे।

इमरजेंसी में जिला मुख्यालय से तत्काल स्टॉक मंगाया जा सकता है। कटंगी में ऐसा न होना प्रबंधन की लापरवाही दर्शाता है। अस्पताल में जांच किट, एक्स-रे फिल्म और पैथोलॉजी रिएजेंट की कमी की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। इसके चलते मरीजों को निजी लैब में जांच करानी पड़ती है।

पार्षद प्रतिनिधि खेमू कोचर अपने बच्चे के साथ। ग्राम बासी निवासी ताराचंद राउत जानकारी देते हुए।

सेवानिवृत्त इंजी डॉ बी. एल. चौहान ने सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त राशि से झंझागी में बनाया बुद्ध विहार

डॉ. बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित और अनावरण आज

कटंगी(स्वतंत्र मत)। तहसील मुख्यालय कटंगी से 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत झंझागी में 13 जून को जीवन वाती मां सार्वजनिक बुद्ध विहार समिति झंझागी के तत्वाधान में परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहब अंबेडकर के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के 100 वे वर्षगाठ के अवसर पर बुद्ध विहार का लोकार्पण एवं सम्यक समबुद्ध व परम् पूज्य डॉ बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण व भिक्षु निवास का उद्घाटन कार्यक्रम के उद्घघाटक पूज्य भदंत धम्म तप कार्यक्रम अध्यक्षता एडवोकेट डॉक्टर संजय खोबरागड़े (जिला अध्यक्ष बालाघाट जिला बौद्ध संघ बालाघाट) कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय बोरकर (बामसेफ) दिल्ली, विशेष अतिथि दलित मेश्राम (अध्यक्ष तहसील बौद्ध संघ तिरोड़ी),कपिल मेश्राम (सभापति नगर परिषद कटंगी) ,महेंद्र हिरकने (तहसील अध्यक्ष बालाघाट जिला बौद्ध संघ तहसील शाखा कटंगी), संजय शेन्डे (अध्यक्ष डॉ अंबेडकर जयंती समारोह कटंगी) ,भोजराज वासनिक,(सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता)डी डी गजभिए (नगर अध्यक्ष जिला बौद्ध संघ कटंगी), रामचंद्र मेश्राम , प्रदीप ऊके (पूर्व जिला अध्यक्ष समता सैनिक दल बालाघाट) भीम प्रकाश बोरकर (जनपद सदस्य) यशवंत गणवीर (सचिव परम् पूज्य डॉ बाबा साहब अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह कटंगी) चन्द्रप्रभा युवराज वाघाडे(सरपंच ग्राम पंचायत झंझागी)विशेष आतिथ्य में संपन्न होगा।कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता दीपांशी बौद्ध आयु 13वर्ष व् सौम्य मेश्राम आयु 14वर्ष दोनों बुद्ध अम्बेडकर मिशन पर उद्बोधन करेंगे। बालाघाट जिले के इतिहास में ये इबारत स्वर्ग अक्षरो से लिखी जावेगी ग्राम के निवासी डॉ बी एल चौहान के द्वारा सेवानिवृत्त होने के उपरांत प्राप्त राशि से भव्य बुद्ध विहार का निर्माण करवाया व तथागत सम्यक संबुद्ध व परम् पूज्य डॉ बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा क्रय कर स्थापित किया है ज्ञात हो कि आरक्षण से जिले में अनेको अधिकारी व कर्मचारी बने किन्तु 20लाख रुपये की राशि व्यय कर किसे ने भी निर्माण नहीं किया है। कार्यक्रम 3 बजे से 5बजे विशाल धम्म रैली 6बजे नवनिर्मित बुद्ध विहार का लोकार्पण तथा तथागत सम्यक संबुद्ध व परम् पूज्य डॉ बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा व भिक्षु निवास का होगा।

जिला जेल उमरिया में यज्ञ हवन पूजन कार्यक्रम संपन्न

उमरिया, स्वतंत्र मत।

जेल अधीक्षक डी. के. सारस ने बताया कि आज जिला जेल उमरिया में गायत्री परिवार उमरिया के साधक श्री मनोज - उमेश्वरी विश्वकर्मा के द्वारा जेल में परिरुध बंदियों की मानसिक शांति एवं नशा मुक्त रहने के लिए यज्ञ हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधिक सहायता हेल्प डेस्क कक्ष में बंदियों को विधिवत मंत्रोच्चारण एवं यज्ञ हवनध्पूजन कराने के लिए बंदियों को अनुशासन में रखकर सम्मिलित कराया गया। बंदियों को यह कार्यक्रम आयोजित करने से अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिली। इस कार्यक्रम में जेल अधीक्षक डी. के. सारस एवं जेलर ध् उप अधीक्षक माखन सिंह मार्को तथा प्रमुख मुख्य प्रहरी शिवशंकर कोल तथा श्रीमती सुभद्रा ठाकुर, सहायक 02 एवं ड्यूटीरत अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी

उमरिया। पाली थाना अंतर्गत वार्ड कमांक 14 शंकर दफाई में आरोपियो ने फरियादी से गाली गालौज करते हुए मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी है। जानकारी अनुसार विमला बर्मन पति लल्ला बर्मन उम्र 55 साल कि शिकायत पर आरोपी सुनील बर्मन, संगीता बर्मन के खिलाफ मामला कायम कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है।

एक राय होकर की मारपीट -इंदवार थाना अंतर्गता ग्राम बंजरिया बडछड में आरोपियो ने एक राय होकर फरियादी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। फरियादी की शिकायत पर अतुल चौधरी, सरोज चौधरी पर पुलिस ने मामला कायम कर लिया है।

शटर खुलने से पहले ही खुल गई दीवारें, पाली के नए बस स्टैंड की गुणवत्ता पर फिर उठे सवाल

उमरिया, स्वतंत्र मत।

बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका क्षेत्र में साईं मंदिर के समीप करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित नया बस स्टैंड एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा किसी नई सुविधा या विकास कार्य की नहीं, बल्कि निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे गंभीर सवालों की है। हैरानी की बात यह है कि जिन दुकानों का संचालन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, उनकी दीवारों में आई दरारों के कारण मरम्मत का कार्य शुरू करना पड़ गया है। जानकारी के अनुसार बस स्टैंड परिसर में बनी दुकानों के पीछे की दीवारों में दरारें दिखाई देने लगी थीं। स्थिति इतनी गंभीर बताई जा रही है कि ठेकेदार को दीवार का एक हिस्सा बीच से तोड़कर दोबारा मरम्मत कार्य शुरू करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण पूरा होने और दुकानों के शटर खुलने से पहले ही दीवारों का टूटना पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक बस स्टैंड निर्माण कार्य शुरू होने के समय से ही गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई बार निर्माण सामग्री और कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें भी सामने आईं, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया।

परिणामस्वरूप आज नई-नई बनी संरचनाओं में खामियां दिखाई देने लगी हैं। नागरिकों का आरोप है कि यदि निर्माण कार्य के दौरान तकनीकी निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण सही तरीके से किए गए होते तो इतनी जल्दी दीवारों में दरारें नहीं आतीं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका के इंजीनियर और संबंधित अधिकारियों की निगरानी में यह निर्माण कार्य हुआ है, ऐसे में अब सामने आ रही खामियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे कुछ नागरिकों ने बताया कि दुकानों के पीछे दीवार खोलकर मरम्मत की जा रही है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि निर्माण में कहीं न कहीं गंभीर तकनीकी त्रुटियां रही हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि यदि अभी से ऐसी स्थिति है तो आने वाले वर्षों में भवन की स्थायित्व क्षमता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। नगर के वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि सार्वजनिक धन से निर्मित परियोजनाओं में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

बस स्टैंड जैसी महत्वपूर्ण परियोजना नगर की पहचान होती है, लेकिन यदि निर्माण के कुछ ही समय बाद मरम्मत की नौबत आ जाए तो यह जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। वहीं नगर में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि दुकानों के शटर तो अभी तक नहीं खुले, लेकिन दीवारें खुलना शुरू हो गई हैं। यह टिप्पणी अब लोगों के बीच नगर पालिका की कार्यशैली पर व्यंग्य के रूप में देखी जा रही है।नागरिकों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि बस स्टैंड निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए। साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि निर्माण में कहीं गुणवत्ता मानकों की अनदेखी तो नहीं की गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई तो भविष्य में और भी गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं। फिलहाल साईं मंदिर के समीप स्थित यह नया बस स्टैंड सुविधा से अधिक निर्माण गुणवत्ता को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि नगर पालिका के जिम्मेदारों की चुप्पी लोगों के संदेह को और बढ़ा रही है।

गौरव सिरोठिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं से किया वन टू वन संवाद

भाजपा की मासिक कामकाजी बैठक संपन्न

उमरिया। भारतीय जनता पार्टी जिला उमरिया की कामकाजी मासिक बैठक 12 जून को भाजपा कार्यालय भरौली में बड़े ही सौहार्द पूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न हुई। बैठक में संभागीय संगठन प्रभारी गौरव सिरोठिया, भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल, जिला महामंत्री दीपक छतवानी, हरीश विश्वकर्मा मंचासीन रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कौशल विश्वकर्मा ने बताया कि 12 जून को दोपहर 12 बजे से भाजपा कार्यालय भरौली में भाजपा की मासिक कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सबसे पहले अतिथियों ने भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की छायाचित्रों के समक्ष दीप प्रजलान और माल्यार्पण कर बैठक का शुभारंभ किया। तत्पश्चात भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने बैठक के एजेंडे और संगठन के आगामी कार्यक्रमों के बारे में और उसकी रूपरेखा को लेकर विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार भाजपा की मासिक बैठक हर महीने पहले सभी मंडलों में और फिर जिला स्तर पर की जाती है। जिले के सभी मंडलों में मासिक कामकाजी बैठक संपन्न हो चुकी है और अब जिला स्तर पर बैठक की गई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि यह बैठक मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल को लेकर रही है। इसी को लेकर जिला और मंडल स्तर पर आगामी कार्यक्रम किए जाने हैं जिसकी रूपरेखा तैयार की गई है। मुख्य वक्ता के रूप में बैठक को संबोधित करते हुए संभागीय संगठन प्रभारी श्री गौरव सिरोठिया जी ने कहा कि हम सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि संगठन को मंडल से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक सशक्त बनाना है।

उन्होंने सभी मंडलों के अध्यक्ष, मंडल प्रभारी,संयोजक और टोली प्रमुखों से वन टू वन चर्चा करते हुए संगठन की मजबूती और उसके विस्तार पर जोर दिया। वहीं श्री सिरोठिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, उन्होंने 12 साल पूर्ण कर लिया है। बीते 12 वर्षो में देश विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, आधारभूत संरचना, आत्मनिर्भरता, डिजिटल नवाचार, गरीब कल्याण एवं वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं।आज भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार, आर्थिक प्रगति तथा सांस्कृतिक गौरव के नए युग में प्रवेश कर चुका है। इसके अलावा उन्होंने बीते दिनो संपन्न हुए दो दिवसीय पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण वर्ग की सफलता को लेकर और खासकर जिला भाजपा के द्वारा जिले के दिवंगत भाजपा कार्यकर्ताओं की तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि देने का नवाचार किया गया उसकी उन्होंने जमकर सराहना की।

लालपुर सामुदायिक भवन में तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर का शुभारंभ

विधायक बांधवगढ़ ने नागरिकों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील

उमरिया । मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद उमरिया द्वारा वार्ड क्रमांक 3 स्थित लालपुर सामुदायिक भवन में तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे शिविर में पहुंचकर शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। नगर पालिका उपाध्यक्ष अमृतलाल यादव ने भी लोगों से बड़ी संख्या में शिविर में पहुंचने तथा उपलब्ध सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया।शिविर के दौरान अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेनगुप्ता एवं डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।जन कल्याण शिविर में शासन के विभिन्न विभागों द्वारा 111 जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं। नागरिक अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह शिविर 12 जून से 14 जून तक संचालित होगा।मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह ठाकुर ने शिविर के उद्देश्यों एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों को एक ही स्थान पर शासन की अनेक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उन्हें विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की बचत होगी।

कार्यालय नगर पालिका परिषद उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक/1694/नि.सू./2026 उमरिया, दिनांक 11.06.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु जेम पोर्टल में पंजीकृत फर्म/संस्था/ठेकेदारों से जेम पोर्टल में ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। https://gem.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	बिड क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	लागत राशि	आमनत राशि राशि	कार्य की समयावधि	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	GEM/2026/B/7635175 Date 08/06/2026	Precast Concrete Manhole Cover and Frame (V3) Conforming to IS 12592 (Q3)	10,00,000.00	10,000.00	150 दिवस	24-06-2026
2	GEM/2026/B/7635424 Date 08/06/2026	Operation And Maintenance Of Water Supply Systems-only 10 labour	10,00,000.00	10,000.00	90 दिवस	24-06-2026
3	GEM/2026/B/7606190 Date 08/06/2026	Repair, Maintenance, and Installation of Plant/Systems/Equipents (Version 2)-Commercial, Free water kiosk, only labour	3,60,000.00	3,600.00	71 दिवस	24-06-2026

नोट : - निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://gem.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद उमरिया
जिला-उमरिया (म.प्र.)

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विकास और आत्मनिर्भरता की बनाई नई पहचान, पीआईबी ने किया वार्तालाप कार्यक्रम

मण्डला(स्वतंत्रमत)

जिला मुख्यालय के विट्ठल इन होटल में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी भोपाल द्वारा आयोजित एक दिवसीय वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उईके ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में विकास सुशासन और आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज देश दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों के कारण वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान और प्रभाव लगातार बढ़ा है केबिनेट मंत्री ने एक दिवसीय वार्तालाप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया गया है महिलाओं किसानों युवाओं गरीबों एवं वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की गई हैं उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण मुद्रा योजना प्रधानमंत्री आवास योजना उज्ज्वला योजना जल-जीवन-मिशन तथा अन्य जनहितकारी कार्यक्रमों ने लाखों परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत संरचना डिजिटल सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। देश के गांवों तक सड़क बिजली पानी और डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विज्ञान तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा और बढ़ी है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद का दशक विकास के शानदार कीर्तिमान का दशक रहा है। सिंचाई राजमार्ग स्वास्थ्य विज्ञान एवं तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश में मात्र 7 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही थी। आज 2026 में 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर किसानों को खेती को लाभ में बदलने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मध्यप्रदेश ही नहीं पूरे देश में राजमार्गों का ऐसा जाल बिछाया गया है कि देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 4 से 6 लेनों के शानदार राजमार्ग बनकर तैयार हो गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अटल टनल जैसे अनेक कीर्तिमान हासिल किए गए हैं जिनकी बराबरी मुश्किल है इस दशक में करीब 23 करोड़ से अधिक नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं हाई स्पीड ट्रेन के मामले में भी देश ने ऊंचे प्रतिमान हासिल किए हैं वार्तालाप कार्यक्रम के आरंभ में दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने वार्तालाप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने स्वागत उद्बोधन में मनीष गौतम ने कहा कि सरकार गरीब उपेक्षित किसान मजदूर सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक योजनाओं कार्यक्रमों को आमजन के लिए तैयार कर उनका सफल क्रियान्वयन कर रही है। इन योजनाओं से निश्चित ही बड़ी संख्या में देश के नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय का यह प्रयास होता है कि केंद्र सरकार की इन योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया के माध्यम से आमजन तक जानकारी उपलब्ध कराई जाए सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों में वार्तालाप जैसे कार्यक्रमों के जरिए यह प्रयास किए जाते रहते हैं मंडला में उसी के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम ने कहा कि आज देश बदल रहा है देश की सैन्य शक्ति सशक्त हुई है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित हुआ है महिला सशक्तिकरण से देश मजबूत हो रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा ने भी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इन अधिकारियों ने केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी कृषि विज्ञान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीमती दीपाली वाजपेई ने चर्चा की चिकित्सा अधिकारी डॉ.डीके मरकाम ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित और शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सुजय कुमार ने मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में जिले के एक सफल किसान सुनील झारिया ने प्राकृतिक कार्बनिक खेती के विषय में अपने सफल प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इस अवसर पर सहायक संचालक जनसंपर्कराहुल वासनिक, जेपी सिंह, सुलोचना रजक, उप परियोजना संचालक आत्मा अंजू कोडापे सहित प्रगतिशील कृषक, दीदी एवं मीडिया कर्मी उपस्थित थे कार्यक्रम में पीआईबी भोपाल के सहायक निदेशक अजय प्रकाश उपाध्याय ने आभार व्यक्त किया वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहायक प्रचार अधिकारी अजय बैंस ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर जिले के पत्रकार भी उपस्थित रहे।

ग्रामीणों को मिल रहा लाभ

मण्डला(स्वतंत्रमत)। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से समर्पित संस्था द्वारा संचालित तीनों वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से जिले के सभी नौ विकासखंडों में वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया अभियान के तहत सीएफएल के ब्लॉक काउंसलर गांव-गांव पहुंचकर वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं बीमा योजनाओं तथा वित्तीय प्रबंधन के संबंध में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही बैंक प्रबंधकों एवं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को भी शिविरों में आमंत्रित किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों के बीमा एवं अटल पेंशन योजना के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं इस पहल के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं की जानकारी उनके गांव में ही उपलब्ध हो रही है।

युवा-संगम मेला 16 को

मण्डला(स्वतंत्रमत)। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा-संगम रोजगार मेला का आयोजन 16 जून को किया जाएगा। यह आयोजन जिला रोजगार कार्यालय आईटीआई एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में नगरपालिका के हॉल में सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित होगा।

महिलाओं को 31 दिवसीय प्रशिक्षण

मण्डला(स्वतंत्रमत)। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सेंट-आरसेटी द्वारा जिला आजीविका मिशन के तत्वावधान में महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 31 दिवसीय महिला सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 13 मई से 12 जून तक संचालित हुआ जिसमें स्व-सहायता समूहों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली 20 महिलाओं ने भाग लिया प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सलवार-सूट, लहंगा, स्कूल ड्रेस सहित विभिन्न आकर्षक परिधानों की सिलाई का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

वनाधिकार समिति की बैठक

मण्डला(स्वतंत्रमत)। कलेक्टर एवं जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के अध्यक्ष राहुल नामदेव धोटे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई बैठक में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त दावों के निराकरण एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से संबंधित विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई बैठक में एमपीएफआरए पोर्टल पर दर्ज नवीन व्यक्तिगत वनाधिकार दावों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

आबकारी विभाग ने की कार्यवाही

मण्डला(स्वतंत्रमत)। जिला आबकारी अधिकारी एवं प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी शैली सैयाम के मार्गदर्शन में मण्डला वृत्त अंतर्गत अवैध शराब के विरुद्ध विशेष दबिश कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान ग्राम गाजीपुर स्थित एक होटल की तलाशी में अवैध रूप से मदिरा विक्रय किया जाना पाया गया जिस पर आबकारी विभाग ने विधिवत प्रकरण दर्ज किया। इसी प्रकार ग्राम पुरवा क्षेत्र के झूलापुल के पास भारती बाई के निवास की तलाशी लेने पर छह कैन किंगफिशर बियर दो बोतल विदेशी मदिरा तथा एक आधी भरी हुई मदिरा की बोतल बरामद कर जब्त की गई वहीं सकवाह क्षेत्र में अमित कछवाहा की दुकान से दो बोतल बियर छह नग देसी प्लेन मदिरा तथा पांच बोतल विदेशी मदिरा बरामद कर जब्त की गई।

आरक्षक आत्महत्या मामले में दो महिला एक पुरूष गिरफ्तार

मण्डला/बम्हनी(स्वतंत्रमत)। जिले के बम्हनी बंजर थाना परिसर में पदस्थ आरक्षक द्वारा आत्महत्या किए जाने के बहुचर्चित मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस ने मामले में दो स्टाफ नर्सों और एक नर्स के भाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण जान से मारने की धमकी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने बताया कि मृतक आरक्षक सुनील सरयाम उम्र 40 वर्ष द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट तथा अन्य तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर की गई विस्तृत जांच में यह तथ्य सामने आए हैं। वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान आरक्षक सुनील सरयाम की पदस्थापना बम्हनी बंजर क्षेत्र में थी। इसी दौरान उनका स्थानीय अस्पताल में कार्यरत दो स्टाफ नर्सों से संपर्क हुआ। जांच में सामने आया कि इसी दौरान आरोपियों ने आरक्षक की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें अपने कब्जे में ले ली थीं। बाद में इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जाने लगा। बताया गया है कि पिछले लगभग तीन वर्षों से आरक्षक मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहा था। आरोपियों द्वारा तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन पर लगातार दबाव बनाया जाता था। वहीं एक नर्स के भाई द्वारा भी आरक्षक को जान से मारने की धमकियां दिए जाने की बात जांच में सामने आई है। लगातार हो रही ब्लैकमेलिंग सामाजिक बदनामी के भय और मानसिक तनाव के कारण आरक्षक गहरे अवसाद में चले गए थे। वहीं 8 जून 2026 को बम्हनी बंजर थाना परिसर स्थित शासकीय आवास में आरक्षक सुनील सरयाम का शव फांसी के फंद पर लटका हुआ मिला था। इस घटना ने पूरे पुलिस विभाग को झकझोर कर रख दिया था। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच प्रारंभ की गई थी। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था जिसमें मृतक आरक्षक ने अपनी आत्महत्या के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए लगातार प्रताड़ित किए जाने ब्लैकमेलिंग और धमकियों का उल्लेख किया था। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने तकनीकी जांच मोबाइल कॉल डिटेल डिजिटल साक्ष्य और अन्य तथ्यों का परीक्षण किया। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों से आरोपों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दो महिला स्टाफ नर्सों एवं एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ साथ एससी एसटी एक्ट के तहत भी कार्यवाही की गई है।

गरीबों पर कहर: प्रदेश अध्यक्ष के हस्तक्षेप से मिला न्याय

मण्डला(स्वतंत्रमत)

जिला मुख्यालय के उपनगर महाराजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पौंडी में पंचायत की जमीन को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पेट्रोल पंप के समीप स्थित पंचायत भूमि पर वर्षों से छोटे-छोटे व्यवसाय कर अपना जीवनयापन कर रहे गरीब और आदिवासी कुम्हार प्रजापति परिवारों को हटाकर एक दबंग व्यक्ति द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तेकाम मौके पर पहुंचे और हस्तक्षेप करते हुए कार्यवाही रुकवाई। जानकारी अनुसार पंचायत की उक्त भूमि पर कई वर्षों से स्थानीय गरीब परिवार अपनी छोटी-छोटी दुकानें लगाकर रोजी-रोटी चला रहे हैं। इन परिवारों का जीवनयापन इसी व्यवसाय पर निर्भर है। आरोप है कि क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने इन लोगों को हटाकर जमीन पर अपना कब्जा जमाने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए मौके पर जेसीबी मशीन भी बुला ली गई थी जिससे वहां मौजूद दुकानों और अस्थायी निर्माणों को हटाया जा सके। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तेकाम को दी गई। सूचना मिलते ही वे तत्काल मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित व्यक्ति को पंचायत भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं करने की चेतावनी देते हुए कार्रवाई पर रोक लगवाई। इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों और दुकानदारों ने राहत की सांस ली। वहीं कमलेश तेकाम ने कहा कि यह जमीन ग्राम पंचायत की संपत्ति है और इस पर वर्षों से गरीब आदिवासी कुम्हार प्रजापति परिवार अपनी दुकानों के माध्यम से रोजगार चला रहे हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति द्वारा दबंगई के बल पर इन लोगों को हटाकर कब्जा करना न केवल गलत है बल्कि गरीबों के अधिकारों का हनन भी है। उन्होंने कहा कि पंचायत की जमीन पर किसी भी व्यक्ति का निजी कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि इस भूमि का उपयोग होना है तो वह गांव और ग्रामीणों के हित में होना चाहिए। इसके लिए पंचायत स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार विकास कार्य किए जाएं ताकि पूरे गांव को उसका लाभ मिल सके। कमलेश तेकाम ने ग्राम पंचायत पौंडी के सरपंच से भी इस संबंध में चर्चा की और भूमि की स्थिति की जानकारी ली।

केरेगांव खरीदी केंद्र में लाखों का गेहूं खराब

अधिकारियों के संरक्षण में गुणवत्ताहीन खरीदी के आरोप

जांच की मांग तेज

नैनपुर (स्वतंत्र मत)

जिले में स्थित केरेगांव उपार्जन केंद्र एक बार फिर विवादों में घिर गया है। यहां पर कथित रूप से गुणवत्ता हीन गेहूं एवं धान की खरीदी का मामला सामने आया है, जिससे लाखों रुपये के अनाज के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय किसानों और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे प्रकरण में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार, गत वर्ष भी इसी केंद्र पर घुन लगे एवं पुराने गेहूं की खरीदी का मामला उजागर हुआ था। मामला मीडिया में आने के बाद तत्कालीन कलेक्टर मंडला, सोमेश मिश्रा द्वारा जांच दल गठित किया गया था तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित स्व-सहायता समूह के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद इस वर्ष पुन: केरेगांव में उपार्जन केंद्र संचालित कर मलारा सहकारी समिति को गेहूं खरीदी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आरोप है कि इस बार भी दूरदराज के किसानों एवं व्यापारियों से पुराना और निम्न गुणवत्ता वाला गेहूं खरीदा गया, जो मानकों के अनुरूप नहीं था। परिणामस्वरूप, हीरापुर ओपन कैम्प, नैनपुर वेयरहाउस तथा घुघरी गोदाम में बड़ी मात्रा में गेहूं रिजेक्ट किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 ट्रक गेहूं को अमान्य घोषित किया गया है, वहीं केरेगांव केंद्र में गेहूं खराब हालत में पड़ा हुआ है, जिससे शासन को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है नवागत कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे से क्षेत्रीय किसानों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि जहां अन्य केंद्रों में उनके गेहूं को गुणवत्ता के नाम पर अस्वीकार किया जाता है, वहीं केरेगांव केंद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर खरीदी की गई। भारत कृषक समाज ने भी इस मुद्दे पर एसडीएम नैनपुर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी थी, जिसके बाद कुछ स्थानों पर खरीदी शुरू हुई। लेकिन केरेगांव केंद्र पर किसानों की भागीदारी न के बराबर बताई जा रही है, जिससे व्यापारियों की भूमिका पर संदेह गहरा गया है।

करोड़ों के नुकसान की आशंका

नागरिक आपूर्ति निगम और सहकारिता विभाग की संयुक्त व्यवस्था के तहत संचालित इस खरीदी केंद्र में हर वर्ष सर्वाधिक खरीदी होती है। आरोप है कि इसी कारण यहां गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, जिससे शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है।

शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

मण्डला(स्वतंत्रमत)

जिले में अवैध शराब के निर्माण परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंडला पुलिस को सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड क्षेत्र स्थित एक होटल में दबिश देकर 63 लीटर 760 मिलीलीटर अवैध देशी एवं अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी के निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पीयूष मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने होटल में तलाशी ली।

कार्यालय नगरपालिका परिषद मण्डला

Tele-07642-250705 E-mail-cmomandla.mpurban@ gmail.com Web site- Ngarpalikamandia.mp-np.in

क्रमांक/रा.शा./2026/1073 मण्डला, दिनाक 11/06/2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका डे-एनयूएलएम शाखा के गेट के बाजू में सागर किराना के पीछे तक प्रथमतल 13 व्यवसायिक दुकानों हेतु रिक्त भूखण्ड एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना जवाहर गंज बाजार श्रीराम लाईब्रेरी (वाचनालय) स्थित व्यवसायिक भूखण्ड क्रं. 07, को राईट-ऑफ आक्यूपेशन आधार पर आवंटन हेतु ई-निविदा, Web site-mp tenders.gov.in में दिनांक 29/06/2026 को समय शाम 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त ई-निविदा 01/07/2026 को समय दोपहर 12:00 बजे से तकनीकी निविदा फार्म एवं दिनांक 02/07/2026 को समय दोपहर 12 बजे से फायनेंसियल बिड (दर) खोली जावेंगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिनांक 29/06/2026 को समय 06:00 बजे तक अमानत राशि ऑनलाईन जमाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

टेण्डर क्रं.	भूखण्ड क्र.	आउटर साईज (मीटर में)	आरक्षण वर्ग	आरक्षित मूल्य	प्रतिभूति निक्षेप (अमानत राशि)	लीज अवधि	वार्षिक (भू-भाटक) किराया
2026_UAD_515000_1	1.	3.75X5.40	अनारक्षित	10,68,732 रु.	1,06,900 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515003_1	2.	3.65X5.40	अनारक्षित	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515005_1	3.	3.65X5.40	अनारक्षित	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515007_1	4.	3.65X5.40	अनारक्षित	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515008_1	5.	3.65X5.40	अनारक्षित	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515010_1	6.	3.65X5.40	अनारक्षित	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515013_1	7.	3.65X5.40	अनारक्षित	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515014_1	8.	3.65X5.40	अनारक्षित	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515015_1	9.	3.65X5.40	अन्य पिछड़ा वर्ग	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515018_1	10.	3.65X5.40	अनुसूचित जनजाति	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515019_1	11.	3.65X5.40	अनुसूचित जाति	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515022_1	12.	3.65X5.40	अनारक्षित वर्ग की विधिवा महिला के लिये	10,55,124 रु.	1,05,600 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%
2026_UAD_515023_1	13.	3.75X5.40	अनारक्षित	10,68,732 रु.	1,06,900 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%

द्वितीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना

टेण्डर क्रं.	भूखण्ड क्र.	आउटर साईज (वर्ग मीटर में)	आरक्षण वर्ग	आरक्षित मूल्य	प्रतिभूति निक्षेप (अमानत राशि)	लीज अवधि	वार्षिक (भू-भाटक) किराया
2026_UAD_503918_2	07.	14.84	अन्य बिछड़ा वर्ग	15,19,680 रु.	1,52,000 रु.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम आफॅर का 2%

नोट:- 1. इच्छुक निविदादाता निविदा संबंधी नियम व शर्तें Web site-mp tenders.gov.in में देखी जा सकती हैं एवं ऑनलाईन ई-निविदा प्रपत्र राशि 2,000 रूपये निर्धारित है। निविदा प्रपत्र केवल Web site-mp tenders.gov.in से क्रय किये जा सकते है। 2. नगरपालिका के किसी भी प्रकार के बकायादारों को निविदा प्रपत्र प्रदान नहीं किया जावेगा। इच्छुक व्यक्ति को न.पा. से जारी कर-बेवाकी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। 3. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में ऑन-लाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

(विनोद कछवाहा) अध्यक्ष न.पा.परिषद मण्डला

(अखिलेश कछवाहा) उपाध्यक्ष न.पा.परिषद मण्डला

(सुधीर मिश्रा) प्रभारी सदस्य राजस्व वित्त एवं लेखा विभाग

(गजानन नाफडे) मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मण्डला मण्डला,

संपादकीय

'ग्लोबल सिटिजन' की रेस

कई देशों द्वारा नियम कड़े करने और निवेश की रकम बढ़ाने के बावजूद, विदेशों में रहने और दूसरी नागरिकता पाने को लेकर अमीर भारतीयों का क्रेज बरकरार है। माल्टा की एडवाइजरी फर्म इमिग्रेंट इन्वेस्ट की 2026 की रिपोर्ट बताती है कि यूरोपीय देशों में पैसा निवेश कर वहां रहने का अधिकार पाने के मामले में भारत, चीन और खाड़ी देशों के साथ सबसे आगे है। लोग विदेशों में रहने या वहां की नागरिकता इसलिए चाहते हैं ताकि वे आसानी से दुनिया भर में घूम सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें, अपना बिजनेस बढ़ा सकें और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकें। यूरोप के इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन प्रोग्राम्स ने भाग लेने वाले देशों के लिए कुल मिलाकर 21.8 अरब यूरो से अधिक की कमाई की है। यह दिखाता है कि इस क्षेत्र में बढ़ते राजनीतिक विरोध के बावजूद, वहां रहने का अधिकार देने वाले इन रास्तों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। कई अमीर भारतीय परिवारों के लिए, ये कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय शिक्षा, आसान यात्रा और व्यवसाय या बेहतर लाइफस्टाइल के लिए विदेश में बसने का मौका देते हैं। दूसरी ओर निवेश के जरिए नागरिकता पाने के कार्यक्रम अब काफी महंगे होते जा रहे हैं। सालों तक, कैरिबियाई देशों ने दूसरा पासपोर्ट पाने के लिए सबसे सस्ते रास्ते दिए, जहां निवेश की शुरुआत कभी 1 लाख डॉलर से भी कम में हो जाती थी, लेकिन वह दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। कैरिबियाई कार्यक्रमों में अब ग्रेनाडा सबसे कम 2,35,000 डॉलर में नागरिकता दे रहा है, और उम्मीद है कि 2027 तक इस पूरे क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की रकम 2,50,000 डॉलर के आसपास तय हो जाएगी। कीमतें बढ़ने की वजह यह है कि वहां की सरकारें अपने कार्यक्रमों को प्रीमियम बनाना चाहती हैं और अंतरराष्ट्रीय नियामकों, खासकर यूरोपीय संघ की चिंताओं को दूर करना चाहती हैं। बढ़ती लागत के साथ-साथ, सरकारें आवेदकों की जांच-पड़ताल के नियम भी कड़े कर रही हैं। सेंट किट्स और नेविस ने अप्रैल 2026 में अनिवार्य बायोमेट्रिक नियम लागू किए हैं, जबकि ग्रेनाडा वहां 30 दिन रहना जरूरी करने पर विचार कर रहा है। प्रशासन ने गड़बड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, तय रकम से कम भुगतान करने पर 13 लोगों की नागरिकता छीन ली गई है और दो अधिकृत एजेंटों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब इन स्थापित कार्यक्रमों में बेहतर सुरक्षा मानकों और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का पालन करना आम बात हो जाएगी। नागरिकता चाहने वाले लोगों के लिए एक और बड़ी चुनौती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती सख्ती है। अमेरिका अब एंटीगुआ और बारबुडा और डोमिनिका के नागरिकों को बी-1/बी-2 विजिटर वीजा देने के लिए 5,000 से 15,000 डॉलर तक का बॉन्ड भरने को कह रहा है। ब्रिटेन ने सेंट लूसिया और त्रिनिदाद और टोबैगो के नागरिकों के लिए वीजा जरूरी कर दिया है, जबकि डोमिनिका ने 2023 में ही ब्रिटेन के लिए अपनी वीजा-मुक्त यात्रा का अधिकार खो दिया था। इन बदलावों से साफ है कि कुछ नागरिकता कार्यक्रमों के साथ मिलने वाले वीजा-मुक्त यात्रा के फायदों को हमेशा के लिए तय या गारंटीड नहीं माना जा सकता। जैसे-जैसे कैरिबियाई कार्यक्रम महंगे हो रहे हैं, बाजार में कम लागत वाले नए विकल्प सामने आने लगे हैं। साओ तोमे, प्रिंसिपे, नाउरू, बोत्सवाना ऐसे कार्यक्रम पर विचार कर रहे हैं जो सबसे किफायती हो सकते हैं। भारतीय निवेशकों के लिए यह ट्रेंड दिखाता है कि भले ही वैश्विक निवास और दूसरी नागरिकता के अवसर अभी भी आकर्षक हैं, लेकिन अब ये पहले से कहीं अधिक महंगे, अधिक नियमों से बंधे और जियोपॉलिटिकल बदलावों के अधीन होते जा रहे हैं।

बाल श्रम मुक्त समाज की ओर सामूहिक प्रयास

नन्हें हाथों में सपनों की रोशनी देने का संकल्प

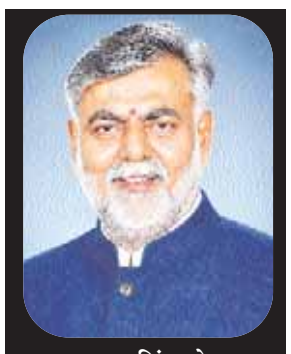

प्रहलाद सिंह पटेल
मंत्री
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
और श्रम विभाग

बचपन जीवन का वह स्वर्णिम काल होता है, जब आँखों में अनगिनत सपने पलते हैं, मन कल्पनाओं के आकाश में उड़ान भरता है और भविष्य की संभावनाएं आकार लेती हैं। यह वह समय है, जब बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, पैरों में खेल की चंचलता और चेहरे पर निश्छल मुस्कान।

समाज का एक कटु सत्य यह भी है कि आज भी अनेक बच्चों का बचपन अभाव, नशा, गरीबी और श्रम के बोझ तले दबा हुआ है। उनके नन्हें हाथ, जो कलम थामने के लिए बने थे, आज मजदूरी के कठिन कार्यों में उलझे दिखाई देते हैं। अनाथों की तरह उनका यह जीवन हमारे समाज की संवेदनहीनता और सामूहिक विफलता का परिणाम है।

हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला विश्व बाल श्रम दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा समाज बना पाए हैं, जहां उन्हें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार सहज रूप से प्राप्त हो सके? यदि नहीं, तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। बाल श्रम केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि मानवता के मूल्यों के विरुद्ध अपराध है। किसी भी बच्चे को उसकी उम्र से पहले जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए विवश करना उसके अधिकारों का हनन है। बच्चों का स्थान कारखानों, दुकानों, ढाबों और खतरनाक कार्यस्थलों पर नहीं, बल्कि विद्यालयों, खेल के मैदानों और परिवार के स्नेहिल वातावरण में होना चाहिए। हमारा श्रमोदय विद्यालय इस भावना का मूल स्वरूप हैं। कोई बच्चा जब मजदूरी करता है, तब केवल उसका वर्तमान ही नहीं, बल्कि उसका भविष्य भी प्रभावित होता है। उसके सपने सीमित हो जाते हैं और उसके विकास की संभावनाएं बाधित हो जाती हैं।

मध्यप्रदेश सरकार बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है-बंधुआ और बाल श्रम मुक्त मध्यप्रदेश। यह केवल एक प्रशासनिक उद्देश्य नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का व्यापक अभियान है। हम ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, जहां किसी भी बच्चे को मजबूरी में श्रम न करना पड़े और प्रत्येक बच्चे को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले।

बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। यह कानून बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान करता है। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम

प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि उस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि शिक्षा ही बच्चों को गरीबी और शोषण के चक्र से मुक्त कर सकती है। कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होता है, बाल श्रम जैसी चुनौती का मुकाबला समाज की सामूहिक भागीदारी से ही संभव है। हमारे आसपास यदि कोई बच्चा मजदूरी करता दिखाई दे, तो यह केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि वह कार्रवाई करे। हम सभी का यह नैतिक दायित्व है कि हम उस बच्चे को बेहतर जीवन की ओर ले जाने में सहयोग करें। समाज, उद्योग जगत, स्वयंसेवी संस्थाएं, शिक्षण संस्थान और जागरूक नागरिक-सभी को इस अभियान में सहभागी बनना होगा।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए 5 महत्वपूर्ण स्तंभ आवश्यक हैं.... कानूनी सहायता, पुनर्वास, कौशल विकास, जनजागरूकता और प्रशासनिक संवेदनशीलता। बच्चों को केवल श्रम से मुक्त करा देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और उज्ज्वल भविष्य के अवसर भी उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सरकार और मेरा विभाग पुनर्वास योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान कर रहा है।

वास्तव में गरीबी बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है। जब परिवार आर्थिक संकट से जूझते हैं, तब बच्चों को भी कम उम्र में जिम्मेदारियों का भार उठाना पड़ता है। इसलिए बाल श्रम के उन्मूलन का अर्थ केवल बच्चों को कार्य स्थलों से हटाना नहीं, बल्कि उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। रोजगार सृजन, स्वरोजगार योजनाएं और ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परिवार जब आत्मनिर्भर होंगे, तब बच्चों को मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे शिक्षा तथा अपने सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बाल श्रम को केवल सरकारी विषय न मानें, बल्कि सामाजिक चेतना का हिस्सा बनाएं। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जहां बच्चों के हाथों में औजार नहीं, बल्कि किताबें हों, उनकी आँखों में भय नहीं, बल्कि सपनों की चमक हो और उनके जीवन में संघर्ष नहीं, बल्कि अवसरों की अनंत संभावनाएं हों।

बाल श्रम और कौशल विकास के बीच अंतर को समझना भी आवश्यक है। कोई बच्चा यदि अपने परिवार की परंपरागत कला, व्यवसाय या पुश्तैनी कार्य में रुचि रखता है, तो वह उसकी जन्मजात प्रतिभा और कौशल का परिचायक हो सकता है। ऐसे में, उसकी इच्छा और रुचि के अनुरूप उस कौशल का ज्ञान प्राप्त करना उसके व्यक्तित्व विकास का माध्यम बन सकता है, बशर्ते यह उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और बचपन के अधिकारों को प्रभावित न करे। विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी बच्चे का बचपन मजबूरी में न बीते।

आइए, हम मिलकर ऐसा मध्यप्रदेश और ऐसा भारत बनाने का प्रयास करें, जहां हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। बाल श्रम मुक्त मध्यप्रदेश केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ऐसे विकसित, संवेदनशील और समृद्ध भारत की आधारशिला है, जिसकी नींव हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य पर टिकी हुई है। यही सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण का मार्ग है और यही हमारी सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी।

गुलाम कश्मीर में नरसंहार

आदित्य नारायण चौपड़ा
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

भारत की आजादी के तुरन्त बाद से ही जिस तरह पाकिस्तान ने सीमावर्ती रियासत जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण करके वहां की आम रियाया पर घनघोर अत्याचार और बर्बरता अपने कथित कबायलियों को भेज कर की थी उससे स्पष्ट हो गया था कि 15 अगस्त, 1947 को भारत को काट कर बने इस नये मुल्क पाकिस्तान के इरादे जम्मू-कश्मीर को अपना गुलाम बनाने के हैं। कबायलियों के वेष में पाकिस्तानी फौज के सैनिकों ने इस आक्रमण को विस्तृत रूप देना शुरू किया तो रियासत के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह के होश उड़े और उन्होंने 26 अक्तूबर, 1947 को अपनी पूरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया और इसके बाद भारतीय फौजों ने पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करना शुरू किया और उसे पीछे धकेलना जारी रखा परन्तु इसी बीच पाकिस्तान के खिलाफ भारत के राष्ट्रसंघ में पहुंच जाने की वजह से युद्ध विराम की घोषणा हो गई और दोनों फौजें अपने-अपने स्थान पर स्थिर हो गईं। अतः जम्मू-कश्मीर रियासत का एक-तिहाई से भी अधिक इलाका पाकिस्तान के कब्जे में रह गया जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर या गुलाम कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कह कर शेखी बघारता है। मगर इसके बाद से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के लिए जो नीतियां अपनाईं वे पूरी तरह मानवाधिकार विरोधी व आम लोगों को उनके लोकतान्त्रिक हकों से महरूम रखने वाली थीं। कहने के लिए पाकिस्तान ने यहां एक कश्मीर एसेम्बली का गठन किया जिसकी 45 सीटें हैं मगर धीरे-धीरे इस इलाके में अपने देश के दूसरे राज्यों के लोगों को बसाना शुरू किया, इस क्षेत्र का पूरा प्रशासन भी इन्हीं लोगों के हाथों में देने के मंसूबे बनाये।

पाकिस्तानी हुक्मरानों ने गुलाम कश्मीर में अपनी तानाशाही बरकरार रखने के लिए यहां की एसेम्बली में 12 सीटें भी गैर कश्मीरियों के लिए आरक्षित कर दी हैं जिससे इस क्षेत्र के प्रशासन के हर अंग पर उनका कब्जा रह सके और उनकी मर्जी के बिना न तो चुना हुआ कोई सदर बन सके और न प्रशासनिक मुखिया। पाकिस्तान की इन नीतियों के विरुद्ध क्षेत्र की जनता पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही है मगर हर बार पाकिस्तान की सरकार पुलिस व सेना का बल प्रयोग कर जन आन्दोलन को कुचल देती है। मगर पिछले दो दिनों से गुलाम कश्मीर में पाक फौज और पुलिस द्वारा जिस बर्बर और चंगेजी तरीके से यहां की आम जनता पर जुल्म ढहाये जा रहे हैं उसने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों के अनुसार 100 से अधिक नागरिकों को गोलियों का शिकार बना दिया गया है और 200 से अधिक को जख्मी कर दिया गया है। इसके बावजूद पूरे पाक अधिकृत कश्मीर की जनता सड़कों पर है और वह हुक्मरानों के अत्याचारों का विरोध कर रही है। इससे पता चलता है कि गुलाम कश्मीर में मानवाधिकारों का पूरी तरह हनन हो रहा है और प्रशासन दमनकारी चक्र चला रहा है।

दरअसल क्षेत्र की जनता ने एक संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी बना कर सरकार का विरोध करना शुरू किया। इस कमेटी में नागरिक समाज के सभी तबके के लोग शामिल हैं और वे लम्बे समय से बढ़ती महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी, भ्रष्ट प्रशासन और स्थानीय लोगों की राजनीतिक उपेक्षा के विरुद्ध आन्दोलन चला रहे हैं। इस आन्दोलन की प्रमुख मांग यह भी है कि एसेम्बली में गैर कश्मीरियों के लिए जो 12 सीटें आरक्षित की गई हैं वे समाप्त की जायें। मगर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी को ही प्रतिबन्धित करने की घोषणा कर दी जिसके खिलाफ आम लोगों में रोष पैदा हो गया और विगत मंगलवार से इस प्रतिबन्ध के खिलाफ जनान्दोलन शुरू करने की घोषणा की। मगर इस आन्दोलन के आह्वान के बाद बीते रविवार को एक्शन कमेटी के दो नेताओं का फौज व पुलिस ने अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी गई। इन नेताओं के शव गुलाम कश्मीर के शहर रावलकोट के अस्पातल में रखे हुए थे। आन्दोनकारियों ने तब रावलकोट अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां से फौज ने उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की जिसका प्रतिरोध करने पर उन पर गोलियों की बरसात बेतरतीब तरीके से की गई।

अतः बहुत साफ है कि गुलाम कश्मीर के मूल निवासियों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखने के उपाय प्रशासन द्वारा किये जा रहे हैं जिसका संज्ञान दुनिया के उन देशों सहित राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार संरक्षक संगठन द्वारा भी लिया जाना चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें नागरिकों का मौलिक हक मानता हैं। अभी तक केवल ब्रिटेन की संसद के 30 सदस्यों ने पाकिस्तान विरोधी प्रस्ताव रखा है। जहां तक भारत का सवाल है तो वह शुरू से ही मानता है पूरा जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का अटूट हिस्सा है, इसी कारण से उसने अपनी जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें गुलाम कश्मीर के लोगों के लिए खाली छोड़ रखी हैं अब यह अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी को ही देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढहा रही है और उनके नागरिक अधिकारों को कुचल रही है। दूसरी तरफ भारत के जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारतीय संविधान के तहत मिले नागरिकों को अधिकारों से पूरी तरह लैस कर दिया गया है और उन्हें अपने विकास के लिए सभी प्रकार के साधन मुहैया कराये जा रहे हैं।

जीवन धारा: ऐसा ज्ञान बेकार है जो करुणा न जगाए

जीवन का मूल्य इस बात में नहीं कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया है, बल्कि इस बात में है कि हमारे कारण कितने लोगों का दुख कम हुआ। मनुष्य इस संसार में जन्म केवल अपने लिए नहीं लेता। अगर उसका समस्त ज्ञान, सारी विद्वता और उपलब्धियां केवल उसके अहंकार की दीवारें ऊंची करने में लग जाएं, तो वह ज्ञान नहीं, सिर्फ बोझ है। मैं उस विद्या को अधूरी मानता हूं, जो मनुष्य के भीतर करुणा न जगाए। मैंने अपने जीवन में देखा है कि समाज विद्वानों का तो सम्मान करता है, मगर दुखियों की पीड़ा सुनने से बचता है। लोग शास्त्रों के पन्ने तो उलटते हैं, किंतु मनुष्य के हृदय को पढ़ने का प्रयास नहीं करते। मुझे सदैव यह लगा कि यदि शिक्षा हमें मनुष्य के दुख के प्रति संवेदनशील नहीं बनाती, तो वह केवल शब्दों का संग्रह है, प्रकाश नहीं। जब मैं छोटा था, तब मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा। मैंने उन रातों को जिया है, जब दीपक जलाने के लिए हमारे यहां तेल भी नहीं हुआ करता था और सड़क की मद्धिम रोशनी में पढ़ना पड़ता था। उस समय मैंने जाना कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य क्या है। समाज में मैंने अनेक लोगों को देखा, जो धर्म और परंपरा की बड़ी-बड़ी बातें तो करते थे, किंतु एक विधवा के आंसू उन्हें विचलित नहीं करते थे। वे शास्त्रों की रक्षा में इतने व्यस्त हो गए थे कि मनुष्यता की रक्षा करना तक भूल गए। तब मेरे भीतर यह प्रश्न बार-बार उठता था कि अगर किसी व्यवस्था के कारण मनुष्य का जीवन अपमान और पीड़ा में डूब जाए, तो उस व्यवस्था की पवित्रता का क्या अर्थ रह जाता है? धर्म वह नहीं हो सकता, जो करुणा को कुचल दे। मनुष्य का कर्तव्य केवल सत्य को जानना नहीं, बल्कि अन्याय के सामने खड़े होने का साहस रखना भी है।

मेरे लिए जीवन का उद्देश्य पीड़ित मनुष्य की पीड़ा को थोड़ा कम कर देना है। यदि आपके कारण किसी निराश व्यक्ति को आशा मिले, किसी भूखे को भोजन मिले, अशिक्षित को शिक्षा मिले, अपमानित को सम्मान मिले, तो समझिए आपका जीवन सार्थक हुआ। सच्चा ज्ञान वही है, जो सिखाए कि हर मनुष्य का दुख हमारे अपने दुख से अलग नहीं है। हम सब एक-दूसरे से जुड़े हैं। मनुष्य चाहे कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, उसके जाने के बाद लोग उसके शब्दों को नहीं, उसके व्यवहार को याद रखते हैं। वे यह याद रखते हैं कि उसने कितनों के आंसू पोंछे, कितनों को सहारा दिया और कितनों के लिए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई।

शिक्षा का अर्थ है-अपने भीतर ऐसी दृष्टि विकसित करना, जिससे हम हर मनुष्य में अपनी ही आत्मा का अंश देख सकें। यदि कभी तुम्हें यह निर्णय लेना पड़े कि अपनी प्रतिष्ठा या किसी पीड़ित की सहायता करने में से महत्वपूर्ण क्या है, तो सदैव मनुष्यता को चुनना। समाज की प्रशंसा क्षणिक होती है, किंतु किसी पीड़ित मनुष्य की आंखों में लौटती हुई आशा अमर होती है। वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा।

जीवन की सार्थकता ज्ञान के संचय में नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को दूर करने में है। सच्चा मनुष्य वही है, जो शास्त्रों के पन्ने पलटने के बजाय इन्सानी दिल को पढ़े और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखे। सदैव प्रतिष्ठा से ऊपर मानवता और सेवा को चुनें। आपके जाने के बाद लोग आपकी उपलब्धियों को नहीं, बल्कि आपकी संवेदनशीलता को याद रखेंगे।

नामांकन निरस्तीकरण की अस्पष्टता और लोकतंत्र की चुनौती

क्या चुनाव लड़ने का अधिकार प्रशासनिक विवेक पर निर्भर हो सकता है?

भूपेन्द्र गुप्ता
लेखक स्वतंत्र विश्लेषक हैं

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, सरकारें बनाती है और उन्हें बदलती भी है। किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यह मूल सिद्धांत तब प्रश्नों के घेरे में आ जाता है जब किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले ही नामांकन निरस्त कर प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। हाल के वर्षों में नामांकन पत्रों और शपथपत्रों (फार्म 26) से जुड़े विवादों ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़ा किया है-क्या चुनाव लड़ने का अधिकार स्पष्ट कानूनी मानकों से संचालित हो रहा है, या फिर यह अधिकारियों की व्याख्या और विवेक पर निर्भर होता जा रहा है? यह प्रश्न किसी एक दल या व्यक्ति का नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता और विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है।

कानून का उद्देश्य क्या है?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इस धारा का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही उम्मीदवार चुनाव लड़ें जो कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हों और जिनके नामांकन में कोई गंभीर कानूनी दोष न हो। साथ ही यह धारा स्पष्ट रूप से यह भी संकेत देती है कि तकनीकी या मामूली त्रुटियों के आधार पर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की भावना भी यही कहती है कि जहाँ संदेह हो, वहाँ निर्णय चुनाव के पक्ष में होना चाहिए, न कि बहिष्कार के पक्ष में। यही कारण है कि न्यायालयों ने समय-समय पर रिटर्निंग आफीसर की भूमिका को सीमित बताया है। रिटर्निंग आफीसर कोई न्यायालय नहीं है और न ही वह विस्तृत तथ्यात्मक जांच करने वाली एजेंसी है। उसका कार्य प्रारंभिक परीक्षण करना है, न कि जटिल कानूनी विवादों का अंतिम निपटारा करना।

शपथपत्र और मतदाता का अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय ने एडीआर तथा बाद के अनेक निर्णयों में मतदाता के जानने के अधिकार को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना है। इसी सोच के आधार पर उम्मीदवारों के लिए संपत्ति, देनदारियों, आपराधिक मामलों और शैक्षणिक योग्यता का खुलासा अनिवार्य किया गया। फार्म 26 इसी पारदर्शिता का साधन है। लेकिन यहीं से एक जटिल प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि कोई उम्मीदवार शपथपत्र प्रस्तुत करता है, किंतु उसके खुलासों की पर्याप्तता या पूर्णता पर विवाद उठता है, तो क्या रिटर्निंग अधिकारी उसी समय यह तय कर सकता है कि जानकारी पर्याप्त है या नहीं? सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का संकेत यही रहा है कि शपथपत्र की सत्यता और पर्याप्तता का अंतिम परीक्षण न्यायिक मंच पर होना चाहिए, न कि स्क्रूटनी की सीमित प्रक्रिया में।

परिमल नाथवानी और मीनाक्षी नटराजन के प्रकरण

इसी संदर्भ में दो चर्चित प्रकरण विशेष महत्व रखते हैं-झारखंड में परिमल नाथवानी का मामला और मीनाक्षी नटराजन से जुड़ा विवाद। परिमल नाथवानी के मामले में आरोप लगाया गया कि कुछ जानकारियों का पूरा खुलासा नहीं किया गया। इसके बावजूद नामांकन को वैध माना गया। इसके पीछे प्रमुख तर्क यह था कि शपथपत्र दाखिल किया जा चुका है और उसकी पर्याप्तता अथवा सत्यता का विस्तृत परीक्षण स्क्रूटनी के दौरान नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर मीनाक्षी नटराजन के मामले में शपथपत्र संबंधी आपत्तियों के आधार पर नामांकन निरस्तीकरण का प्रश्न सामने आया। यहाँ मूल प्रश्न यह नहीं है कि कौन-सा उम्मीदवार सही था और कौन-सा गलत। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या दोनों मामलों में समान कानूनी सिद्धांत लागू किए गए? यदि एक मामले में कथित अपूर्ण खुलासे को नामांकन निरस्तीकरण का आधार नहीं माना जाता और दूसरे मामले में समान प्रकृति की कमी को गंभीर दोष मान लिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से विधिक समानता और न्यायिक स्थिरता पर प्रश्न उठेंगे। कानून की विश्वसनीयता केवल उसके अस्तित्व से नहीं बनती। उसकी विश्वसनीयता इस बात से बनती है कि वह समान परिस्थितियों में समान रूप से लागू हो।

लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा

बहस का केंद्र किसी विशेष उम्मीदवार का भाग्य नहीं होना चाहिए। वास्तविक चिंता इससे कहीं बड़ी है। यदि अपूर्ण खुलासा, अपर्याप्त जानकारी और सारभूत दोष की स्पष्ट परिभाषा नहीं होगी, तो भविष्य में कोई भी उम्मीदवार विवादों और व्याख्याओं के आधार पर चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार केवल उम्मीदवार का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। यह मतदाताओं का भी अधिकार है कि वे अधिकतम विकल्पों में से अपना प्रतिनिधि चुन सकें। जब किसी उम्मीदवार का नामांकन निरस्त किया जाता है, तब केवल एक व्यक्ति प्रक्रिया से बाहर नहीं होता बल्कि मतदाताओं के सामने उपलब्ध एक विकल्प भी समाप्त हो जाता है। इसलिए नामांकन निरस्तीकरण की शक्ति को अत्यंत सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए।

क्या झूठी जानकारी को अनदेखा किया जाए?

इस तर्क का यह अर्थ नहीं है कि उम्मीदवारों को गलत जानकारी देने की छूट मिल जानी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर तथ्य छिपाता है या झूठा शपथपत्र देता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनावी पारदर्शिता लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि उस कार्रवाई का मंच कौन-सा होना चाहिए?

क्या सीमित समय में कार्यरत

रिटर्निंग अधिकारी जटिल तथ्यों की जांच कर अंतिम निष्कर्ष निकाले, या फिर न्यायालय साक्ष्यों और विस्तृत सुनवाई के आधार पर निर्णय करे? लोकतांत्रिक न्यायशास्त्र का सामान्य झुकाव दूसरे विकल्प की ओर रहा है। इसका कारण यह है कि गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवार के विरुद्ध बाद में कार्रवाई की जा सकती है, किंतु अनुचित रूप से निरस्त किए गए नामांकन की क्षति अक्सर अपूरणीय होती है। इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका मिलकर स्पष्ट दिशानिर्देश विकसित करें।

यह स्पष्ट होना चाहिए कि- कौन-सी त्रुटि केवल तकनीकी त्रुटि है, कौन-सी कमी अपूर्ण खुलासा मानी जाएगी,

कौन-सी स्थिति सारभूत दोष होगी

और किन परिस्थितियों में नामांकन निरस्त किया जा सकता है। जब तक यह स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक विभिन्न राज्यों और विभिन्न मामलों में अलग-अलग व्याख्याएँ सामने आती रहेंगी। परिमल नाथवानी और मीनाक्षी नटराजन के प्रकरण हमें एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रश्न की ओर ले जाते हैं। क्या भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार पर्याप्त रूप से संरक्षित है, या वह अभी भी प्रशासनिक विवेक और कानूनी अस्पष्टता के बीच झूल रहा है?

लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि कोई विवादित उम्मीदवार चुनाव लड़ ले। सबसे बड़ा खतरा यह है कि कोई वैध उम्मीदवार अस्पष्ट नियमों और असंगत व्याख्याओं के कारण चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया जाए।

आखिरकार लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि उम्मीदवारों का अंतिम निर्णय जनता करे। कानून का उद्देश्य चुनावी प्रतिस्पर्धा को सीमित करना नहीं, बल्कि उसे निष्पक्ष, पारदर्शी और समान अवसरों पर आधारित बनाना है। यदि यह सिद्धांत कमजोर पड़ता है, तो केवल किसी एक उम्मीदवार का अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा भी संकट में पड़ जाती है।एक ही परिस्थिति में एक पुरुस्कृत और दूसरा तिरस्कृत हो यह न्याय चेतना को अपाहिज बनाता है।

यूरोप में तैनात विमानों-युद्धपोतों में बड़ी कटौती की तैयारी कर रहा अमेरिका

वाशिंगटन डीसी।

अमेरिका यूरोप में नाटो के लिए तैनात अपने सैन्य संसाधनों में बड़ी कटौती की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के तहत लड़ाकू विमान, निगरानी विमान, टैंकर, युद्धपोत और अन्य अहम सैन्य उपकरणों की संख्या घटाई जाएगी। वॉशिंगटन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यूरोपीय देशों और कनाडा को महाद्वीप की सुरक्षा में अधिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अमेरिका यूरोप में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के अभियानों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विमानों और युद्धपोतों की संख्या में बड़ी कटौती करने की योजना बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यूरोप के दो वरिष्ठ अधिकारियों और जून की शुरुआत में सहयोगी देशों के साथ साझा किए गए एक लिखित दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस प्रस्तावित कटौती का असर नाटो के अभियानों में इस्तेमाल होने वाले अहम सैन्य संसाधनों पर पड़ेगा। इनमें लड़ाकू विमान, निगरानी विमान, ईंधन भरने वाले टैंकर विमान और नौसैनिक तैनाती शामिल हैं। प्रस्तावित कटौती के तहत एफ-16 और एफ-15ई लड़ाकू विमानों की संख्या

करीब 150 से घटाकर 100 की जाएगी। समुद्री निगरानी विमानों की संख्या 26 से घटाकर 15 कर दी जाएगी। इसके अलावा, यूरोप के लिए उपलब्ध सभी आठ हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों को हटा लिया जाएगा। इसमें मिसाइल दागने वाली एक पनडुब्बी और एक विमानवाहक पोत को भी दूसरी जगह भेजना शामिल है। इसके साथ ही कई युद्धपोतों और विमानवाहक पोत मिशनों से जुड़े दर्जनों विमानों को भी हटाया जाएगा। यूरोप की रक्षा के लिए पहले से तैनात दो बमवर्षक समूहों में से एक को भी दूसरी जगह भेजे जाने की संभावना है। अमेरिकी अखबार के अनुसार, इन बदलावों से नाटो की लंबी दूरी तक हमला करने और निगरानी करने की क्षमता सीमित हो सकती है। इसमें रूसी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर लंबी दूरी की मिसाइल हमले करना भी शामिल है। पेंटागन ने अभी तक इस कटौती की समय-सीमा की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है। उसने आंकड़ों पर टिप्पणी करने से इनकार किया और केवल यूरोप में अपनी सैन्य प्रतिबद्धताओं को समायोजित करने संबंधी अमेरिकी यूरोपीय कमान के सामान्य बयान का हवाला दिया।

नाटो 3.0% रणनीति का हिस्सा

अमेरिका की यूरोपीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने नाटो सहयोगियों को सूचित कर दिया है कि वह 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और %नाटो 3.0% की परिकल्पना के तहत व्यापक जिम्मेदारी साझा करने की नीति के हिस्से के रूप में नाटो फोर्स मॉडल में अपने योगदान को %उचित आकार% देगा।

यूरोपीय देशों को उठानी होगी ज्यादा जिम्मेदारी : अमेरिका

अमेरिकी वायुसेना के जनरल एलेक्सस जी. ग्रिनकेविच अमेरिकी यूरोपीय कमान के कमांडर हैं। उन्होंने कहा, नाटो फोर्स मॉडल में अमेरिकी सैन्य बलों पर अत्यधिक और अनुचित निर्भरता रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बदलावों का मकसद नाटो की रक्षा योजना को अधिक यथार्थवादी बनाना है। यह पहल अमेकिता ते युद्ध नीति मामलों के लिए अवर सचिव एल्ब्रिज कोल्बी के नेतृत्व में की जा रही है। उनका तर्क है कि अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों और कनाडा को महाद्वीप की पारंपरिक रक्षा की अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर यूएस को फटकार

यूएन ने याद दिलाए कायदे-कानून

नई दिल्ली।

ओमान के तट पर कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को दूसरी बार तलब किया है। भारत ने अमेरिकी राजनयिक जेसन मीक्स को तलब किया। गौरतलब है कि गुरुवार को भी अमेरिकी नौसेना ने ओमान तट के पास 20 भारतीय क्रू मेंबर वाले एक जहाज पर हमला किया था। इसके पहले जब अमेरिकी नेवी के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी तब भी भारत ने अमेरिकी राजनयिक जेसन मीक्स को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई थी। भारत ने कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों को बेहद चिंताजनक बताया है और इस मामले को अमेरिका के सामने सख्ती से उठाया है। इस बीच अमेरिकी नौसेना के हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे संगठनों और देशों ने अमेरिकी कार्रवाई की तीखी आलोचना की है और इसे अस्वीकार्य बताया है। अमेरिकी दादागीरी के सामने तनकर खड़े होते हुए अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर असर डालने वाली सभी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समुद्र में व्यक्ति की सुरक्षा का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं यूएन ने कहा कि वो आईएमओ के बयान से इत्तेफाक रखता है। बुधवार को अमेरिका ने पलाऊ के झंडे वाले एक टैंकर पर हमला किया था। इस टैंकर का नाम एमटी सेटेबेलो है। अमेरिका नौसेना ने सेटेबेलो पर मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी।

भारत के बाद अब चीन दौरे पर जाएंगे नेपाल के विदेश मंत्री, वांग यी से करेंगे मुलाकात

काठमांडू

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल इस रविवार को चीन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की घोषणा की है। मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, खनाल 14 से 17 जून 2026 तक चीन के दौरे पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उन्हें इस यात्रा के लिए न्योता दिया है। बीजिंग में शिशिर खनाल और वांग यी के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस दौरान दोनों नेता नेपाल और चीन के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे आपसी हित के मुद्दों और सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बात करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान खनाल चीन के कुछ अन्य उच्च स्तरीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। शिशिर खनाल ने मार्च के अंत में विदेश मंत्री का पद संभाला था। पद संभालने के बाद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। वे पिछले हफ्ते पांच जून को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर दिल्ली पहुंचे थे। भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी। भारत में हुई बैठक में दोनों विदेश मंत्रियों ने आपसी संबंधों की समीक्षा की। इसमें विकास कार्य, कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी रिश्तों जैसे विषय शामिल थे। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक और ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में हो रही प्रगति पर संतोष जताया। दोनों देश अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सहमत हुए। इस दौरे पर भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता समझौते (रु) को लागू करने की प्रक्रिया पूरी हुई। यह समझौता सीमा पार होने वाले अपराधों की जांच और कानूनी कार्यवाही में मदद करेगा। इसके अलावा, भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य केंद्र और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपीं। ये सभी निर्माण कार्य 2015 के भूकंप के बाद भारत की मदद से पूरे किए गए हैं।

बांग्लादेश ने भगवान राम की विशाल प्रतिमा परियोजना पर लगाई रोक, धार्मिक स्वतंत्रता पर उठे सवाल

ढाका

बांग्लादेश के अधिकारियों ने भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के निर्माण को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह प्रतिमा गाइबांधा जिले के पलाशबारी उपजिला में स्थित श्री श्री राधा गोविंदा और काली मंदिर में लगाई जा रही थी। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, मंदिर के सलाहकार श्याममल कुमार महंत ने गुरुवार शाम मंदिर सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की। इस फैसले से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आलोचकों का आरोप है कि परियोजना का विरोध करने वाले इस्लामी समूहों के दबाव में इसे निलंबित किया गया है। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने राम मंदिर के निर्माण के इर्द-गिर्द हो रही धमकियों, उकसावे और शत्रुतापूर्ण बयानबाजी की कड़ी निंदा की। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस देश में कई लाख मस्जिदें मौजूद हैं और जिनका निर्माण जारी है। वहां एक अकेले हिंदू पूजा स्थल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। नसरीन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में कई लाख मस्जिदें हैं और

पूरे देश में नई मस्जिदें बनती जा रही हैं। तो फिर एक राम मंदिर या भगवान राम की मूर्ति के निर्माण का इतना विरोध क्यों हो रहा है? अगर धार्मिक स्वतंत्रता सचमुच सबके लिए है, तो यह अल्पसंख्यकों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए, न कि केवल बहुसंख्यकों पर। उन्होंने आगे कहा पालाशबारी, गाइबांधा में निर्माणाधीन राम मंदिर के खिलाफ मिल रही धमकियां, उकसावे और नफरत भरी बयानबाजी बेहद चिंताजनक है। किसी भी व्यक्ति या समूह को सिर्फ इसलिए किसी दूसरे समुदाय के पूजा स्थल को गिराने का अधिकार नहीं मिल जाता क्योंकि उन्हें वह पसंद नहीं है। कानून के शासन वाले राय में धार्मिक मतभेदों का समाधान हिंसा या बर्बरता से नहीं किया जा सकता। नसरीन ने इस बात पर जोर दिया कि पलाशबारी में हिंदू मंदिरों पर हमलों और मूर्तियों को तोड़ने के इतिहास को देखते हुए स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जिससे हिंदी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस करता है। नसरीन ने सवाल उठाया दुनिया भर के कई मुस्लिम बहुल देशों में - जिनमें इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और ओमान शामिल हैं। बड़े-बड़े हिंदू मंदिर हैं। इन देशों में मंदिरों का अस्तित्व राय के लिए खतरा नहीं माना जाता। तो फिर बांग्लादेश में एक मंदिर के निर्माण को कुछ मुसलमानों के अस्तित्व का संकट क्यों बताया जा रहा है?इसी बीच, बांग्लादेशी समाचार पत्र ब्लिट्ज के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने भी इस्लामी चरमपंथी समूहों के दबाव के बीच मंदिर निर्माण के रुकने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। चौधरी ने एक्स पोस्ट में लिखा, बांग्लादेश के गाइबांधा जिले में चल रहे सनातन परिसर के अधिकारियों ने स्थानीय जिहादी और इस्लामी समूहों के व्यापक विरोध के बीच सभी गतिविधियों को निलंबित करने और भगवान राम की मूर्ति का निर्माण रोकने की घोषणा की है।

रक्षा सचिव के बाद सशस्त्र बल के मंत्री अल कार्न्स का भी इस्तीफा, बजट पर बढ़ा विवाद

लंदन। ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के मंत्री अल कार्न्स ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने रक्षा निधि और सैन्य तैयारियों को लेकर गहरी चिंताओं का हवाला दिया। इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा खर्च को लेकर प्रशासन के भीतर मौजूद मतभेद और भी उजागर हो गए हैं। कार्न्स का जाना पूर्व रक्षा सचिव जॉन हीली के इस्तीफे के बाद हुआ है, जिनका प्रधानमंत्री के साथ सरकार के रक्षा बजट को लेकर मतभेद था। हीली का तर्क था कि स्टारमर सरकार ने प्रस्तावित सैन्य खर्च देश की रक्षा के लिए जरूरी राशि से काफी कम है। कार्न्स ने अपने इस्तीफे का एलान एक्स पर किया। उन्होंने लिखा कि सरकार ब्रिटेन के सशस्त्र बलों को पर्याप्त समर्थन देने में असफल रही है। उन्होंने लिखा, ब्रिटेन की सेवा करने वालों को काम करने के लिए जरूरी उपकरण और काम पूरा होने पर उनके साथ खड़े रहने की वफादारी देना हमारा कर्तव्य है। हम इन दोनों में विफल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने सरकार में अपना पूरा समय यही बात रखने में बिताया है।

भारतीय आम को लगा बड़ा झटका, जापान के बाद अब नेपाल ने भी लगाया बैन, करोड़ों के नुकसान की आशंका

नई दिल्ली

जापान के बाद अब पड़ोसी देश नेपाल ने भी भारत से आने वाले आम और अन्य फलों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने यह सख्त कदम तब उठाया, जब सीमा पर क्वारंटाइन (संगरोध) निरीक्षकों ने भारतीय फलों की खेप में खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों की मात्रा तय सीमा से काफी अधिक पाई। नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय द्वारा लगाया गया यह प्रतिबंध अप्रैल-मई से ही लागू है। गर्मियों के इस मुख्य सीजन में इस फैसले से भारत के आम निर्यात को बड़ा झटका लगा है।

इससे भारत की प्रीमियम किस्में जैसे अल्फांसो, दशहरी, चौसा, लंगड़ा और केसर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। इस पाबंदी से नेपाल के स्थानीय व्यापारी भी परेशान हैं। जनकपुरधाम फल और सब्जी व्यवसायी संघ के महासचिव भुवनेश्वर पुर्बे ने कहा कि देश में आम की मांग सिर्फ स्थानीय उत्पादन से पूरी नहीं हो सकती। आयात रुकने से बाजार में आम की भारी किल्लत हो जाएगी। उन्होंने सरकार से पूरी तरह बैन लगाने के बजाय गुणवत्ता जांच के बाद भारतीय फलों को अनुमति देने की अपील की है। दूसरी ओर, नेपाली अधिकारी इसे अपने घरेलू बाजार के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। इस फैसले से स्थानीय किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिकों को केमिकल-मुक्त, सुरक्षित फल मिल सकेंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने ही जापान ने भी भारत के ट्रीटमेंट सेंटरों में कीट-नियंत्रण (पेस्ट-कंट्रोल) प्रक्रियाओं में कमी पाए जाने पर भारतीय आम के आयात पर रोक लगा दी थी।

फिलीपींस में भूकंप के बाद गहराया खाद्य संकट

मनीला। दक्षिणी फिलीपींस में आए भूकंप को चार दिन बीच चुके हैं, लकिन वहां के हालात आज भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। हजारों लोगों को राहत शिविर में रहना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपदा प्रभावित इलाकों में अब लोगों को खाने और पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। फिलीपींस के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों की मदद के लिए पहुंच पाना प्रशासन के लिए काफी कठिन हो चला है। भूकंप के कारण कई मुख्य सड़कें या तो बाधित हो गई हैं या फिर खराब हो गई हैं। 7.8 तीव्रता के भूकंप ने कई गांवों का संपर्क भी तोड़ दिया है। इसी कारण से प्रशासन को फंसे हुए लोगों की मदद करने में भी समस्या आ रही है। इस प्राकृतिक आपदा में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक सारंगानी का ग्लान कस्ब है। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में राहत कार्य के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी सिलसिले में इलाके के मेयर विक्टर जेम्स याप ने ने सरकार से वायुसेना के हेलीकॉप्टर भेजने की बात कही है। विक्टर का कहना है कि उनके क्षेत्र के 31 में से 10 गांव अभी भी भूस्खलन के कारण पूरी तरह के कटे हुए हैं, जिस कारण से वहां राहत सामग्री पहुंचाने में कठिनाई हो रही है।

फिल्म/टीवी मनोरंजन

उर्वशी रौतेला को चाहिए संस्कारी लड़का

किसी भी रिश्ते में बाहरी आकर्षण से ज्यादा अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के लिए पारिवारिक मूल्य मायने रखते हैं। उर्वशी मानती हैं कि उन्हें पसंद करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जीवनसाथी के रूप में वह ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगी जो अच्छे संस्कारों वाला हो। यही वजह है कि वह फिल्म इंडस्ट्री के बजाय अभिनय जगत से बाहर के किसी शख्स को अपना हमसफर बनाने के पक्ष में हैं। उर्वशी कहती हैं कि जो इंसान मुझे नजदीकी से जानेगा, उसे मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। कई लड़के हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मायने नहीं रखता है कि लड़का कैसा दिखता है। मेरे लिए पारिवारिक मूल्य मायने रखते हैं। वह कितना जिम्मेदार है, अपनी कही बातों पर कितना खरा उतरता है, यह देखना भी जरूरी है। कई लड़के होते हैं, जो किसी भी तरह का कमिटमेंट यानी वादा करने से डरते हैं, लेकिन जिन्हें अच्छे पारिवारिक संस्कार मिले होंगे, वे इन चीजों से नहीं डरेंगे।

क्या उर्वशी फिल्म इंडस्ट्री से ही अपने लिए हमसफर चुनेंगी या इंडस्ट्री के बाहर से?

इस पर वह कहती हैं कि मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री से अगर कोई होगा तो मेरे परिवार वाले ही उसे नहीं अपनाएंगे। वे चाहते हैं कि अभिनय के पेशे के बाहर से कोई हो। मैं भी यही चाहती हूं, क्योंकि इसे पेशे से बाहर का अगर कोई होगा तो उसके साथ घर जाने पर बातें करने के लिए कई और चीजें होंगी।

उर्वशी रौतेला हाल ही में ओटीटी सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश पार्ट 2 में नजर आई थीं। उर्वशी ने इसमें पूनम मिश्रा की भूमिका निभाई थी। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लाइफ पार्टनर और जिंदगी में किस एक्टर को वो अपना हमसफर बनाना चाहेंगी इस पर बात की।

अछा हुआ तुमने इंडस्ट्री छोड़ दी, वरना..., भाग्यश्री से बोली थीं जूही चावला, एक्ट्रेस ने बताया क्यों

भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि जब उन्होंने मैंने प्यार किया की रिलीज के बाद मेनस्ट्रीम फिल्में छोड़ीं तो बड़े-बड़े डायरेक्टर्स को झटका लगा था। यश चोपड़ा ने उन्हें डांटा था। वहीं, जूही चावला ने भाग्यश्री से कहा था कि अछा हुआ जो उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। पर क्यों? एक्ट्रेस भाग्यश्री ने सलमान खान स्टारर मैंने प्यार किया से एक्टिंग डेब्यू किया था, और रातोंरात स्टार बन गई थीं। उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। यश चोपड़ा से लेकर मनमोहन देसाई तक हर बड़ा फिल्ममेकर भाग्यश्री के साथ काम करना चाहता था। लेकिन एक फैसले ने भाग्यश्री के करियर की दिशा ही मोड़ दी। वह उनके लिए भारी पड़ गया, पर इससे कई एक्ट्रेसेस को फायदा हो गया था। भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में अपने स्टारडम से लेकर सिर्फ पति संग फिल्में करने के फैसले और उस वक्त के बारे में बात की, जब जूही चावला ने उनसे कहा था कि अछा हुआ, जो तुमने इंडस्ट्री छोड़ दी। भाग्यश्री ने 20 साल की उम्र में एक्टिंग से दूरी बना ली थी और वह शादी-परिवार पर फोकस करने लगी थीं। भाग्यश्री ने बिजनेसमैन हिमालय दासानी से शादी कर ली थी। मैंने प्यार किया साल 1989 में रिलीज हुई थी, और भाग्यश्री ने उसी साल शादी कर ली। चूंकि फिल्म की रिलीज और शूटिंग में तीन साल का गैप था, तो तब तक भाग्यश्री प्रेगनेंट भी हो चुकी थीं और पहले बचे की मां बनने वाली थीं। भाग्यश्री ने इस बारे में वैराइटी इंडिया से कहा, मैं बहुत छोटी थी और प्यार में थी। मैं शादी करके अपना परिवार बसाना चाहती थी। मुझे लगता है कि हर लड़की का यही सपना होता है। जब फिल्म रिलीज हुई, तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और मैं प्रेगनेंट भी थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग और रिलीज के बीच एक साल का अंतर था। मैं बहुत छोटी थी और प्यार में थी। मैं शादी करके अपना परिवार बसाना चाहती थी। मुझे लगता है कि हर लड़की का यही सपना होता है।

जैकलीन फर्नांडिस केस : सुको जज प्रशांत कुमार मिश्रा ने खुद को सुनवाई से किया अलग

200 करोड़ रुपए के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है। 200 करोड़ रुपए के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब यह मामला नई पीठ के समक्ष रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकरण से जुड़े एक अन्य मामले में उनका बेटा वकील है। ऐसे में निष्पक्षता ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग करने का फैसला किया है अब इस मामले की सुनवाई दूसरी पीठ करेगी। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 24 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। अब नई बेंच यह तय करेगी कि जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर आगे क्या रुख अपनाया जाए। जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के 30 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में जैकलीन, सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉल और 14 अन्य आरोपितों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ एक्ट्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। वेलकम टू वद जंगल% एक्ट्रेस जैकलीन का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों और सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ आरोप तय किया जाना उचित नहीं है, जिसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की। यह पूरा मामला 200 करोड़ की जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

तामिया और पातालकोट में जनजातीय लोगों के जड़ी बूटियों के ज्ञान को संरक्षित करने की जरूरत : डॉ दिवाकर सिंह राजपूत

नरसिंहपुर, स्वतंत्र मत।

भारिया जनजाति के लोग प्रकृति के बीच जीवन को संवारते हैं. वह लोग प्रकृति को अपने परिवार और आराध्य की तरह सम्मान देते हैं. शायद इसीलिये उनको जड़ी बूटियों की गहन जानकारी होती है. उनका चिकित्सीय ज्ञान अद्भुत है. भारतीय ज्ञान परम्परा की उस अनमोल धरोहर को संरक्षित करने की बहुत जरूरत है. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनकी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखते हुए उनके ज्ञान भंडार का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करें. यह विचार दिये प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत ने भारतीय ज्ञान परम्परा पर केन्द्रित एक कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता करते हुए. इंडियन काउन्सिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के अंतर्गत और रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा आयोजित कार्यशाला का आयोजन तामिया में किया गया. संस्कृत, प्राच्य भाषा एवं भारतीय ज्ञान परम्परा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य विषय था- भारिया जनजाति की चिकित्सीय ज्ञान परम्परा और ज्योतिषीय आस्था का अंतर्संबंध. कार्यक्रम समन्वयक डॉ संजय दुबे ने विषय की प्रस्तावना पर प्रकाश डाला. विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रो राजेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाहा, श्री शिवदास खरपुसे, पवन श्रीवास्तव सहित अनेक शिक्षाविद एवं पाताल कोट के वैद्य प्रताप सिंह, घन सिंह, सरपंच रमेश भारती, राजू,पत्रकार नवीन दत्ता आदि लोगों ने सहभागिता की. डॉ संजय दुबे ने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से जानकारी एकत्रित करते हुए उनके ज्ञान और ज्योतिषीय आस्था के बीच अंतर्संबंध को खोजने का शोधपरक प्रयास किया जाएगा. प्रोफेसर राजेन्द्र मिश्रा ने शोध की रूपरेखा तैयार करने की बारीकियों की जानकारी दी. कार्यशाला के द्वितीय सत्र में स्थानीय वैद्य, जनप्रतिनिधि, सहयोगी, शिक्षा विद और जनजाति लोगों ने अपने अपने विचार रखे. भारिया जनजाति के वैद्य आदि ने जड़ी बूटियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया और उनके उपयोग बताये. सभी प्रतिभागियों का मानना है कि इस अद्भुत ज्ञान का संरक्षण करना बहुत जरूरी है।

कलेक्टर द्वारा मछुआ समिति के सदस्यों के साथ हुई बैठक

तियरा तालाब का प्रोजेक्ट तैयार

पर्यटन एवं मछली उत्पादन का दिखेगा अनोखा संगम

सिंगरौली। कलेक्टर गौरव बैनल एवं जीएम सीएसआर एनसीएल राजीव रंजन के द्वारा तियरा ग्राम पंचायत स्थित गर्रा सिंचाई जलाशय का भ्रमण किया गया। विदित हो कि कलेक्टर द्वारा मछुआ समिति के सदस्यों के साथ विगत दिवस बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मछली पालन सह-पर्यटन के संबंध में प्रस्ताव मांगे गए थे। जिसके फलस्वरूप आज स्वयं कलेक्टरबैनल ने गर्रा जलाशय पहुंचकर चतियरा जल विहार एवं मत्स्य पालनज के प्रस्तावित प्रोजेक्ट का अवलोकन किया ।प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कलेक्टर ने आदिवासी मछुआ सहकारिता समिति तियरा द्वारा किए जा रहे मछली पालन एवं प्रस्तावित जल विहार को पर्यटन एवं मछली उत्पादन का एक बेहतरीन संगम बताया। साथ ही यह भी कहा कि शीघ्र ही समिति के सभी सदस्यों को रोजगार का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा ।समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से तालाब में आधुनिक केज कल्चर तथा अन्य तकनीकों के माध्यम से मछली उत्पादन किया जाएगा। इसी के साथ ही बतख पालन कर समिति की आय को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। प्रस्तावित प्रोजेक्ट में पर्यटन को मद्देनजर रखते हुए तालाब की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा, जिसमें रिक्रिएशनल थीम पर आधारित पाथ-वे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने हेतु बैठक व्यवस्था, बोटिंग एक्टिविटीज तथा अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

साहित्य के क्षेत्र में सुयश त्यागी को मिला अखिल भारतीय कीर्ति पुरस्कार

नरसिंहपुर, स्वतंत्र मत।

भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी व नरसिंहपुर विधानसभा के ग्राम करतार निवासी सुयश त्यागी को साहित्य के क्षेत्र मे उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति 'छूटते किनारे' के लिए साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव (उपन्यास) पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह सम्मान आपकी साहित्यिक साधना, सृजनात्मक प्रतिभा, वैचारिक गहराई एवं समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टि का गौरवपूर्ण अभिनंदन है। आपकी लेखनी केवल शब्दों का सृजन नहीं करती, बल्कि समाज को दिशा, संवेदना और प्रेरणा भी प्रदान करती है ।सुयश त्यागी की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर भाजपा परिवार के समस्त नेतागणों, पदाधिकारीयों, कार्यकर्ताओं व शुभचिंतकों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें उनके साहित्य और जनसेवा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करने हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

ऑनलाइन ट्रेडिंग ठगी के दो आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार

10 लाख रुपये की पूरी राशि वापस कराई

गाडरवारा (स्वतंत्र मत)।

पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नरसिंहपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर 10 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पीड़ित की ठगी गई शत-प्रतिशत राशि बरामद कर वापस दिलाई गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 10 लाख की साइबर ठगी- दिनांक 04.05.2026 को वल्लभ मार्केट, गाडरवारा निवासी आशीष पटेल ने थाना गाडरवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फेसबुक पर प्रदर्शित एक विज्ञापन के माध्यम से उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश कर अधिक लाभ अर्जित करने का प्रलोभन दिया गया। झांसे में आकर उसने विभिन्न किश्तों में कुल 10 लाख रुपये निवेश कर दिए, जिसके बाद उसे न तो कोई लाभ प्राप्त हुआ और न ही उसकी राशि वापस मिली। स्वयं के साथ धोखाधड़ी होने का एहसास होने पर उसने पुलिस से शिकायत की।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीम गठित- शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना गाडरवारा में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा एसडीओपी गाडरवारा के मार्गदर्शन में साइबर सेल नरसिंहपुर एवं थाना गाडरवारा की संयुक्त टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान- पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यो, बैंकिग ट्रांजेक्शन एवं डिजिटल विश्लेषण के आधार पर आरोपी खाताधारक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी कर प्राप्त की गई पूरी 10 लाख रुपये की राशि बरामद कर जप्त की गई, जिसे नियमानुसार पीड़ित को वापस दिलाया गया।

गिरफतार आरोपी: सूरज कुमार शाहू पिता नक्षत्रबलि शाहू, निवासी वैशाली नगर, नागपुर, महाराष्ट्र।

परमानंद मिश्रा पिता त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा, निवैसी भारत नगर, नागपुर, महाराष्ट्र।

बरामदगी = आरोपी सूरज शाहू के कब्जे से धोखाधड़ीपूर्वक हड़पी गई संपूर्ण राशि 10 लाख रूपये बरामद किये गये। वैधानिक कार्यवाही: आरोपियों के विरूद्ध धारा 318 (4) बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रकरण पंजीवद्ध किया गया है। कार्यवाही में सराहनीय भूमिका उक्त आरोपीगण की पतारसी एवं मशरूका बरामदगी में थाना प्रभारी गाडरवारा निरीक्षक अशोक सिंह चौहान, उप निरीक्षक अनिल कुमार भगत, आरक्षक रूपेन्द्र चौबे, सुजीत बागरी की सराहनीय भूमिका रही है।

घर के अंदर घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 का अर्थदण्ड

नरसिंहपुर। स्वतंत्रमत। न्यायालय श्री शिवकांत कुशवाहा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के न्यायालय द्वारा घर के अंदर घुसकर मारपीट करने वाले प्रकरण के आरोपी प्रकाश दुबे पिता ठाकुर प्रसाद दुबे उम्र 57 वर्ष निवासी खैरीखुर्द थाना तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर म0प्र0 को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 452 में 06 माह का सश्रम कारावास तथा 1000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 323 में 03 माह का सश्रम कारावास तथा 1000 रूपए का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। जिला मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि फरियादी में ने थाना तेंदूखेड़ा उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि प्रकाश दुबे ने 04 साल से उसकी खेती सिकमी पर लिये है एवं सिकमी के पैसे नहीं दिये हैं। दिनांक 23/04/2023 को रात्रि लगभग 8रू30 बजे उसने प्रकाश दुबे से सिकमी के पैसे का बोला तो वह भड़क गया और उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा था।

मानसून के मद्देनजर नगर निगम के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान तेज

सिंगरौली, स्वतंत्र मत

नगर पालिक निगम सिंगरौली की आयुक्त सविता प्रधान के निर्देशानुसार, मानसून के आगमन और आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए शहर भर में स्वच्छता अभियान को युद्धस्तर पर तेज कर दिया गया है। वर्षा काल के दौरान संभावित जलभराव की स्थिति से निपटने और मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी तारतम्य में निगम के डिप्टी कमिश्नर आर.पी. बैस एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी.जी. चतुर्वेदी के द्वारा वार्डों में पहुंचकर साफ-सफाई व्यवस्था का सघन निरीक्षण किया गया और मानसून पूर्व तैयारियों का जायजा लिया गया।

अभियान के तहत सर्वप्रथम वार्ड क्र. 12 सिम्प्लेक्स कॉलोनी, जयंत का दौरा किया गया, जहां स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद कर जलभराव वाले संभावित बिंदुओं की पहचान की गई। साथ ही सफाई अमले को पाबंद किया गया कि मानसून की भारी बारिश से पहले क्षेत्र की सभी छोटी-बड़ी नालियों के अवरोध (ब्लॉक) को पूरी तरह हटा दिया जाए ताकि पानी की निकासी सुगम हो सके।

इसके बाद वार्ड क्र. 23 नवानगर पहुंचकर मानसून में गंदगी के कारण होने वाले जलभराव और मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। यहां अधिकारियों ने वार्डवासियों से मानसून में गीले कचरे से होने वाली दुर्गंध और जलभराव की समस्या पर चर्चा की तथा सूखा व गीला कचरा अलग-अलग डस्टबिन में देने की समझाइश दी। साथ ही, वर्षा के पानी के जमाव को रोकने के लिए निचले इलाकों और रास्तों के किनारे जमे मलबे व झाड़ियों को भारी जेसीबी मशीनों की मदद से साफ कराया गया, जिससे पानी का प्राकृतिक बहाव न रुके।

इसी कड़ी में व्यापारिक केंद्र वार्ड क्र. 40 कटरा मार्केट, बैढ़न में मानसून की पहली बारिश में ही जलभराव की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए विशेष सफाई अभियान चलाया गया। आधुनिक जीपीएस तकनीक के जरिए सुबह से ही नालियों की गहरी सफाई (सिल्ट सफाई) की कड़ी निगरानी की गई और मार्केट क्षेत्र की नालियों से भारी मात्रा में गाद और प्लास्टिक कचरा बाहर निकाला गया।

निरीक्षण के दौरान सफाई अमले को निर्देशित किया गया कि मानसून के दौरान बाजार में जलभराव की स्थिति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वहीं नगर निगम आयुक्त द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मानसून के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहें। लापरवाही पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे मानसून के दौरान नालियों में प्लास्टिक, पॉलिथीन या अन्य कचरा न फेंकें और शहर को स्वच्छ व सुरक्षित रखने में सहयोग करें।

समान नागरिक संहिता विषय पर परिचर्चा 18 जून को जिला पंचायत सभागार में

उमरिया । समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में जनसामान्य के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने तथा सामाजिक एवं कानूनी विषयों पर व्यापक संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से 18 जून 2026 को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सभागार, उमरिया में एक महत्वपूर्ण परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ।इस परिचर्चा में विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक एवं कानूनी विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों एवं आम नागरिकों के विचारों और सुझावों को प्राप्त कर उन्हें संकलित करना है ।जिला प्रशासन उमरिया ने जिले के नागरिकों से कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की है।

एनसीएल ने रिलेशनशिप मैनेजमेंट और इमोशनल वेल-बीइंग पर कार्यशाला का किया आयोजन

आध्यात्मिक प्रशिक्षक, देवामीरा दास ने सिखाए स्वस्थ संबंधों के गुर

सिंगरौली। शुक्रवार को सिंगरौली स्थित कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने च्फाइट क्लीन- स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड्स दैट फ्री असज्ज विषय पर सीईटीआई परिसर, सिंगरौली में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आध्यात्मिक प्रशिक्षक, देवामीरा दास उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यस्थल और निजी जीवन में संतुलन बनाने हेतु पारस्परिक संबंधों की चुनौतियों और मानव मन पर उनके पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने घर और कार्यस्थल पर आने वाली विभिन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक व्यावहारिक उपकरणों और जीवन-कौशलों के बारे में भी बताया। अंत में देवामीरा दास ने इस बात पर विशेष बल दिया कि आंतरिक जागरूकता, सीखने की ललक और सही आत्मिक सहयोग के माध्यम से ही आपसी संबंधों की जटिलताओं को गहराई से समझा जा सकता है।

इस दौरान कार्यक्रम में एनसीएल की सभी परियोजना और इकाइयों से लगभग 73 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिक्रियात्मक आदतों, आत्म-नियमन (सेल्फ-रेगुलेशन) और सचेत होकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने (कॉन्शियस रिस्पॉन्डिंग) के गुर सीखे।

गौरतलब है कि एनसीएल द्वारा कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु ऐसी अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

उमरिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती राखी सहाय की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के संबंध में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई ।बैठक में मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा ने संशोधित मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रों पर प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दावे एवं आपत्तियां 15 जून तक प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा, जबकि निराकृत दावा-आपत्ति आवेदन पत्रों की ईआरएमएस में प्रविष्टि 30 जून तक की जाएगी ।उन्होंने बताया कि चेकलिस्ट तैयार करने की अवधि 3 जुलाई तक निर्धारित है। त्रुटि सुधार के उपरांत सूची को वेंडर को वापस करने की अवधि 6 जुलाई, फोटोयुक्त एवं फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट करने की अवधि 9 जुलाई तथा फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को वेबसाइट पर अपलोड करने की अवधि 10 जुलाई निर्धारित की गई है ।इसी प्रकार फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराने की अवधि 16 जुलाई, नगर पालिका वार्डों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य विहित स्थानों पर अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन की अवधि 18 जुलाई तथा अंतिम फोटोयुक्त सूची की पीडीएफ, डीवीडी एवं सीडी की तीन प्रतियां ज्वेल केस में वेंडर से प्राप्त करने की अवधि 20 जुलाई तय की गई है। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची की फोटोरहित डीवीडी एवं सीडी विक्रय हेतु उपलब्ध कराने की अवधि 21 जुलाई तथा फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण-पत्र स्कैन करने, नगरीय निकायों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची उपलब्ध कराने एवं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित करने की अवधि 22 जुलाई निर्धारित की गई है।

जन कल्याण शिविर के तहत जनपद पंचायत करकेली में तीन दिवसीय शिविर का शुभारंभ

उमरिया । शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत करकेली परिसर में तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर 14 जून तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल ने कहा कि जन कल्याण शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि एक छत के नीचे योजनाओं से संबंधित जानकारी, आवेदन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने अधिकारियों से पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने का आग्रह किया ।कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विकासखंड एवं नगरीय निकाय स्तर पर जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर का प्रमुख उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए ।उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे तथा कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का यथाशीघ्र निराकरण किया जाएगा। जिन प्रकरणों का तत्काल निराकरण संभव नहीं होगा, उनके लिए समय-सीमा निर्धारित कर समाधान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी ।कलेक्टर ने उपस्थित ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करें तथा अपनी आवश्यकतानुसार आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपने आसपास के नागरिकों को भी शिविर की जानकारी देने का आग्रह किया, ताकि अधिक से अधिक लोग शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें ।सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत करकेली परिसर में आयोजित शिविर में 110 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करकेली ऋषभ शुक्ला ने शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए आयोजन की जानकारी दी।

शिविर में आयुष विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने इन स्टॉलों का अवलोकन कर विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष करकेली प्रियंका मून सिंह, जिला पंचायत सदस्य ओंकार सिंह, एसडीएम बांधवगढ़ अंबिकेश प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

बच्चों के भविष्य से जुड़े कार्यों में नहीं होगी कोई लापरवाही : महापौर

शहर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों पर भी विशेष जोर

कटनी (स्वतंत्रमत)

नगर निगम क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों एवं शैक्षणिक अधोसंरचना की प्रगति की समीक्षा करते हुए महापौर प्रीति संजीव सूरी ने मंगलवार को निगम के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की विस्तृत बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क, भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के साथ बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना भी निगम की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न केवल नागरिक सुविधाओं को प्रभावित करती है, बल्कि शिक्षा एवं सामाजिक विकास की गति को भी बाधित करती है। उन्होंने सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान महापौर ने चौपाटी निर्माण कार्य, घंटाघर से जगन्नाथ चौक तक सड़क चौड़ीकरण, निर्माणाधीन ए. रविंद्रराव शाला भवन, स्वीकृत पुरवार शाला भवन सहित पूर्व में चिन्हित जर्जर शाला भवनों के मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही सिविल लाइन स्थित डॉ. प्रवीण वैश्य गली, लखेरा रोड, गौरीशंकर मंदिर रोड, सरस्वती स्कूल रोड, आदर्श कॉलोनी से गर्ग चौराहा मार्ग, कैंप मुख्य बाजार से मुक्तिधाम मार्ग तथा प्रीतम राइस मिल क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर दीवान सायकल से झूलेलाल मंदिर मार्ग कैंप तक डामरीकरण का प्रस्तावित एवं प्रगतिरत डामर सड़कों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। महापौर ने प्रगतिरत कार्यों में गुणवत्ता एवं समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से स्कूल भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को सुरक्षित, सुविधायुक्त एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना नगर निगम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करना भविष्य की पीढ़ी को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में महापौर ने शहर में संचालित विभिन्न अधोसंरचनात्मक एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बस स्टैंड क्षेत्र में क्षतिग्रस्त एवं झुके हुए डिवाइडरों के सुधार कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख मार्गों के उन्नयन, सड़क चौड़ीकरण, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में अपेक्षित गति लाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य केवल निर्माण करना नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम आवागमन और स्वच्छ एवं व्यवस्थित शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। महापौर ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की सबसे मजबूत नींव होती है। बेहतर स्कूल भवन, सुरक्षित परिसर एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शाला भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा वर्षा ऋतु से पूर्व सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। साथ ही सभी अधूरे निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा निर्धारित समयसीमा में उन्हें पूर्ण कर नागरिकों को शीघ्र लाभ उपलब्ध कराया जाए। महापौर ने कहा कि शहर के विकास की गति बनाए रखने के लिए विभागीय समन्वय, जवाबदेही और सतत निगरानी अत्यंत आवश्यक है। विकास एवं शिक्षा, दोनों ही नगर के समग्र विकास के प्रमुख आधार हैं और इनसे जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए। बैठक में प्रभारी कार्यपालन यंत्री असित खरे, सहायक यंत्री सुनील सिंह, अनिल जायसवाल, आदेश जैन सहित सभी क्षेत्रीय उपयंत्री उपस्थित रहे।

1008 चालान कर 5 लाख से अधिक राशि का किया जुर्माना

कटनी (स्वतंत्रमत)। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में अनूप सिंह निरीक्षक थाना प्रभारी यातायात पुलिस द्वारा कटनी जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आमजन के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष यातायात प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया। यातायात पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ट्रिपल सवारी, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बातचीत, रेड सिग्नल जंप, नो पार्किंग, वन-वे उल्लंघन, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों का पालन करने के बजाय ट्रैफिक पुलिस से बचने या कार्रवाई से बचकर निकलने का प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध भी शहर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी रखते हुए ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तकनीकी निगरानी के माध्यम से निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। 18 मई से 11 जून तक की गई प्रमुख चालानी कार्यवाही धारा 185 (नशे की हालत में वाहन संचालन) 09, बिना हेलमेट 31, बिना नंबर प्लेट 97, बिना सीट बेल्ट 27, नो पार्किंग 203, रेड लाइट जंप 31, वन-वे में वाहन संचालन 41, खतरनाक स्थिति में वाहन खड़ा करना 31, ट्रिपल सवारी 173, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन संचालन 161 तथा अन्य धाराओं में कार्रवाई- 204 कुल चालान 1008 चालान किए गए हैं, एवं 5 लाख से अधिक की राशि का जुर्माना किया गया है। अभियान के दौरान आमजन से अपील की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने परिवार, मित्रों एवं परिचितों को भी सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करें, जिससे सुरक्षित शहर- सुरक्षित जीवन के उद्देश्य को सफल बनाया जा सके।

निजी क्लीनिक की अधिकारियों ने की जांच, बनाया पंचनामा

नाहर द्वारा मेडिकल प्रैक्टिस की जाती है।

कटनी (स्वतंत्रमत)। विकासखण्ड विजयराघवगढ़ के ग्राम पंचायत सिघनपुरा के ग्राम बकेली के मंदिर परिसर में संचालित निजी क्लीनिक का नायब तहसीलदार सिंगौड़ी राजेन्द्र श्रीवास्तव और विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी विनोद कुमार द्वारा यहां पहुंचकर निरीक्षण और जांच कर पंचनामा तैयार किया। जांच दल को यहां पहुंचने पर पता चला कि इस क्लीनिक में सी.पी. सिंह नाहर एवं भूपेन्द्र सिंह

कटनी स्टेशन के फूड प्लाजा में आर्मी जवान से मारपीट का आरोप

कटनी (स्वतंत्रमत)। कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 स्थित फूड प्लाजा में एक आर्मी जवान के साथ कथित मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आने के बाद स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के अनुसार मैहर साइड बने फूड प्लाजा के एक कर्मचारी और आर्मी जवान के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान जवान के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सूत्रों का दावा है कि प्रारंभिक रूप से लूट और मारपीट जैसे आरोपों की चर्चा थी, लेकिन बाद में मामले को चैन पुलिंग से जोड़कर कार्रवाई की गई और जवान को जाने दिया गया। जानकारी अनुसार कटनी रेलवे स्टेशन और उसके आसपास आर्मी जवानों के साथ विवाद और अभद्रता की यह तीसरी घटना बताई जा रही है। इससे स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

24 घंटे के अंदर लूट के अज्ञात लुटेरों को किया गिरफ्तार भेजा जेल

पैसों के लिये तीन दोस्तों ने मिलकर लूट की घटना को दिया अंजाम

कटनी (स्वतंत्रमत)। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के कुशल निर्देशन एवं रत्नेश मिश्रा उप पुलिस अधीक्षक के मार्ग दर्शन में थाना एनकेजे थाना प्रभारी को मिली सफलता। 11 जून को प्रार्थी अभिषेक रजक पिता कमलेश रजक उम्र 23 साल निवासी ग्राम हीरापुर कौडिया थाना एनकेजे कटनी का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की में अपनी मोटर साईकिल से अकेला अपने घर हीरापुर कौडिया जा रहा था नर्मदा वेयर हाउस मोड पर तीन अज्ञात व्यक्ति जो मुह पर सफेद गमछा बाधे हुये थे। तीनो ने मेरा रास्ता रोककर चाकू दिखाकर मेरे साथ मारपीट कर एमेरी पेंट की जेब से मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरा मोटर साईकिल लेकर भाग गये प्रार्थी अभिषेक रजक की रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 296(बी), 126(2), 309(4), 309(6), 351(3), 61(2) बीएनएस का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे एवं उप पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में गठित थाना एनकेजे पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना व तकनीकी साक्ष्यो के आधार पर संदेही गुलशन चौधरी निवासी गाताखेडा को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ किये जिसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने दो अन्य साथी करन रैकवार निवासी पोस्ट आफिस मुख्य डाकघर के सामने थाना कोतवाली कटनी एवं दीपांशु सेन निवासी केलवारा फाटक कटनी को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ किये जिसमे तीनो ने घटना दिनांक को लूट की घटना करना स्वीकार किया। गुलशन चौधरी के कब्जे से लूट की गयी मोटर साईकिल, आरोपी दीपांश सेन से घटना मे प्रयोग की गयी स्वयं की मोटर साईकिल व लूट किया गया मोबाईल एवं आरोपी करण रैकवार से घटना मे प्रयोग की गयी चाकू जप्त की गई है। तीनो आरोपियो को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कटनी मे पेश कर जिला जेल कटनी भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण:- गुलशन चौधरी पिता स्व. चुन्नी लाल चौधरी निवासी ग्राम गाताखेडा थाना एनकेजे, करन रैकवार पिता अनूप रैकवार उम्र 20 साल निवासी वार्ड नं. 24 ईश्वरी पुरा वार्ड थाना कोतवाली, दिपांशु उर्फ दिपांश उर्फ सागर सेन पिता दीपक सेन उम्र 23 साल निवासी नदी पार कैलवारा मोड थाना कोतवाली।

औषधि विभाग की टीम ने किया मेडिकल स्टोर का निरीक्षण

कटनी (स्वतंत्रमत)। जिले में औषधियों की बिक्री और भंडारण व्यवस्था को नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में बुधवार को सीएमएचओ डॉ. राज सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में औषधि विभाग की टीम ने कन्हवारा स्थित मित्रा फार्मेसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर पर कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। मौके पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला और दवाओं के संधारण से संबंधित कोई भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा बिना चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं का विक्रय किया जाना भी पाया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध रूप से इलाज किया जा रहा था, जहां एक डॉक्टर मरीजों का उपचार करते हुए पाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निरीक्षण दल ने मौके पर ही मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया। साथ ही संबंधित संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई जारी है।

दुर्घटना रोकथाम हेतु कटनी पुलिस की विशेष पहल जारी

कटनी (स्वतंत्रमत)। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में निरीक्षक अनूप सिंह थाना प्रभारी यातायात, सहायक उप निरीक्षक अशोक सिंह, आरक्षक राजकुमार एवं आरक्षक सुरेन्द्र सिंह द्वारा थाना माधवनगर एवं चौकी निवार क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-30 स्थित चिन्हित ब्लैक स्पॉट ग्राम लखपतेरी (जलासुर मार्ग) का निरीक्षण कर विशेष सुरक्षा एवं जन-जागरूकता संबंधी कार्यवाही की गई। कटनी पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त स्थान पर विगत समय में लगातार गंभीर सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें कई व्यक्तियों की मृत्यु एवं अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस द्वारा दुर्घटना संभावित क्षेत्र में चेतावनी सूचक फ्लेक्स बोर्ड, सावधानी संकेतक एवं जागरूकता संदेश स्थापित कराए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को समय रहते सतर्क किया जा सके। स्थापित किए गए संदेशों के माध्यम से वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, तेज गति एवं ओवरटेकिंग से बचने, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने एवं सड़क पर पूर्ण सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा स्थानीय नागरिकों, वाहन चालकों एवं आसपास के निवासियों से भी सहयोग की अपील की गई है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा अन्य लोगों को भी जागरूक करें।

एसपी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में चला सघन चेकिंग अभियान

कटनी (स्वतंत्रमत)। थाना कुठला अंतर्गत इंदिरा नगर तिराहे पर 11 जून को सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा एक विशेष और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के कुशल निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में की गई। अभियान के दौरान थाना प्रभारी कुठला अखलेश दहिया एवं पुलिस टीम ने मुख्य तिराहे और मार्गों पर नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया। विशेष रूप से लापरवाही से तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल पर तीन सवारी (ट्रिपल राइडिंग) बैठाने वाले और बिना नंबर प्लेट के घूम रहे वाहन चालकों को रोककर उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत वैधानिक एवं चलानी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी कुठला अखलेश दहिया ने आम जनता से अपील की है कि वे जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और अनिवार्य रूप से यातायात नियमों का पालन करें। भविष्य में भी इस प्रकार का चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा।

जिला अस्पताल में जरूरतमंदों को वितरित की गई आवश्यक सामग्री

कटनी (स्वतंत्रमत)। गहोई एकता मंडल कटनी के तत्वावधान में शासकीय जिला अस्पताल कटनी में सेवा एवं मानवता को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों तथा नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर मरीजों एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन की थालियां, टोस्ट, बिस्किट, मठा एवं मिठाई वितरित की गई। वहीं नवजात शिशुओं को कपड़े, मच्छरदानियां एवं अन्य उपयोगी सामग्री प्रदान की गई। गहोई एकता मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज के जरूरतमंद एवं असहाय वर्ग के सहयोग से और ऐसे सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में संवेदनशीलता एवं मानवता की भावना को बल मिलता है। इस सेवा अभियान को सफल बनाने में शासकीय जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा एवं अस्पताल के समस्त चिकित्सकीय तथा गैर-चिकित्सकीय स्टाफ का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। मंडल ने उनके सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में गहोई एकता मंडल के पदाधिकारी शिल्पी सोनी टंडन, रीता सेठिया, मनीषा कनकने, स्नेह लता सेठिया, अर्चना कनकने, उदिता चौदहा, रश्मि मसुहरा, प्रीति सुहाने, प्रियंका सेठिया, संगीता कनकने, कुमुद चौदहा, नीतू कनकने, मीता चौदहा, आभा नौगरहिया, रीना आनंद चौदहा, आरती त्रिसोलिया, रीना चौदहा, सारिका कनकने एवं वरिष्ठ संघ से केशव छिरोल्या भगवान दास गुप्ता, नवयुवक मंडल से राहुल सुहाने, अनुराग सोनी, सृजन चौदहा एवं अन्य समाजसेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उपस्थित सभी लोगों ने भविष्य में भी ऐसे जनहित एवं सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया।

छात्र-छात्राओं ने कलेक्ट्रेट एवं विभिन्न शासकीय कार्यालयों का किया शैक्षणिक भ्रमण

कटनी (स्वतंत्रमत)

कटनी आर्ट्स कामर्स एण्ड लॉ कॉलेज ऑटोनॉमस के एलएलबी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए चड्ढा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डॉयरेक्टर देवाशीष चड्ढा एवं कॉलेज संचालक डॉ. जय चड्ढा के निर्देशन विधि पाठ्यक्रम अंतर्गत मूट कोर्ट प्रशिक्षण विषय के अंतर्गत कलेक्ट्रेट एवं विभिन्न शासकीय कार्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। इस भ्रमण में एलएलबी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राऐं शामिल रहे। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी डी.एम. एवं अपर जिला दण्डाधिकारी ए.डी.एम. न्यायालय, राजस्व न्यायालय, नजूल न्यायालय तथा लोक सेवा विभाग सहित अन्य विभागों का अवलोकन किया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर जितेन्द्र कुमार पटेल के मार्गदर्शन में छात्र-छात्राओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। जिला प्रबंधक लोक सेवा विभाग दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने छात्र-छात्राओं को लोक सेवा विभाग की कार्यप्रणाली, उसकी उपयोगिता एवं आमजन के लिए उसकी महत्ता के विषय में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना शासन की प्राथमिकता है साथ ही कलेक्ट्रेट में पदस्थ दीसी स्थापना एवं हरप्रीत सिंह ग्रोवर द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं ने जिला पंजीयक कार्यालय एवं रजिस्ट्री कार्यालय का भी भ्रमण किया। इस दौरान जिला पंजीयक पंकज कोरी ने संपत्ति पंजीयन से सम्बंधित विभिन्न अधिनियमों एवं विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट रूप में समझाया। इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विधि प्राचार्य डॉ. गोपाल उपाध्याय, विभागाध्यक्ष डॉ. ऋतिका साहनी आहूजा, सहायक प्राध्यापिका माला उपाध्याय, सहायक प्राध्यापक शैलेज तिवारी एवं पवन केवट उपस्थित रहे और उन्होंने छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन किया।

स्वतंत्र मत
जबलपुर

बदलाव की ओर बढ़ रही टीम इंडिया वन-डे में भी बादशाहत साबित करने उतरेगी

धर्मशाला (वार्ता)।

धर्मशाला में अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ 13 जून को भारत का वनडे सीरीज़ का पहला मैच बदलाव बनाम मौके की एक मज़बूत कहानी पेश करता है, जिसमें मेज़बान टीम अपने व्हाइट-बॉल स्ट्रक्चर में एक नए दौर में जा रही है, जबकि मेहमान टीम एक जबरदस्त हेड-टू-हेड रिकॉर्ड को चुनौती देना चाहेगी। शुभमन गिल की लीडरशिप में बदलाव पर पूरा ध्यान है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटों के कारण बाहर हैं। उनकी गैरमौजूदगी ने भारत के युवा कोर में बदलाव को तेज़ कर दिया है, जिससे उभरते हुए लीडर्स और परफॉर्मर्स पर हाई-प्रेशर इंटरनेशनल माहौल में अच्छा प्रदर्शन करने की तुरंत ज़िम्मेदारी आ गई है।

टॉप ऑर्डर अभी भी स्थिरता की तलाश में

गिल की लीडरशिप ऐसे समय में शुरू हो रही है जब टॉप ऑर्डर को अभी भी नए सिरे से बनाया जा रहा है, जिसमें यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर से बैटिंग लाइन-अप की रीढ़ बनने की उम्मीद है, जो अभी भी स्थिरता की तलाश में है। केएल राहुल का सीनियर स्टेबलाइज़र और विकेटकीपर के तौर पर रोल बैलेंस बनाता है, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर वाले लोअर मिडिल ऑर्डर की फिनिशिंग और ऑल-राउंड दोनों ड्यूटीज़ में परीक्षा होगी।

बॉलिंग में अर्शदीप और कृष्णा पर निर्भर

बॉलिंग डिपार्टमेंट में, इंडिया शुरुआती ब्रेकथ्रू दिलाने के लिए अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा, जबकि कुलदीप यादव से बीच के ओवरों को कंट्रोल करने में अहम रोल निभाने की उम्मीद है। हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी से इंडिया के पार्ट-टाइम और उभरते हुए

ऑल-राउंड ऑप्शंस पर ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है।

राशिद खान मेन खतरा बने हुए हैं

इस बीच, अफ़गानिस्तान स्पिन डॉमिनेंस और डिसिप्लिन्ड ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन के आस-पास बनी एक पक्की पहचान के साथ आ रहा है। राशिद खान उनके लिए मेन खतरा बने हुए हैं, जिन्हें मोहम्मद नबी के एक्सपीरियंस और बीच के ओवरों में कंट्रोल का सपोर्ट है। अज़मतुल्लाह उमरज़ई का हालिया ऑलराउंड फ़ॉर्म और गहराई जोड़ता है, जिससे अफ़गानिस्तान एक ऐसी टीम बन गई है जो दोनों इनिंग्स में लगातार प्रेशर डाल सकती है। टॉप पर, रहमानुल्लाह गुरबाज़ और इब्राहिम ज़दरान से एक अग्रेसिव बेस देने की उम्मीद है, जबकि सेदिकुल्लाह अटल और रहमत शाह मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देते हैं। फ़जलहक फ़ारूक़ी नई गेंद से पेस अटैक को लीड करेंगे, और धर्मशाला के हालात में शुरुआती मूवमेंट का फ़ायदा उठाना चाहेंगे।

बैटिंग के लिए आसान पिच

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से उम्मीद है कि बैटिंग के लिए आसान पिच पर सेट होने से पहले सीमर्स को शुरुआती मदद मिलेगी, पुराने डेटा के हिसाब से पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 280-300 के बीच रहता है। दूसरी इनिंग में ओस अहम रोल निभा सकती है, जिससे टॉस जीतने वाली टीम के लिए चेज़ करना एक पसंदीदा ऑप्शन बन जाएगा।

मुकाबला आसान नहीं होगा

भारत स्ट्रक्चरल बदलाव के दौर से गुज़र रहा है और अफ़गानिस्तान का व्हाइट-बॉल क्रिकेट में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसलिए इस मुकाबले को इस फ़ॉर्मेट के सबसे डिसिप्लिन्ड स्पिन अटैक में से एक के खिलाफ़ भारत की बेंच स्ट्रेंथ का टेस्ट माना जा रहा है। हालांकि, भारत अपने घरेलू हालात में फेवरेट के तौर पर शुरुआत करेगा, हालांकि अफ़गानिस्तान की बॉलिंग यूनिट यह पक्का करती है कि मुकाबला आसान नहीं होगा।

टीमें इस प्रकार हैं

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेट कीपर), कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, ईशान किशन (विकेट कीपर), अर्शदीप यशवर, गुरनोव

अफगानिस्तान : एल हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इकराम अलीखिल (विकेट कीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोटी, फरीद अहमद मलिक, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद नबी, इब्राशिह राशिद ज़द्रासोली, शरीफी, रहमत शाह।

चेन सु-यू को हराकर सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेफा में

सिडनी (वार्ता)। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए चीनी ताइपे की चेन सु-यू को आसानी से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जहां उनका मुकाबला जापान की वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। आज यहां महिला एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 10वें स्थान पर मौजूद पीवी सिंधु ने 68वीं रैंकिंग वाली चेन सु-यू को क्वार्टरफाइनल में 21-6, 21-9 से हराने में केवल 27 मिनट लिए और बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। हालांकि, 30 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए सेमीफ़ाइनल में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची के खिलाफ जीतना आसान नहीं होगा। यामागुची ने अपने क्वार्टर-फ़ाइनल मुकाबले में भारतीय किशोरी तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से हराया था। बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट में तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु का जापानी स्टार के ख़िलाफ़ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 15-13 का है, जिसमें उन्हें मामूली बढ़त हासिल है। हालांकि, यामागुची ने उनके बीच हुए पिछले पांच मुक़ाबलों में से चार जीते हैं। इन दोनों के बीच हालिया मुक़ाबला पिछले महीने थाईलैंड ओपन में हुआ था, जहाँ सिंधु जीत के बहुत करीब पहुंच गई थीं। भारतीय खिलाड़ी ने पहला गेम जीता था और दूसरे गेम के मिड-गेम इंटरवल तक चार अंकों की बढ़त बना ली थी, लेकिन यामागुची ने वापसी करते हुए 19-21, 21-18, 21-15 से जीत हासिल की।

पूर्व निशानेबाज जसपाल राणा का निधन

नयी दिल्ली (वार्ता)। पूर्व दिग्गज निशानेबाज और भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के हाई-परफॉर्मेंस कोच जसपाल राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को खेल जगत के लिए बड़ी क्षति बताते हुए दुख व्यक्त किया है। भारतीय राष्ट्रीय रायफल संघ (एनआरएआई) ने जसपाल राणा के निधन की पुष्टि की है। वह 49 वर्ष के थे। उन्हें वर्ष 2020 में खेल जगत के सर्वोच्च कोचिंग सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्वकप से भारतीय दल की वापसी के दौरान

फ्लाइट में जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी, वह असहज महसूस कर रहे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के हाई-परफॉर्मेंस कोच के रूप में कार्यरत थे। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण और दो रजत सहित कुल चार पदक जीते।

सफल और गौरवशाली निशानेबाजी करियर के बाद राणा ने जूनियर राष्ट्रीय टीम कोच और हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनर के रूप में भारतीय निशानेबाजी टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कोच के रूप में उनके योगदान में मनु भाकर को प्रशिक्षण देना शामिल है। उनकी देखरेख में मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में दो जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जसपाल राणा के निधन से गहरा दुख हुआ है।

केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

आकलैंड (वार्ता)। *न्यूज़ीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज़ केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उनके 16 साल लंबे शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत हो गया। 35 वर्षीय विलियमसन न्यूज़ीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन (19,346) बनाने वाले बल्लेबाज़ के रूप में विदा ले रहे हैं। संन्यास की घोषणा करते हुए विलियमसन ने कहा, मैं पिछले कुछ समय से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह साफ़ हो गया कि इस फ़ैसले के लिए यही सही समय है।*

अर्जेंटीना ने फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में फिर से टॉप पर जगह बनाई

ज़्यूरिख (स्विट्ज़रलैंड) (वार्ता)।

मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना दुनिया की टॉप रैंक वाली टीम के तौर पर अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत करेगा। जून फीफा/कोका-कोला पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग अब तक के सबसे बड़े फीफा वर्ल्ड कप के खत्म होने से कुछ घंटे पहले जारी की जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप से पहले कई फ्रेंडली मैचों के बाद, जिसमें दूसरा पीरियड था जब फीफा/कोका-कोला मेन्स वर्ल्ड रैंकिंग को इंटरनेशनल मैचों के दौरान रियल टाइम में अपडेट किया गया था, अर्जेंटीना आइसलैंड और होंडुरास के खिलाफ अपने

दोनों वार्म-अप मैचों में जीत के बाद टॉप पर वापस आ गया। वे फ्रांस की जगह लेंगे, जो कोटे डी आइवर से हारने के बाद पीछे हो गया था, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड को हराया, और स्पेन (दूसरे, बिना किसी बदलाव के), जिसे इराक ने ड्रॉ पर रोका और फिर पेरू को हराया। टॉप टेन में और नीचे, मोरक्को अपनी बढ़त जारी रखते हुए, अगस्त 1993 में फीफा/कोका-कोला मेन्स वर्ल्ड रैंकिंग शुरू होने के बाद से अपनी अब तक की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया है। ऐसा करके, वे नीदरलैंड्स से आगे निकल गए, जबकि टॉप 20 में कहीं और, मेक्सिको और उरुग्वे सेनेगल और अमेरिका से ऊपर चले गए, जबकि ईरान टॉप 100 में शामिल हो गया। हंगरी , चिली और चीन टॉप 100 में सबसे बड़े चढ़ने वाले हैं, जबकि सर्बिया , माली और बेनिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। टॉप 100 के बाहर, लेबनान और भूटान की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। कॉम्पिटिशन रेगुलेशन के मुताबिक, फीफा/कोका-कोला मेन्स वर्ल्ड रैंकिंग भी टाईब्रेकर का काम करेगी, ताकि ग्रुप स्टेज के आखिर में दो या उससे ज़्यादा टीमों के ग्रुप में रैंकिंग पक्की हो सके और यह तय हो सके कि स्टेप 1 और 2 में कई बार थर्ड-रैंक 32 क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी टाई हुई टीम तक पहुंचने के लिए कौन सी आठ टीमें सबसे

कच्चे तेल में नरमी से रुपया 67 पैसे मजबूत

मुंबई (वार्ता)। कच्चे तेल में नरमी और विदेशों में बॉन्ड यील्ड घटने से शुक्रवार को रुपया 67 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.18 रुपये का बोला गया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद से कच्चे तेल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट है और शेयर बाजार बढ़त में हैं जबकि बॉन्ड यील्ड घट गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता काफी आगे पहुंच गयी है और इस सप्ताहांत पर समझौता संभव है। श्री ट्रंप के इस बयान के बाद आज कच्चा तेल दो प्रतिशत से अधिक गिरकर 88 डॉलर प्रति बैरल के

करीब आ गया। इससे रुपये को समर्थन मिला। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा 45 पैसे की बढ़त के साथ 95.40 रुपये प्रति डॉलर पर खुली। पूरे दिन इसमें उतार-चढ़ाव देखा गया। बीच कारोबार में रुपया नीचे 95.53 प्रति डॉलर तक उतरा था, लेकिन दोपहर बाद 94.95 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ। अंत में 95.18 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

गेहूं, तेलों, दालों में तेजी, चीनी नरम

नयी दिल्ली (वार्ता)।

घरेलू थोक जिंस बाजारों में शुक्रवार को चावल का औसत भाव लगभग स्थिर रहा। गेहूं, दालों और खाद्य तेलों के दाम बढ़ गये जबकि चीनी नरमी का रुख देखा गया। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 3,890 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग अपरिवर्तित रही। गेहूं चार रुपये मजबूत हुआ और 2,776 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया।

आटे की कीमत 12 रुपये बढ़ी। दाल-दलहनों में तुअर दाल की औसत कीमत 43 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। उड़द दाल का भाव 29 रुपये और मूंग दाल का 21 रुपये चढ़ गया। चना दाल 18 रुपये और मसूर दाल तीन रुपये

प्रति क्विंटल महंगी हुई। मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में अगस्त का पाम ऑयल वायदा 72 रिंगिट गिरकर 4,479 रिंगिट प्रति टन पर रह गया। जुलाई का अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 0.81 प्रतिशत टूटकर 73.85 सेंट प्रति पौंड के भाव बोला गया। स्थानीय बाजारों में मूंगफली तेल की औसत कीमत 132 रुपये और पाम ऑयल की 68 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। सूरजमुखी तेल 49 रुपये और सरसों तेल 43 रुपये महंगा हुआ। वनस्पति के भाव में 37 रुपये और सोया तेल में सात रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही। मीठे के बाजार में आज गुड़ का औसत भाव सात रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया। वहीं, चीनी तीन रुपये सस्ती हुई। दाल चना 7740.54 रुपये, मसूर काली 8151.80 रुपये, मूंग दाल 10183.41 रुपये, उड़द दाल 10895.68 रुपये, तुअर दाल 11287.65 रुपये प्रति क्विंटल रही। अनाज (भाव प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2776.24 रुपये और चावल 3889.74 रुपये प्रति क्विंटल और आटा (गेहूं) 3255.86 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चीनी एस 4348.11 रुपये और गुड़ 5074.06 रुपये प्रति क्विंटल बोले गये। सरसों तेल 18153.75 रुपये, मूंगफली तेल 19217.05 रुपये, सूरजमुखी तेल 17686.55 रुपये, सोया तेल 15228.93 रुपये, पाम ऑयल 13811.75 रुपये और वनस्पति 15232.64 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर रहा।

खुदरा महंगाई लगातार चौथे महीने बढ़ी

नयी दिल्ली (वार्ता)। खाने-पीने के सामान, ईंधन और गहनों के दाम बढ़ने से मई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर यानी खुदरा महंगाई बढ़कर 3.93 प्रतिशत पर पहुंच गयी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि मई में ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई 4.25 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 3.53 प्रतिशत दर्ज की गयी। खुदरा महंगाई लगातार चौथे महीने बढ़ी है। इस साल अप्रैल में यह 3.48 प्रतिशत रही थी। खास बात यह रही कि एक साल में सोने से ज्यादा मुद्रास्फीति टमाटर की रही। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति दर

4.78 प्रतिशत दर्ज की गयी। मांस की महंगाई दर 9.46 प्रतिशत, मछली और दूसरे समुद्री खाद्य उत्पादों की 7.53 प्रतिशत, तेल एवं वसा उत्पादों की 9.46 प्रतिशत और फलों की आठ प्रतिशत रही। पान एवं अन्य तंबाकू उत्पाद 6.62 प्रतिशत महंगे हुए। ईंधन की महंगाई दर छह प्रतिशत रही, हालांकि बिजली तीन प्रतिशत सस्ती हुई। माल परिवहन सेवा की 7.63 प्रतिशत दर्ज की गयी।

विश्व बैंक ने 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाया

कोविड-19 के बाद सबसे धीमी रह सकती है गति

वॉशिंगटन (वार्ता)। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाते हुए चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का आर्थिक प्रभाव क्षेत्र से कहीं आगे तक फैल रहा है और दुनिया भर के देशों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। गुरुवार को जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स शीर्षक रिपोर्ट के ताजा संस्करण में विश्व बैंक ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो एक वर्ष पहले 2.9 प्रतिशत थी। वहीं, वैश्विक मुद्रास्फीति (महंगाई) औसतन 4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो कई अर्थव्यवस्थाओं में जारी मूल्य दबावों को दर्शाती है। यह संशोधित अनुमान ऐसे समय में आया है जब कि ईरान युद्ध से ऊर्जा की लागत बढ़ी है और इसका

असर वैश्विक बाजारों में दिखाई दे रहा है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ रही है और इस बात का जोखिम भी बढ़ गया है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखें या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीतियों को और सख्त करें। विश्व बैंक ने यह भी चेतावनी दी कि विकासशील देश इस संकट का सबसे अधिक भार उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बढ़ती आयात लागत, कमजोर विकास संभावनाओं और सार्वजनिक वित्त पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रभाव को कम करने के लिए संस्था ने कहा कि वह विकासशील देशों के लिए तत्काल 60 अरब डॉलर के बराबर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है। मांग और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार यह राशि अगले 15 महीनों में बढ़कर 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में गत जनवरी के पिछले आकलन के बाद से लगभग दो-तिहाई देशों की आर्थिक वृद्धि संबंधी संभावनाओं को संशोधित कर नीचे किया गया है। विश्व बैंक ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव, जारी संघर्ष और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता निवेश, व्यापार और उपभोक्ता विश्वास पर लगातार नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार घटा

मुंबई (वार्ता)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच जून को समाप्त सप्ताह में 71.1 करोड़ डॉलर घटकर 681.61 अरब डॉलर रह गया। यह गिरावट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में कमी के कारण दर्ज की गयी है। स्वर्ण भंडार में सप्ताह के दौरान हालांकि वृद्धि हुई है। गत 29 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 93.8 अरब डॉलर बढ़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पांच जून का समाप्त सप्ताह में स्वर्ण भंडार 1.975 अरब डॉलर बढ़कर 114.575 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। आलोच्य सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 2.704 अरब डॉलर घटकर 543.444 अरब डॉलर रह गयी। इसमें अमेरिकी डॉलर के साथ जापानी येन, ब्रितानी पाउंड और यूरो भी शामिल है। उनके मूल्य का निर्धारण डॉलर के मुकाबले उनकी संदर्भ दर के आधार पर किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि 4.826 अरब डॉलर पर स्थिर रही।

शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी

प्रमुख सूचकांक दो प्रतिशत चढ़े

मुंबई (वार्ता)।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद में शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में चौतरफा लिवाली देखी गयी और प्रमुख सूचकांक दो प्रतिशत की बढ़त में दो सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गये। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि ईरान के साथ शांति वार्ता में अब तक की सबसे बड़ी प्रगति हुई है और इस सप्ताहांत पर समझौता संभव है, दुनिया भर में शेयर बाजारों में तेजी रही और कच्चा तेल गिर गया।

ईरान ने हालांकि ऐसी किसी ठोस प्रगति से इनकार किया है। श्री ट्रंप के बयान से उत्साहित निवेशकों की लिवाली से बीएसई का सेंसेक्स 876 अंक चढ़कर खुला। दोपहर बाद बाजार में लिवाली और बढ़ी। अंत में यह 1,695.40 अंक (2.30 प्रतिशत)

की बढ़त में 75,527.95 अंक पर बंद हुआ। यह 29 मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 461.30 अंक यानी 1.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,622.90 अंक पर बंद हुआ जो 27 मई के बाद का इसका सबसे ऊंचा बंद स्तर है। वृहत बाजार में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 2.37 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 2.80 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। आईटी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक ऊपर रहे। बैंकिंग, वित्त, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, रियल्टी, ऑटो और तेल एवं गैस सेक्टरों में निवेशकों ने खूब पैसा लगाया।

एनएसई में जिन 3,390 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ उनमें से 2,739 के शेयर बढ़त में और 564 के गिरावट में रहे। अन्य 87 कंपनियों के शेयर अंतत: अपरिवर्तित रहे। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 27 के शेयर हरे निशान में बंद हुए। बजाज फाइनेंस का शेयर 5.56 प्रतिशत चढ़ा। एलएंडटी में 4.94 प्रतिशत, इंडिगो में 4.59, टाइटन में 4.03, एचडीएफसी बैंक में 3.73 और इटरनल में 3.63 प्रतिशत की तेजी रही। एक्सिस बैंक का शेयर 2.92 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व का 2.69, कोटक महिंद्रा बैंक का 2.61, अल्ट्राटेक सीमेंट का 2.53, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2.39, भारती एयरटेल का 2.27, मारुति सुजुकी का 2.12 और एशियन पेट्स का 2.06 प्रतिशत मजबूत हुआ। टाटा स्टील में 1.98 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 1.74, भारतीय स्टेट बैंक में 1.62, ट्रेंट में 1.58, अडानी पोर्ट्स में 1.45, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.40, हिंदुस्तान यूनीलिवर में 1.32, टीसीएस में 1.23, बीईएल में 1.04 और आईटीसी में 1.01 प्रतिशत की तेजी रही।

सन फार्मा और एनटीपीसी में भी तेजी रही। टेक महिंद्रा का शेयर 2.41 फीसदी टूट गया। पावरग्रिड भी लाल निशान में बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर जापान का निक्केई 2.81 प्रतिशत, हांगकांग का हैंग सेंग 1.93 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.12 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में जर्मनी का डैक्स 1.41 प्रतिशत और ब्रिटेन का एफटीएसई 1.07 प्रतिशत की बढ़त में था।

बेहतर कानून व्यवस्था के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी रहें मुस्तैद : डॉ. यादव

शिक्षा केंद्रों के निकट छेड़छाड़ की घटनाएं न हों, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर रहें

भोपाल (स्वतंत्र मत)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बदलते दौर में पुलिस बल को नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपराधों के अन्वेषण का दायित्व निभाने वाले विवेचना अधिकारियों को अन्वेषण भत्ता भी मिले, इस दृष्टि से अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। इस क्षेत्र में अपराध स्थल पर त्वरित पहुंच, सुरक्षा व्यवस्था, साक्ष्य संकलन, अभियुक्त गवाह और पीड़ित के परिवहन, भोजन आदि के साथ फोटोग्राफी - वीडियोग्राफी, डिजिटल साक्ष्य संग्रह, न्यायलीन प्रक्रिया से जुड़े आकस्मिक खर्च देखते हुए मध्यप्रदेश में अन्वेषण भत्ता लागू किए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक स्तर तक सजगता और सक्रियता से भूमिका निभाई जाए।

आईटी कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का कार्य किया जाए- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा में कहा कि सायबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गृह विभाग द्वारा आईटी कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। बैठक में सिंहस्थ 2028 के लिए भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ की दृष्टि से विभिन्न कंट्रोल रूम तथा अन्य व्यवस्थाओं को इस तरह पूर्ण किया जाए ताकि उनका स्थाई महत्व और प्रभाव रहे।

उज्जैन में अनेक बाबा महाकाल मंदिर सहित देव स्थान हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बसंत पंचमी और हाल ही में भोजशाला से संबंधित प्रसंग में पुलिस बल की सजग सक्रिय भूमिका के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और फोर्स के अन्य सदस्यों को बधाई दी। **पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचार सराहनीय**-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचार सराहनीय हैं। राज्य को नक्सल मुक्त बनाने, आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, अन्य विभागों के सहयोग से सुगम परिवहन सुनिश्चित करने, अग्निशमन इकाईयों को सहयोग, एयर एम्बुलेंस के उपयोग में सहयोग, सैनिक कल्याण प्रयासों को बढ़ाने के कार्य सराहनीय हैं। इसके साथ ही खुले स्थानों में मांस विक्रय पर प्रतिबंध और तेज ध्वनि में स्पीकर आदि के प्रयोग को नियंत्रित करने के निर्देशों का भी निरंतर पालन किया गया है। यह व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहें, इसके लिए विभाग का अमला सक्रिय रहे। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन वर्चुअली शामिल हुए। अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव गृह संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा, एडीजी ए. साई मनोहर सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पुलिस चयन और भर्ती बोर्ड के गठन की पहल-बैठक में मध्यप्रदेश पुलिस चयन और भर्ती बोर्ड के गठन की पहल, सायबर अपराधों, सोशल मीडिया आधारित गतिविधियों और अपराधों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते दुरूपयोग के प्रभावी विशलेषण के लिए राज्य सायबर सेल ने विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में विचार किया गया। इसके साथ ही काउंटर टेररिस्ट ग्रुप की संरचना और बल में वृद्धि, राज्य स्तरीय उन्नत प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से एटीएस,एसटीएफ, हॉक फोर्स और अन्य विशिष्ट इकाईयों के लिए क्षमता संवर्धन प्रबंध, जिला स्तर पर सीन ऑफ क्राइम मोबाइल इकाई के संचालन के प्रावधान, वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने, एआई का प्रयोग कर सेफगार्ड एमपी प्रणाली के माध्यम से बुजुर्गों, कमजोर व्यक्तियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में एक नई तरह की पहल करने के संबंध में भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश- पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहे, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी मुस्तैद रहें। शिक्षा केंद्रों के निकट छेड़छाड़ की घटनाएं न हों, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर रहें। गौवंश रक्षा पर पूरा ध्यान दें, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त एक्शन हो। भू-माफिया के विरूद्ध कार्यवाही सख्त हो। अपराधियों की सम्पत्ति कुर्क करने में पीछे न रहें। संगठित अपराधियों पर निरंतर नजर रखी जाएं। मुखबिर तंत्र सशक्त रहना चाहिए।

राज्य में ई-चालान व्यवस्था और ई-साक्ष्य जैसे उपायों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आईटी के अधिकतम प्रयोग से अपराधों के नियंत्रण और जांच कार्य में आसानी लाएं जिससे कि मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी बने। प्रतिदिन ग्रामों से दूध ,सब्जी आदि लाने वाले किसानों को कृषक कल्याण वर्ष में जीवन रक्षा के लिए हेलमेट प्रदान किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग ऐसे अभिनव प्रयोग में सहयोगी बने और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए उपयोगी हेलमेट के इस्तेमाल के लिए नागरिकों को जागरूक करने का अभियान जारी रखे। पुलिसकर्मियों के लिए अपने आवास अर्थात आशियाने की व्यवस्था करने में गृह विभाग आवश्यक सहयोग दे। पुलिस लाइन्स में आवास गृहों की व्यवस्था और पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा नए आवास गृहों के निर्माण करवाने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं विकसित की जाएं, ताकि कम व्यय पर पुलिस जवानों को मकान उपलब्ध हो सके। विभाग के श्रेष्ठ कार्य करने वालों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाए। प्रदेश में नशा विरोधी अभियान निरंतर संचालित करें। युवाओं को हर हालत में नशे से बचाना है। सिंहस्थ 2028 में सुरक्षा उपकरणों के साथ ही पार्किंग, परिवहन और भीड़ प्रबंधन के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाएं।

प्रमुख उपलब्धियां और नवाचार-बैठक में गृह विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए श्रेष्ठ कार्यों की भी चर्चा हुई। प्रमुख उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी दी गई। सैनिक कल्याण के क्षेत्र मध्यप्रदेश के कार्य की रक्षा मंत्रालय द्वारा सराहना की गई। संपदा संचालनालय द्वारा शासकीय आवास गृह के ऑनलाइन आवंटन का कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता वर्धन के लिए निरंतरण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का प्रदेशवासियों से किया आह्वान

बच्चों के माथे पर बोझ अच्छा नहीं लगता

भोपाल (स्वतंत्र मत)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'विश्व बालश्रम निषेध दिवस' पर प्रदेशवासियों से बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि बच्चों के माथे पर बोझ अच्छा नहीं लगता, बच्चों के हाथों में कलम-किताब ही शोभा देते हैं। खुशहाल बचपन और शिक्षा उनका अधिकार है। हमारी सरकार बच्चों के हितों और शिक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से मां बेटे की मौत

दमोह (स्वतंत्र मत)। जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई जबकि 10 वर्षीय एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा झलौन-तेजगढ़ मार्ग पर बांसा पुरा गांव के पास हुआए जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान पुरा गांव निवासी 30 वर्षीय संतोष सेन और उनकी 60 वर्षीय मां संतोषी रानी के रूप में हुई है। घायल बच्ची मानवी 10 वर्ष का इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जानकारी के अनुसारए संतोष सेन अपनी मां का इलाज कराने और घरेलू सामान खरीदने के लिए भतीजी मानवी के साथ झलौन गांव गए थे। काम पूरा करने के बाद तीनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे।रात करीब 10 बजे बांसा पुरा गांव के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर के बाद तीनों सड़क पर घायल अवस्था में पड़े रहे। उन्होंने घायलों को देखा और तत्काल अपने वाहन से तेंदूखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रास्ते में मां और बेटे की हालत बिगड़ गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद संतोष सेन और संतोषी रानी को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस जनसंवाद को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

पुलिस द्वारा मोहल्ला समिति बैठक के माध्यम से जनसंवाद एवं समस्याओं का निराकरण किया गया

दमोह (स्वतंत्र मत)। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक दमोह आनंद कलादगि ;प्ब्द्ध के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फुटेरा वार्ड क्रमांक 4 नरसिंह मंदिर के पास मोहल्ला समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य आमजन से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुनना, अपराधों की रोकथाम हेतु जनसहभागिता बढ़ाना तथा पुलिस एवं नागरिकों के मध्य विश्वास को और सुदृढ़ करना रहा। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने नागरिकों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मोहल्ले में शिकायत पेटी स्थापित करवाई जिससे नागरिक अपनी शिकायतें एवं सुझाव आसानी से पुलिस तक पहुंचा सकें।पुलिस अधीक्षक महोदय ने वार्डवासियों से मोहल्ले की सुरक्षा में सक्रिय सहभागिता का आह्वान करते हुए प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, साथ ही मोहल्लों में एंट्री एवं एग्जिट गेट विकसित करने हेतु सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सहभागिता से अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी तथा सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण का निर्माण संभव है। बैठक में उपस्थित नागरिकों, महिलाओं एवं वरिष्ठजनों ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव पुलिस प्रशासन के समक्ष रखे। पुलिस अधीक्षक श्री कलादगी ने प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।आमजन की सुविधा एवं पुलिस से त्वरित संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने मोहल्लों में बीट प्रभारी एवं आरक्षकों के नाम तथा मोबाइल नंबरों की सूचना पट्टिका लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी की जानकारी होना चाहिए जिससे किसी भी आपात स्थितिए शिकायत अथवा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस तक पहुंचाई जा सके।

ब्यारमा नदी के नए पुल से आवागमन शुरू, लोगों में खुशी की लहर

हटा (स्वतंत्र मत)। दमोह और पन्ना जिलों को जोड़ने वाली ब्यारमा नदी पर निर्मित नए पुल से आवागमन शुरू होने के बाद क्षेत्र के लोगों में उत्साह और राहत का माहौल है। लंबे समय से आवागमन की परेशानी झेल रहे ग्रामीणों और राहगीरों ने पुल को चालू कराने के लिए सांसद राहुल सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त 2025 को भारी बारिश के दौरान तत्कालीन कलेक्टर सुधीर कोचर ने गैसाबाद-सिमरिया के बीच स्थित पुराने ब्यारमा पुल को क्षतिग्रस्त बताते हुए उस पर आवागमन बंद करा दिया था। इस निर्णय के बाद क्षेत्र के लोगों को सिमरिया, अमानगंज और पन्ना जाने के लिए लगभग 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी। हालांकि बाद में पुराने पुल की तकनीकी जांच भी कराई गई लेकिन उस पर यातायात दोबारा शुरू नहीं हो सका। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के बीच जनवरी माह में गैसाबाद गौशाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों ने सांसद राहुल सिंह को पुराने पुल के बंद होने तथा नए पुल के तैयार होने के बावजूद अप्रोच रोड नहीं बनने की समस्या से अवगत कराया। सांसद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दमोह और पन्ना के कलेक्टरों को समय सीमा में अप्रोच रोड निर्माण के निर्देश दिए तथा कार्य की लगातार समीक्षा की। सांसद के हस्तक्षेप के बाद एमपीआरडीसी अधिकारियों ने दमोह-सिमरिया मार्ग के ठेकेदार को नए पुल की अप्रोच रोड निर्माण का कार्य सौंपा।

लक्ष्मण कुटी धाम खजरी में गूंज रही रामचरितमानस की चौपाइयां

निरंतर चल रहा महाअखण्ड रामायण पाठ, भक्ति रस में डूबा क्षेत्र

दमोह (स्वतंत्र मत)। दमोह के लक्ष्मण कुटी क्षेत्र के सुप्रसिद्ध और आस्था के प्रमुख केंद्र श्री लक्ष्मण कुटी धाम खजरी में इन दिनों भक्ति की बयार बह रही है। धाम परिसर में पिछले वर्ष 25-26 अगस्त 2025 से शुरू हुआ महाअखण्ड रामायण पाठ बिना किसी विघ्न बाधा के निरंतर 24 घंटे जारी है। इस पावन आयोजन से संपूर्ण लक्ष्मण कुटी धाम और आस.पास का क्षेत्र पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। सुबह से लेकर देर रात तक मंदिर परिसर में गूंजती रामचरितमानस की चौपाइयों ने वातावरण को अलौकिक और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया है। गुरु दादा नागा शांति गिरी जी का मिला है। आशीर्वाद से धार्मिक आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि लक्ष्मण कुटी मंदिर के समीप ही स्थित भव्य श्री गणेश मंदिर में इस अखण्ड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस महान धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत भादो मास की पावन गणेश चतुर्थी के अवसर पर परम पूज्य गुरु दादा नागा शांति गिरी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से हुई थी। तब से लेकर आज तक, स्थानीय भक्तों और श्रद्धालुओं की टोली बिना रुके, बारी-बारी से चौबीसों घंटे इस पाठ को अनवरत चला रही है।लक्ष्मणकुटी धाम के मुख्य पुजारी ने इस अनुष्ठान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाअखण्ड रामायण के श्रवण और दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है। उन्होंने क्षेत्र के साथ.साथ दूरदराज से आने वाले सभी श्रद्धालुओं और आम जनमानस से भावपूर्ण अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस महापाठ में सम्मिलित हों। आरती व प्रसाद ग्रहण करें और इस पुण्यमयी आयोजन का हिस्सा बनकर धर्म लाभ अर्जित करें। इस ऐतिहासिक और दीर्घकालिक धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने में समस्त ग्रामवासी खजरी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ जुटे हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैठक, विश्राम और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं।

विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत विधायक मलैया ने प्रबुद्धजनों से भेंट कर किया संवाद

दमोह (स्वतंत्र मत)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के सेवा, सुशासन एवं गरीब उत्थान, विकसित भारत संकल्प के तहत चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत विधायक जयंत मलैया ने दमोह विधानसभा के अभाना मंडल में प्रबुद्धजनों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के सेवा, सुशासन एवं जन कल्याणकारी कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबुद्ध वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों डॉ. राम सिंह ठाकुर डॉ. प्रहलाद खरे, ठेकेदार चंदन सिंह दिव्यांग खिलाड़ी पंडा सर्पदंश विशेषज्ञ जेपी साहू सेवानिवृत्त शिक्षक प्रहलाद सिंह किसान चित्तर सेन हाथ पैर सुधार विशेषज्ञ एवं गंधर्व सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिकों से भेंट कर संवाद एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला मंत्री भरत यादव, मंडल अध्यक्ष दान सिंह लोधी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय लोधी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना अंतर्गत वैष्णो देवी जाएंगे श्रद्धालु

मंत्री सारंग ने लाभार्थियों को वितरित किए यात्रा टिकट

भोपाल (स्वतंत्र मत)।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना अंतर्गत नरेला विधानसभा क्षेत्र के श्रद्धालु 13 से 18 जून तक पवित्र वैष्णो देवी धाम की तीर्थ-यात्रा पर जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने लाभार्थियों को यात्रा टिकट वितरित कर उनकी सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों और श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देने वाली महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से उन्हें नि:शुल्क तीर्थ-यात्रा का अवसर प्राप्त हो रहा है।

श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान कर रही सरकार

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अनेक श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी इच्छा होती है कि वे देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करें, लेकिन आर्थिक अथवा अन्य कारणों से यह संभव नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना ऐसे श्रद्धालुओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बनी है।

13 से 18 जून तक होगी यात्रा

मंत्री श्री सारंग के निर्देशानुसार श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्रद्धालु 13 जून को वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना होंगे तथा 18 जून को वापस लौटेंगे। यात्रा के दौरान आवागमन, भोजन, ठहरने एवं सुरक्षा सहित संपूर्ण प्रबंध मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण कर सकें।

श्रद्धालुओं ने जताया आभार

टिकट वितरण के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण धार्मिक सपने को पूरा करने का अवसर प्रदान किया है। श्रद्धालुओं ने कहा कि यह योजना वरिष्ठ नागरिकों एवं आमजन के लिए अत्यंत लाभकारी और प्रेरणादायी है।

जनकल्याण और आस्था के संगम का उदाहरण

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है। प्रदेश सरकार आगे भी जनहित और लोककल्याण की योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

1200 पेटी अवैध शराब जब्त

दमोह (स्वतंत्र मत)। नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में दमोह जिले से जहां पर आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया जिसमें दमोह देहात थाना के अंतर्गत एक 12 चक्का ट्रक एमपी07एचबी5439 से अंग्रेजी ब्रांड की 1200 पेटी अवैध शराब जप्त कराई।

CHANGE OF NAME

I, WAS KNOWN AS **SHRESTH KHARE** I, HAVE CHANGED THE SPELLING OF MY FIRST NAME AND AND HENCE-FORTH I, SHALL BE KNOWN AS **SHRESHTH KHARE** S/O RAJENDRA KHARE RESIDENT OF - 56, ASHOK VIHAR, RAM-PUR, JABALPUR (M.P.) 482001.

दान पेटी से 95 लाख रुपये के आभूषण मिले

त्रिपुर सुंदरी मंदिर की चल-अचल संपत्ति का सत्यापन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। तेवर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर की चल एवं अचल संपत्तियों के सर्वेक्षणए सत्यापनए सूचीकरण एवं अभिलेखीकरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई । कार्यवाही के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षित रखी गई सीलबंद पेटी को खोलते हुए स्वर्णए रजत आभूषणों सहित अन्य सामग्री का भौतिक सत्यापन और सूचीकरण किया गया। पूरी प्रक्रिया समिति के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न कराई गई। सत्यापन में पेटी से लगभग 26.17 किलोग्राम चांदी तथा करीब 200 ग्राम स्वर्ण आभूषण एवं सामग्री प्राप्त हुई। इनका विस्तृत विवरण तैयार कर अभिलेखों में दर्ज किया गया तथा सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की कार्रवाई की गई।

जबलपुर से 19 जून और कोयंबटूर से 15 जून से बदलेगा समय

मानसून के चलते जबलपुर-कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। मानसून के मद्देनजर जबलपुर से प्रारंभ और टर्मिनेट होने वाली गाड़ी संख्या 02198/02197 जबलपुर-कोयंबटूर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी में कोंकण रेलवे के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्टेशनों पर आंशिक परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तित मानसून समय सारिणी जबलपुर से 19 जून प्रत्येक शुक्रवार और कोयंबटूर से 15 जून प्रत्येक सोमवार से प्रभावी होगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार, मानसून अवधि के दौरान यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, पनवेल एवं रोहा स्टेशनों पर अपने पुराने व निर्धारित समय पर ही चलेगी, यानी इन स्टेशनों के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत का दबदबा

जबलपुर की बेटियां रिया और दीपा ने जीते 3 गोल्ड

जबलपुर (स्वतंत्र मत)।

गुजरात के अहमदाबाद स्थित ट्रांसटेडिया स्टेडियम में आयोजित प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। योग की जन्मभूमि भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कुल 114 पदक अपने नाम किए , जिसमें रिकॉर्ड 102 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इस ऐतिहासिक महाकुंभ में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए देश की झोली में 9 स्वर्ण और 1 रजत पदक डाले। इसमें संस्कारधानी की होनहार बेटियों रिया और दीपा लोधी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व स्तर पर जीत का परचम लहराया है 4 से 8 जून तक आयोजित इस पांच दिवसीय ऐतिहासिक प्रतियोगिता में विश्व के 78 देशों के लगभग 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ियों ने भाग लिया था।

मील का पत्थर बनी यह चैंपियनशिप

सभी प्रतिभागियों ने योगासन की कला, संतुलन, शारीरिक शक्ति और लचीलेपन का अद्भुत प्रदर्शन किया। इस भव्य आयोजन का मुख्य उद्देश्य योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में नई पहचान देना रहा ।

यह वैश्विक आयोजन अध्यक्ष स्वामी रामदेव, डॉ. जयदीप आर्य और उदित सेठ के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसे योगासन के विस्तार में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रतियोगिता में एशियन योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. संजय मालपानी, उमंग डॉन, वेद प्रकाश शर्मा, दिनेश सिंह ठाकुर, राकेश नेमा, सचिन तिवारी, दीपक जैन, बरुन कुशवाहा और गीता प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया।

जबलपुर और प्रदेश के इन सितारों ने बढ़ाया मान

संस्कारधानी जबलपुर की रिया ने सूपाईन इवेंट में 1 गोल्ड और दीपा लोधी ने आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसके अतिरिक्त इंदौर के राज रजोले ने ट्रेडिशनल ग्रुप व बैकवर्ड बेंडिंग में 2 गोल्ड, आरती पाल ने ट्रेडिशनल इवेंट में 1 गोल्ड, सपना पाल ने ट्रेडिशनल ग्रुप में 1 गोल्ड, निशा चावड़ा ने सुपाइन में 1 गोल्ड और भावना पाल ने बैकवर्ड बेंडिंग में 1 रजत पदक जीतकर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। जबलपुर की रिया और दीपा लोधी की इस सफलता के पीछे कोच शिवम गुप्ता और देवेंद्र मिश्रा का अथक प्रयास व कड़ा प्रशिक्षण रहा। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर डॉ. प्रशांत मिश्रा, राज सोनकर, अशोक तोमर, संदीप वर्मा, संजू राजपूत ने शुभकामनाएं दी।

इलाके में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फेंके बम

सीसीटीवी में कैद हुए स्कूटी सवार 4 बदमाश

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। रांझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंजनी कॉलोनी (रिछाई) में देर रात अज्ञात बदमाशों द्वारा बमबाजी करने का मामला सामने आया । अज्ञात उपद्रवियों ने इलाके में दहशत फैलाने की नीयत से एक के बाद एक कई बम पटके, जिससे पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंजनी कॉलोनी रिछाई निवासी 52 वर्षीय संतोष कुमार भारती ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया की 11 जून की रात वह अपने घर में था तभी अचानक एक के बाद एक तीन बार जोरदार बम फटने की आवाजें आईं। धमाकों की आवाज सुनकर जब वह घबराकर घर के बाहर निकले, तो चारों तरफ धुएं का गुबार उठा हुआ था और हवा में बारूद की तीखी गंध फैली हुई थी। उसी दौरान धमाकों की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी अनिल राजपूत भी अपने घर से बाहर आ गए। दोनों ने जब आसपास मुआयना किया तो संतोष भारती के घर के सामने बम फटने के अवशेष, नायलॉन की रस्सी और बारूद बिखरा पड़ा था। इसके साथ ही, घर के दरवाजे में एक जिंदा बम भी मिला, जो कागज में लिपटा हुआ था और उसकी आधी रस्सी खुली हुई थी। वहीं, पड़ोसी अनिल राजपूत के घर के सामने भी दो फटे हुए बमों के अवशेष पड़े मिले। घटना के बाद जब पड़ोसी अनिल राजपूत के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, तो उसमें पूरी वारदात कैद मिली। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक सफेद रंग की स्कूटी पर सवार होकर 4 लड़के वहां पहुंचे और इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ बम पटककर मौके से फरार हो गए। रांझी थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया है।

होटल अर्क द कोर्टयार्ड पर लगा एक लाख रूपये का जुर्माना, रेस्टोरेन्ट सील

होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम, पर्याप्त वेंटीलेशन नहीं पाया गया

होटल के किचिन में मिली गंदगी

जबलपुर (स्वतंत्र मत) ।

अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम स्वास्थ्य, अग्नि शमन, बाजार, अतिक्रमण और भवन विभाग की टीम द्वारा बिलहरी मेन रोड स्थित होटल अर्क द कोर्टयार्ड का औचक निरीक्षण किया गया। सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही और गंदगी पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए होटल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और रेस्टोरेन्ट को सील किया। कार्यवाही के संबंध में उपायुक्त संभव अयाची ने बताया कि निरीक्षण के दौरान होटल में जन सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों की अनदेखी पाई गई।

फायर सेफ्टी और वेंटिलेशन का अभाव पाया गया और किचन में वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं पाई गयी। इसके साथ ही स्वीकृत नक्शे और क्षेत्र से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से रेस्टोरेंट एवं बार का संचालन किया जा रहा था, जिसके कारण रेस्टोरेन्ट को सील किया गया। इस राजेन्द्र पटैल, अभिनव मिश्रा, पोला राव, किशन दुबे, सचिन सहायक उपस्थित रहे।

किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने सरकार लायेगी नीति

अपेक्स बैंक के प्रशासक ने की संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के कामकाज की समीक्षा

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। सरकार जल्दी ही ऐसी नीति लेकर आ रही है। जिससे प्रदेश के किसान डिफाल्टर नहीं होंगे। यह जानकारी अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने शुक्रवार को जबलपुर प्रवास के दौरान संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के कामकाज की समीक्षा के लिये आयोजित बैठक में दी। यादव ने बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का नियमित भ्रमण करने तथा सदस्यता अभियान को गति प्रदान कर अधिक से अधिक किसानों समितियों का सदस्य बनाने के निर्देश दिये। अपैक्स बैंकए जिला बैंकों एवं पैक्स के माध्यम से छोटेए मझौले और बड़े किसानों को एक वर्ष की अवधि के लिये शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रूपये तक का ऋण प्रदान कर रही है। यह योजना किसानों को खादए बीजए उर्वरक एवं अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करेगी। इससे किसानों को निजी साहूकारों और महंगे ऋणों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगाए जिससे खेती की लागत काम करने में मदद मिलेगी। बैठक में राकेश पांडे आरसी पटले अभय प्रधान मौजूद थे।

उत्साह के साथ मना रादुविवि का 71वां स्थापना दिवस

जबलपुर (स्वतंत्र मत) ।

रादुविवि ने शुक्रवार को उत्साह और संकल्प के साथ अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि छात्र अपने ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के बल पर देश के विकास में सक्रिय योगदान दें। स्थापना दिवस की शुरुआत विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती और संस्थापक कुलपति पं. कुंजीलाल दुबे की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ हुई। स्थापना दिवस को केवल समारोह तक सीमित न रखकर इसे सामाजिक सरोकार से जोड़ा गया।

युवा कांग्रेस ने शुरू किया संविधान लीडरशिप प्रोग्राम

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और युवाओं को वैचारिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से देशभर में चलाए जा रहे संविधान लीडरशिप प्रोग्राम का शंखनाद अब जबलपुर में भी हो गया। युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सत्येंद्र (सोनू) कुकरेले ने बदलते परिवेश में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर जोर दिया। डिजिटल युग में सोशल मीडिया को लोकतंत्र के 'पांचवें स्तंभ' के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संविधान, सामाजिक समानता और जनता के हक की आवाज बुलंद करने वाले युवाओं की भारी जरूरत है। इस अभियान के तहत व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से एक समर्पित युवा टीम तैयार की जाएगी। यह टीम संविधान के प्रगतिशील विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेगी। युवा कांग्रेस ने शहर के छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध नागरिकों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए इच्छुक युवा जारी किए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस दौरान भानु यादव, अभ्युत बाजपेयी,शिशांत सिंह ठाकुर नितिन सिंह, सौरभ यादव, मोंटी वंशकार, शिवम अग्रवाल, प्रवीण चौधरी, शिवम यादव सदस्य शामिल थे।

रेलवे ओवरब्रिज से गिरकर युवक की मौत

सिहोरा (स्वतंत्र मत)।

खितौला थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में युवक की रेलवे ओवरब्रिज से गिरकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 12 निवासी 36 बर्षीय आकाश पारवानी सुबह टहलने के लिए घर से निकला था। टहलते हुए वह रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचा, जहां नीचे देखने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए।

सूचना पर पहुंची खितौला पुलिस के अनुसार गिरने से युवक के बाएं पैर में गंभीर चोट आई थी तथा मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करदी है।

108 करोड़ के आसामी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को बड़ा झटका

हाईकोर्ट ने खारिज की 60 दिन की जमानत अर्जी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित आरटीओ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी, करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जबलपुर हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी 60 दिनों की अस्थायी जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया। इस फैसले के बाद आरोपी पूर्व आरक्षक की जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिलहाल खत्म हो गई हैं। सौरभ शर्मा ने अपनी याचिका में मानवीय आधार का हवाला देते हुए कोर्ट से 60 दिन की मोहलत मांगी थी। उन्होंने दलील दी थी कि उनकी पत्नी दिव्या तिवारी डिविएटेड नेजल सेप्टम क्रॉनिक साइनसिस्टम जैसी नाक की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, जिसके इलाज के लिए डॉक्टरों ने फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी की सलाह दी है। याचिका में कहा गया था कि पत्नी के इस बड़े ऑपरेशन और दो छोटे बच्चों की देखभाल के लिए पति का घर पर होना बेहद जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपी के खिलाफ मौजूद पुख्ता सबूतों को देखते हुए इस दलील को स्वीकार नहीं किया। इससे पहले भी हाईकोर्ट और जिला अदालत सौरभ शर्मा की नियमित जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर चुकी हैं। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी के पास से बरामद 108 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति, 51 किलो सोना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े बेहद संवेदनशील साक्ष्यों का हवाला देते हुए उन्हें जेल में ही रखने का आदेश दिया था। सरकारी पक्ष ने भी जमानत का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि इतने बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी को बाहर भेजने से साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बढ़ सकती है। आखिरकार, कोर्ट ने अपराध की प्रकृति को गंभीर मानते हुए पूर्व आरक्षक को राहत देने से मना कर दिया।

संस्कारधानी को मिलेगी 'ऑक्सीजन' की सौगात

उमरिया पिपरिया की 20 एकड़ भूमि पर मियॉवाकी तकनीक से उगेगा 'नगर वन'

जबलपुर (स्वतंत्र मत)।

प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है। संस्कारधानी को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ नगर निगम इस वर्ष शहर में 11 लाख पौधे लगाने जा रहा है। जून माह से शुरू होने वाले इस महाभियान के तहत 1 साल के भीतर शहर की 175 एकड़ भूमि को चिन्हित कर विशाल 'ऑक्सीजन जोन' के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे शहर की वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) में अभूतपूर्व सुधार आएगा। इस वृहद पर्यावरण योजना को धरातल पर उतारने के लिए महापौर जगत बहादुर सिंह और निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने उमरिया पिपरिया में प्रथम चरण के लिए तय की गई 20 एकड़ भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया। इस भूमि पर एक भव्य 'नगर वन' विकसित किया जाएगा।

कम समय में तैयार होगा घना जंगल

महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जापानी 'मियॉवाकी पद्धति' से पौधे लगाए जाएंगे। इस तकनीक की खासियत यह है कि इसमें पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बेहद कम समय में एक सघन वन तैयार हो जाता है। इस 20 एकड़ के क्षेत्र में मियॉवाकी तकनीक से तैयार प्राकृतिक जंगल के साथ-साथ सुंदर तालाब, आकर्षक वॉकिंग ट्रैक और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए फलदार पौधे भी रोपे जाएंगे, जो पक्षियों का बसेरा बनेंगे। जबलपुर के नागरिकों के लिए यह नगर वन सेहत और सुकून की एक बड़ी सौगात साबित होगा।

पश्चिम मध्य रेल ने वसूला 16.82 करोड़ का जुर्माना

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। बिना टिकट और अनियमित तरीके से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों पर पमरे ने कार्रवाई की मई 2026 के महीने में चले विशेष टिकट जांच अभियान के दौरान रेलवे ने नियम तोड़ने वाले यात्रियों से कुल 16 करोड़ 82 लाख रुपये का भारी-भरकम राजस्व वसूला है। प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के निर्देशन में जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडलों में चलाए गए इस कड़े अभियान में बिना टिकट यात्रा और अनबुक्ड लगेज के कुल 2 लाख 7 हजार मामले पकड़े गए। रेलवे की यह कार्रवाई कितनी सख्त रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार का राजस्व पिछले वर्ष की समान अवधि 14.49 करोड़ के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक रहा।

हितकारिणी प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक- राम असरानी** द्वारा प्रेस काम्पलेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस, सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. **प्रबंध सम्पादक- सुबोध दुबे, सम्पादक- राजेन्द्र मिश्रा,** *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयनार्थ उत्तरदायी।
ई-मेल-smatjbp1@ gmail.com, फोन- 0761-2411414, 4032436 समस्त विवाद जबलपुर न्यायालयाधीन. पोस्टल रजि. नं. एसएसपी जबलपुर/13/2026-28, RNI No. 64561/96.